चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 21 मार्च–27 मार्च 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

रोहित-कन्हैया-ऋचा के ज़रिये सुगबुगा रहे हैं देश के शिक्षा परिसर!

बस कमी है एक जेपी की

प्रभात रंजन दीन

हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैया कुमार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऋचा सिंह के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह विश्वविद्यालयों में माहौल बना उसमें बदलाव की चैतन्य सुगबुगाहट तो दिखी, लेकिन उसके समग्र परिवर्तनकारी आंदोलन में तब्दील होने का स्वरूप बनता नहीं दिखा. साफ तौर पर यह एहसास हो रहा है कि देश के छात्रों के बीच रोहित, कन्हैया, ऋचा जैसे जुझारू छात्र नेता तो हैं लेकिन उन्हें बांधकर बृहत्तर लक्ष्य की तरफ ले चलने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे मार्गदर्शक राजनीतिक व्यक्तित्वों का अकाल है. आप पूरे परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो आपको यह कमी दिखेगी और चिंता में डालेगी. लोहिया और जयप्रकाश के नाम पर दुकानें बहुत सारे लोगों की भले ही चल रही हों, लेकिन ऐसे वास्तविक व्यक्तित्व की कमी देश शिद्दत से महसूस कर रहा है. रोहित, कन्हैया, ऋचा के प्रकरणों पर नेता, पत्रकार और मीडिया संगठनों ने अलग-अलग पत्ते फेंटे और छात्रों के चेहरों को बारूद बना कर अपने-अपने मतलब की बंदूकों में भर-भर कर धांय-धांय फायर किया और उसका खूब फायदा उठाया. यही नेता और मीडिया प्रतिष्ठान देश की राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक-व्यवस्था के परिवर्तन में असली बाधक हैं. परिवर्तन की सुगबुगाहटों पर यही तत्व पानी डालते हैं और छात्रों के साथ खड़े दिखने का छद्म भी भरते हैं.

आप गौर करें, रोहित वेमुला की आत्महत्या के उभरते प्रकरण को जेएनयू मसले ने और पुख्ता किया या उसे पंगु बनाया. रोहित वेमुला की आत्महत्या का मसला गरमाता और जेएनयू होता हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों तक पहुंचता, देशव्यापी शक्ल लेता, उसके पहले ही देशविरोधी और अफजलवादी नारे लगा कर उस आंदोलन की धार को किन तत्वों ने कुंद बनाया, किन तत्वों ने उसे पंगु बनाया और संगठित हो रहे छात्रों को दूर बिदकाया? इस असली सवाल का जवाब तलाशने में किसी की रुचि नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला प्रकरण से ही बात शुरू करते हैं. रोहित वेमुला पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के नाते पिछड़ा था या मातृपक्ष के नाते दलित था, बहस का विषय यह नहीं होना चाहिए था. रोहित जैसे शोध छात्रों का उत्पीड़न जो उसे आत्महत्या करने तक के लिए विवश कर दे, यह संवेदनशील विषय और कारण छात्रों के आंदोलन को समग्रता देने के लिए काफी था. लेकिन सारे राजनीतिक दल रोहित के मृत्यु-वरण पर अलग-अलग शामियाने टांग कर बैठ गए और पूरी धारा को एक खास वोटोन्मुखी राजनीतिक दिशा पकड़ाने में लग गए. ऐसा आंदोलन जो सामाजिक-अकादमिक शक्ल लेता और पूरे देश के छात्रों को सजग-सतर्क करता, गोलबंद करता, उसे नियोजित रूप से राजनीतिक-अंधकूप की तरफ दिग्भ्रमित किया गया. मीडिया ने भी इस आंदोलन के तीखे बनते तेवर को कुंद करने और भरमाने की पूरी कोशिश की, जिससे परिवर्तनकामी छात्र-शक्ति एकाग्र लक्ष्य-बेधी होने से वंचित रह गई. रोहित वेमुला की आत्महत्या, हत्या के उकसावे जैसा संज्ञेय अपराध है, लेकिन अपराध तय हो और उस पर आधारित आंदोलन केंद्रीकृत हो, उसके पहले ही उसमें सियासत का मट्ठा डाल दिया गया. जेएनयू प्रकरण में देशविरोधी और अफजलवादी नारेबाजी से कन्हैया कुमार को अलग कर देखें और उसकी बातें सुनें तो उसमें रोहित वेमुला इश्यू को जाग्रत करने की छटपटाहट दिखती है, लेकिन जिस नकारात्मक आबोहवा में कन्हैया का आकस्मिक प्रादुर्भाव हुआ, उसने कन्हैया की छटपटाहट को खास फ्रेम में कस दिया. 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की आत्महत्या से उछला सवाल, सवाल ही बन कर रह गया. सारे राजनीतिक दल, सारा मीडिया समूह और सारा बुद्धिजीवीनुमा समूह राष्ट्रविरोध को उचित ठहराने या अनुचित ठहराने की प्रतिद्वंद्वी पतंगें उड़ाने में लगा रहा और पूरा मसला कटी पतंग की तरह भक्क-काटा हो गया. रोहित की नेट फेलोशिप रोके रखने, छात्रावास से निकाल बाहर करने और इससे विवश होकर उसके आत्महत्या कर लेने का मसला धार पकड़े उसके पहले ही उसका घंटाधार करने की तिकड़में रच दी गईं. आप कहीं यह सुन रहे हैं कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में पिछले एक दशक में नौ दलित छात्र आत्महत्या कर चुके हैं या पूरे देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में इस दरम्यान करीब 18 दलित छात्रों ने आत्महत्या की! यह बात कहां और क्यों हवा हो गई! कभी सोचा आपने! राजनीतिक स्वार्थों को ताक पर रख कर कोई जेपी या लोहिया सरीखा व्यक्तित्व रोहित या कन्हैया जैसे छात्रों को मार्गदर्शन देता तो ये सवाल अनुत्तरित नहीं रहते. इनका जवाब भी मिलता और ऐसे सवालों के भविष्य में पैदा होने की संभावनाओं पर भी कारगर कुल्हाड़ी चलती. राजनीतिक दलों की पशुवृत्ति के कारण ही फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रकरण में छात्रों का गैरपरिणामी इस्तेमाल हुआ और राजनीतिक रोटियां सेंक ली गईं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विजिटिंग प्रोफेसर गांधीवादी संदीप पांडेय को नक्सलवादी बता कर निष्कासित कर दिया गया और कोई चूं भी नहीं बोल पाया. सिद्धार्थ वरदराजन जैसे वरिष्ठ पत्रकार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भाषण नहीं होने दिया गया. किसी बुद्धिजीवी की खाल पर इसका असर भी नहीं पड़ा. इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, लेकिन छात्र-जगत चुप रहा! ऋचा सिंह का एडमिशन गलत साबित कर उन्हें विश्वविद्यालय से निकालने और छात्र संघ के अध्यक्ष पद से हटाने के संस्थानिक षडयंत्रों के खिलाफ छात्रों की बोलती बंद है! ऋचा सिंह का कसूर यह है कि विवादास्पद ओएसडी की नियुक्ति का उन्होंने विरोध किया था. ऋचा सिंह का अपराध यह है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का विरोध किया था. ऋचा सिंह और उनकी कुछ मित्रों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सामने पिछले ही साल 20 नवम्बर को बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन यह घटना आज तक दबी रही. क्यों दबी रही? यह मामला तब क्यों खुला जब रोहित वेमुला की आत्महत्या हो गई और कन्हैया गिरफ्तार होकर जेल चला गया? जिस विश्वविद्यालय में 90 साल बाद कोई महिला छात्र संघ अध्यक्ष चुनी जाती हो, उस पर गर्व करने के बजाय उसे अपमानित किए जाने पर छाया कायराना मौन छात्र-शक्ति के बिखराव की क्रूर सनद देता है. यह उस विश्वविद्यालय का हाल है जो कभी चंद्रशेखर आजाद से लेकर समाजवादी चंद्रशेखर और प्रगतिशील विश्वनाथ प्रताप सिंह तक की प्रेरणा-पीठ रहा. आज इन विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन राजनीतिक दलों का हित साधने के लिए उपकरण मात्र बन कर रह गए हैं.

यह विचित्र संयोग ही है कि कभी पूरे देश में राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन का जोरदार आंदोलन सृजित करने वाले संघर्ष-केंद्र पटना विश्वविद्यालय के छात्र आज चुप हैं, लेकिन उसी पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता लालू यादव रोहित या कन्हैया प्रकरण पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

छात्र आंदोलन से सत्ता तक पहुंचे लोगों ने ही छात्र राजनीति की हत्या कर दी : संतोष भारतीय

जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे और आपातकाल में जेल की सजा काट चुके वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय कहते हैं कि गांधी के बाद जेपी ने ही 1974 आंदोलन के रूप में देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया था. उन्होंने छात्रों में आंदोलन की प्रेरणा जगाई थी और यह भी शिक्षा दी थी कि समाज में कैसे सम्पूर्ण बदलाव लाया जा सकता है. आज की राजनीति से लोग घृणा करने लगे हैं. 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले से सरकार बदल गई थी जबकि आज लाखों करोड़ का घोटाला होने के बाद भी कुछ नहीं होता. जनता में निराशा का भाव है. इसलिए देश के आमजन समेत युवाओं को जागना होगा. तभी देश की तस्वीर बदल सकती है. संतोष भारतीय आजादी के बाद के काल को दो खंडों में बांटते हैं. कहते हैं कि 1975 के पहले देश के विश्वविद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया की परम्परा थी. इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों तक समितियां गठित होती थीं और उनमें बाकायदा सचिव समेत अन्य पदाधिकारी चुने जाते थे. पूरी प्रक्रिया में छात्र संगठनों की बाकायदा हिस्सेदारी होती थी. विभिन्न राजनीतिक दलों से विचारधारात्मक रूप से संलग्न छात्र संगठनों के वैचारिक शिविर लगते थे. कॉलेजों में छात्रों की ही कमेटी बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरह प्रत्याशी तय करती थी और चुनाव हुआ करता था. पूरी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली का छोटा प्रतिरूप विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में दिखाई पड़ता था. आजादी के बाद से लगातार विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक-वैचारिक निर्माण के बाद प्रगाढ़ हुए विचारधारात्मक लगाव के कारण ही छात्रों ने देश में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ आंदोलन का रास्ता चुना था और इसी वजह से जेपी ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया था. उसी आंदोलन के फलस्वरूप छात्र नेताओं को 1977 में सत्ता हासिल हुई लेकिन उन्हीं लोगों ने देश की मौलिक लोकतांत्रिक छात्र राजनीति की हत्या कर दी. इस तरह 1977 के बाद का कालखंड पूरी तरह बदल जाता है. जिन छात्र नेताओं ने छात्र आंदोलन के बूते सत्ता हासिल की, उन्हीं छात्र नेताओं ने छात्र राजनीति का सत्यानाश कर दिया. दरअसल जेपी भी इसी वजह से नाराज हुए थे और अंत तक नाराज ही रहे. छात्र आंदोलन के जरिए सत्ता तक पहुंची जमात को छात्र समुदाय से ही खतरा महसूस हुआ। कॉरपोरेट और बाजारवादियों को भी छात्र आंदोलन से ही डर था, लिहाजा वे सब एक हो गए और बड़े ही नियोजित तरीके से शिक्षा परिसरों में छात्र राजनीति में सक्रिय छात्र नेताओं को पहले तो जातीय समूहों में बांटा, भौतिक स्वार्थों और सुविधाओं की लत लगाई और विरोधाभासों को हवा देकर छात्र संगठनों के चुनावों पर रोक लगा दी. राजसत्ता ने छात्र नेताओं को प्रलोभनों में फंसाया और विदेशों की चकाचौंध से परिचित करा कर उनका ध्यान भटकाया. इन सब वजहों से छात्र आंदोलन पूरी तरह भटक गया और कुंद हो गया.

जेएनयू प्रकरण को संतोष भारतीय छात्र आंदोलन नहीं मानते, वे कहते हैं कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या का प्रकरण एक बड़ा संवेदनशील मसला है, लेकिन जेएनयू प्रकरण वैचारिक स्वतंत्रता की लंबी परम्परा में उच्छृंखल होकर अभिव्यक्ति की मर्यादा भूल जाने का महज परिणाम भर है. इसीलिए न तो इसे राजनीतिक दलों को अधिक तूल देना चाहिए था और न मीडिया को। हां, रोहित वेमुला का मसला एक व्यापक आंदोलन की शक्ल ले सकता था। इसने छात्रों के बीच थोड़ी सुगबुगाहट पैदा भी की थी, लेकिन इसमें कॉरपोरेट-बाजारवादी अवसरवाद से वंचित निराश तत्वों के कूद पड़ने से, यह व्यापक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले सका और कुछ स्थानों पर टिमटिमा कर रह गया... ■

उत्तर प्रदेश : चन्द से रह गई पूर्ण खुशी | P-5

आपदा , आंदोलन और अर्थव्यवस्था | P-6

इरोम शर्मिला : कब ख़त्म होगा रिहाई-गिरफ्तारी का सिलसिला | P-7

बस कमी है एक जेपी की

पृष्ठ 1 का शेष

काफी मुखर हैं. उसी पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी मुखर हैं. लालू नीतीश और उनके जैसे कई नेता 74 आंदोलन के ही उत्पाद हैं, जिस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और सत्ता केंद्र की चूलें हिला दी थीं. पर आज कोई जेपी जैसा नहीं है. जेपी आंदोलन के सियासी प्रतिउत्पादों में भी उस व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सका, जो आज की युवा-सुगबुगाहट को व्यवस्था परिवर्तन के व्यापक आंदोलन में परिवर्तित कर सके. सारे नेताओं के अपने-अपने स्वार्थ के घेरे हैं, जिसकी वजह से व्यापक संभावनाएं खंडित होकर बिखर जाती हैं. ये स्वार्थ भारतीय लोकतंत्र पर इस कदर हावी हैं कि जिन शक्तियों ने जेपी आंदोलन के खिलाफ षडयंत्र किया, जिन शक्तियों ने जेपी आंदोलन को कुचलने और बिखेरने के सारे उपक्रम किए, जिन शक्तियों ने जेपी को जेल में ठूंस कर नियोजित रोगी बना कर अशक्त बना दिया, जिन शक्तियों ने जेपी आंदोलन के वृक्ष पर सवार होकर उसकी शाखाएं काटने की हरकतें कीं, वही शक्तियां आज रोहित-कन्हैया मसले पर जोर-जोर से रुदालियां गा रही हैं और व्यवस्था के व्यापक परिवर्तन की लड़ाई को गति देने के बजाय उसे वोट के संकुचन में ही घेरे रखना का कुचक्र कर रही हैं.

आज देश के किसी भी विश्वविद्यालय में कोई छात्रसंघ, स्थानीय (विश्वविद्यालयीय) स्तर पर भी दबाव बनाने लायक नहीं बचा है. इसके लिए राजनीतिक दल ही दोषी हैं, जिन्होंने सत्ता में आते ही छात्र संघों के चुनाव प्रतिबंधित किए. राजनीतिक दलों को हमेशा से यह डर सताता रहा है कि छात्र एकीकृत हुए तो व्यवस्था हिल जाएगी. राजनीतिक दलों में यह डर 74 आंदोलन के बाद अधिक गहरा गया है. वैसे आजादी के आंदोलन के बाद जितने भी निर्णायक आंदोलन हुए वे सब छात्रों और युवकों की भागीदारी के कारण नतीजाजनक बने. 1960 के दशक का पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघजनित बिहार आंदोलन, 1969 का तेलंगाना आंदोलन, 1974-75 का जेपी आंदोलन और 1981 का असम आंदोलन छात्र-शक्ति के कारण ही कामयाब हो पाया. लेकिन आज पूरे देश की छात्र-शक्ति में राजनीतिक पार्टियों का घुन लग गया है. 60 से लेकर 80 के बीच का दो दशक जुझारू छात्र आंदोलनों के रूप में जाना जाता है. लेकिन आपातकाल के बाद सारे राजनीतिक दलों ने मिल बैठ कर छात्रों की आंदोलनकारी भूमिका का राजनीतिक दखलंदाजी के बतौर अर्थायन किया और छात्र-शक्ति को हतोत्साहित और नपुंसक करने की सिलसिलेवार साजिशें रचीं. इसमें वह पार्टी भी शामिल थी जिसने आपातकाल लागू किया था और वह भी जो उसकी गोद में जाकर बैठ गई थी और वह भी जिसने जेपी आंदोलन के फलस्वरूप सत्ता हासिल की थी. उसके बाद बड़े ही नियोजित तरीके से युवकों को जाति और धर्म में विभाजित किया गया.

ऋचा सिंह : इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष.

यादवपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्र.

सत्ताधारी दलों ने अपने-अपने कब्जे वाले राज्यों में विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों को प्रतिबंधित किया. लिंगदोह समिति ने बाकी की कसर पूरी कर दी. विश्वविद्यालयों के अ-राजनीतिकरण के नाम पर छात्र संघों का चुनाव प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन छात्रों को राजनीतिक मुहरा बना कर रखने का बद-चलन बदस्तूर जारी रहा. इसी बीच असम छात्र आंदोलन के जरिए देशभर में एक सुगबुगाहट फिर से पैदा हुई, लेकिन कड़े संघर्ष के बाद असम में सत्ता हासिल करने वाला ऑल असम स्टूडेंट यूनियन लोगों का दीर्घजीवी-भरोसा कायम रखने में कामयाब नहीं हो पाया. छात्र आंदोलनों पर समीक्षात्मक नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि देश के युवाओं पर सबसे अधिक डॉ. राम मनोहर लोहिया के आंदोलन और बाद में जेपी आंदोलन ने व्यापक प्रभाव डाला है. राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, दिग्विजय सिंह (बिहार वाले), वशिष्ठ नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह जैसे समाजवादी नेताओं की पूरी पीढ़ी जेपी आंदोलन की ही फसल है. भाजपा के सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, सुषमा स्वराज, विजय गोयल जेपी आंदोलन या छात्रसंघ से पैदा हुए नेता हैं. कांग्रेस के सीपी जोशी, अजय माकन, भाकपा के डी. राजा, माकपा के प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वगैरह सब छात्रसंघ की ही उपज हैं. जेपी आंदोलन ने न सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही का कारगर प्रतिकार किया था बल्कि सारे दलों को एकीकृत कर कांग्रेस का एकाधिकार भी खत्म किया था. लेकिन सत्ता के प्रलोभन में सारे दल मेढकीय समूह साबित हुए और संपूर्ण क्रांति का नारा पूर्ण रूप से टांय टांय फिस्स हो गया.

आप देशभर के विश्वविद्यालयों पर निगाह डालें, सभी जगह छात्र संगठन छोटे-छोटे स्वार्थों को पूरा करने में लगे हैं. ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक पार्टियां. राजनीतिक पार्टियां छात्रों को भौतिक सुविधाओं की अफीम चटा-चटा कर मत्त कर रही हैं. कोई छात्र नेता ठेकेदार बन गया तो कोई बिल्डर. कोई जमीन कब्जे करा रहा है तो कोई मकान. कोई छात्र नेता विधान परिषद में नॉमिनेशन का आश्वासन पाकर मस्त है तो कोई राज्यसभा का. किसी को सरकारी उपक्रम का चेयरमैन बना कर लालबत्ती दे दी तो किसी को सत्ता-शक्ति की फूंक मार दी. सब ऐंठे-ऐंठे घूम रहे हैं और पावन छात्र-शक्ति को पतित बना रहे हैं. बीएचयू कैंपस कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अखाड़ा हुआ करता था, अब संकीर्ण राजनीति का अड्डा बन गया है. छात्रसंघ राजनीतिक दलों की इकाइयों, या कहें उपकरणों के बतौर काम कर रहे हैं. जाति, धर्म और क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों पर छात्र राजनीति उसी तरह चल रही है जिस तरह राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीएचयू हो या एएमयू, पटना विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय, सब जगह के छात्रसंघ जाति और धर्म से जुड़े राजनीतिक मसले कंधों पर उठाए घूम रहे हैं. उस्मानिया यूनिवर्सिटीज के फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज (एफपीयू) का मंतव्य है कि नेताओं को शिक्षा के कैंपस से दूर रहना चाहिए. एफपीयू ने विश्वविद्यालय परिसरों के राजनीतिकरण की निंदा की है. तमाम बौद्धिक संस्थानों और बुद्धिजीवियों का भी मत रहा है कि शिक्षा परिसर राजनीति का प्रयोगस्थल न बनें. शिक्षा परिसरों को तार्किक-अकादमिक बहस के केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहिए और छात्रसंघ को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद देनी चाहिए. लेकिन हुआ है उसका ठीक उल्टा. राजनीतिक दलों ने शिक्षा परिसरों को राजनीति का एनाटॉमी डिपार्टमेंट बना कर रख दिया है.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 03
21 मार्च-27 मार्च 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्ट्रीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चुनाव के पहले की पेशबंदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा से एक कदम आगे चलती दिखीं. चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर नौकरशाहों का स्थानांतरण यह सुनिश्चित करते हुए किया कि सही बाबू की नियुक्ति सही जगह हो और वे बाबू अलग हो जाएं जिनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है. उन्होंने दिल्ली से तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर लौटे 12 युवा आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की. सामान्यतः ऐसे अधिकारियों की सब डिविजनल ऑफिसर(एसडीओ) के रूप में नियुक्ति होती है. इसके बाद वे अपने-अपने सब-डिवीजन की जिम्मेदारी संभालते हैं. ये अधिकारी कुछ अलग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके बारे में अलग नजरिया अपनाया. आधिकारिक तौर पर जो बयान इन अधिकारियों के संबंध में दिया गया उसमें कहा गया कि फिलहाल इनके पास चुनाव आयोजित कराने का किसी तरह का अनुभव नहीं है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन लोगों की पदस्थापना को लेकर आशंकित थीं उन्हें शंका थी कि मोदी सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान इन सभी का ब्रेनवाश कर दिया गया होगा. चांस न लेते हुए उन्होंने इन सभी की पोस्टिंग ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी(ओएसडी) के रूप में बिना किसी स्पष्ट भूमिका के कर दी है. क्योंकि ओएसडी रिटर्निंग ऑफीसर नहीं बन सकते हैं इसलिए लगता है कि सरकार ने बिलकुल सही चाल चली है. हालांकि अब अधिकारियों को अपने कार्यकाल के कुछ महीने बेकार जाने की आशंका है अन्यथा एसडीओ के रूप में उनकी नियुक्ति एक दो साल में पूरी हो गई होती. लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों के अतिरिक्त सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है.■

दंतहीन संस्था कर रही जांच

राज्य के नौकरशाहों के खिलाफ शिकायतों की जांच गुजरात सतर्कता आयोग (जीवीसी) फिलहाल सतर्कता आयुक्त के बगैर कर रहा है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के तनेजा लोकायुक्त का कार्यभार संभाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि पारंपरिक रूप से जीवीसी कार्यालय असंतुष्ट नौकरशाहों के लिए शरण स्थली रहा है. व्यापक पैमाने पर यह एक दंतहीन संस्था है जिसके पास केवल अनुशंसात्मक अधिकार हैं. अधिकांश मामलों में उसकी अनुशंसाएं भी महज कागजों तक सीमित रह जाती हैं. अभी भी कम से कम चार सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस उच्च पद पर काबिज होने की दौड़ में शामिल हैं. हरिभाई पटेल, एच के दश, राजेश किशोर और एस के नंदा ने आधिकारिक रूप से इस पद के लिए आवेदन किया है. सूत्रों का कहना है कि नंदा सभी आवेदकों में वरिष्ठ हैं जो कि पिछले महीने ही गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नजदीकी होने की वजह से पूर्व में उन्हें राज्य का मुख्य सचिव नहीं बनाया गया था. लेकिन इस बार उन्हें आशा है कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. अब देखना है कि इस मामले में अंतिम फैसला राज्य का गृह विभाग करता है या नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर होती है. ■

तबादले के बूते सियासत

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही खींचातनी अब कोई राज नहीं रह गई है जिसे नौकरशाही के बल पर कार्यान्वित किया जा रहा है. इस बार वाकया दो दर्जन से अधिक नौकरशाहों के स्थानांतरण का है. केंद्र सरकार ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बार केंद्र ने जिन अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं उनमें ऊर्जा विभाग की प्रमुख सचिव शकुंतला गैमलिन शामिल हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. गृह सचिव एस एन सहाय को गोवा स्थानांतरित किया गया है. ट्रांसफर किए गए बाबुओं में गैमलिन और सहाय सहित जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनमें से अधिकांश का आप सरकार के साथ टकराव हुआ था. उप-राज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल की इच्छा के विपरीत गैमलिन को अस्थाई रुप से दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया था. सहाय भी अपने नीचे कार्यरत दो विशेष सचिवों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने से खुश नहीं थे. इसमें किसी तरह का आश्चर्य नहीं है कि अनिंदो मजूमदार जिन्होंने नजीब जंग के निर्देशानुसार गैमलिन से संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य सचिव बना दिया गया है. संभवतः इस प्रक्रिया से स्थानांतरित नौकरशाह और दिल्ली सरकार दोनों ही खुश हैं. ■

बस कमी है एक जेपी की

पृष्ठ 2 का शेष

सब सत्ता पाने के हथकंडे हैं : राजनाथ शर्मा

लोहियावादी चिंतक राजनाथ शर्मा की राय अलग है. शर्मा कहते हैं कि राष्ट्रविरोधी नारों की बुनियाद पर कोई आंदोलन मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता. डॉ. राम मनोहर लोहिया के साथ रहे वरिष्ठ समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा कहते हैं कि जेएनयू में हुई राष्ट्र विरोधी घटना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वामपंथियों का चरित्र हमेशा से संदेहास्पद रहा है. चाहे रूस के साथ, चाहे चीन से युद्ध के समय और चाहे आपातकाल का लगना हो. सभी स्थितियों में वामपंथियों के बारे में बहुत ही सटीक टिप्पणी डॉ. राममनोहर लोहिया ने की थी कि कम्युनिस्टी कीड़ा कांग्रेसी कुड़े पर पलता है, कूड़ा साफ तो कीड़ा साफ. वामपंथी किसी भी राष्ट्रद्रोही गतिविधि मे लिप्त होकर उसे प्रगतिशील रूप देने का प्रयास करते हैं. इस देश में गांधी जी केविचारों, उनकी बातों का पालन न करके कांग्रेस को पुनर्जीवित रखा और सत्ता के लालच में डूबे एक परिवार जिसके चलते इस देश में लगभग सौ जगहों पर गोलियां चलाकर नरसंहार किया गया, जिसमें बस्तर के सैकड़ों आदिवासियों को गोली का शिकार बनाया गया. आपातकाल लगाकर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तथा लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया गया. लाखों लोग जेल गए. कई हजार लोगों के परिजन बीमारी और भुखमरी के शिकार हुए. मुझको भी जेल में ठूंस दिया गया, फाकाकशी की हालत में मेरी पत्नी जो बीमार हुईं आज तक टीबी से रोगग्रस्त हैं. जेपी आंदोलन के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता पर काबिज होने के लिए भिन्डरांवाला जैसे लोग तैयार किए गए जिसके चलते पुनः सत्ता में आने के लिए पवित्र अम्रतसर पर हमला हुआ और भारी नरसंहार हुआ. दिल्ली में सुनियोजित ढंग से सिखों को जलाया गया और हत्याएं की गई. दोगलेपन का प्रमाण देने वाली लिट्टे नीति बनाई. जिस परिवार ने सत्ता के लिए भारत का विभाजन कराया. जिसमें करीब चौदह लाख लोगों की मौत हुई. वही परिवार पुनः सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय लोकतंत्र की पवित्र संस्था संसद भवन पर हमला करने वाले अफजल गुरु की फांसी और देश को तोड़ने वाले राष्ट्रविरोधी तत्वों से मिलकर सत्ता पर वापस आने की बेचैनी में लिप्त है. न इन्हें देश की नैतिकता, देशभक्ति और न ही सहिष्णुता की चिंता है. इन्हें सत्ता की बेचैनी है, जो देश की जनता को गुमराह कर रही है. लोहियावादी राजनाथ शर्मा कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि हिटलर को कम्युनिस्टों ने पैदा किया. पहले विश्वयुद्ध के बाद वर्साय की संधि में ब्रिटेन और फ्रांस ने पराजित जर्मनी को बुरी तरह अपमानित किया था. जर्मनी केआहत राष्ट्रीय स्वाभिमान को कॉमरेड पहचान नहीं पाए. वह जर्मनी के जन आक्रोश को पकड़ नहीं पाए. वह भूल गए कि मजदूरों को रोटी तो चाहिए लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत पर नहीं. हिटलर ने इसका फायदा उठाया. कम्युनिस्टों ने जो गलती जर्मनी में की, वही गलती वे अब जेएनयू में दोहरा रहे हैं. भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी- जैसे नारे कम्युनिस्टों की ताबूत की आखिरी कील बनेंगे. देखते रहिए. ■

भारत से नहीं, भारत में आज़ादी चाहिए : कन्हैया

जमानत पर छूटने के बाद जेएनयू पहुंचे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने परिसर में जो भाषण दिया, उसकी खूब चर्चा रही. प्रस्तुत हैं भाषण के प्रमुख और प्रासंगिक अंश...

■ इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है. इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है. हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होकर रहेगा.हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर. हम पूरे तरीके से खड़े होते हैं अपने संविधान की उन तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कही गई हैं, समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता-समानता.

■ किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है. खासकर विद्यार्थी परिषद के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं है. पूछिए क्यों? वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो विद्यार्थी परिषद है वो दरअसल बाहर के विद्यार्थी परिषद से ज्यादा बेहतर है और मैं कहना चाहता हूं वो सारे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं तो एक बार पिछले अध्यक्ष पद चुनाव में जो हालत हुई है विद्यार्थी परिषद उम्मीदवार की, उसका वीडियो देख लीजिए. जो जेएनयू का विद्यार्थी परिषद है उसको जब हमने पानी-पानी कर दिया तो बाकी देश में क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए. इसीलिए विद्यार्थी परिषद के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं. हम लोग सचमुच संविधान में भरोसा करते हैं इसीलिए विद्यार्थी परिषद को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं और लोकतंत्र में भरोसा करते हैं.

■ आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ता था, सिस्टम को झेलता कम था. इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है. पहली बात ये है कि जो प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है. सिर्फ एक बात कहनी है कि इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है, जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है, वो इशारों ही इशारों में समझ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं. जो मामला न्यायालय में है उस पर मुझे कुछ कहना है.

■ प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते. मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे भारी वैचारिक मतभेद है लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, संविधान का है. मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते. और सत्य की ही जय होगी.

■ ये मत समझिएगा कि कुछ छात्रों के ऊपर एक राजनीतिक हथियार की तरह देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है. इसको ऐसे समझिएगा कि मैंने ये बात अक्सर बोली है अपने भाषणों में, हम लोग गांव से आते हैं, मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं तो हमारे हर रेलवे स्टेशन पर जिसको देशन कहा जाता है वहां पर जादू का खेल होता है. जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूरा कर देगी ऐसा जादूगर कहता है. इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं वो कहते हैं काला धन आएगा. हर-हर मोदी, महंगाई कम होगी. बहुत हो गई मत सहिए, अबकी बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास, वो सारे जुमले आज लोगों के जेहन में हैं. हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए और ये जुमलेबाज जो कर रहे हैं और इसको कैसे भुलाया जाए तो ऐसा करो इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो. लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए, फिर करेंगे कि अच्छा ठीक है जो 5 हजार और 8 हजार देता था वही जारी रहेगा. मतलब बढ़ाने का मामला गया. बोलेगा कौन? जेएनयू. तो जब आपको गालियां पड़ रही हैं चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग. इस देश में जो जनविरोधी सरकार है उस जनविरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका सायबर सेल क्या करेगा? वो छेड़छाड़ वाला वीडियो भेजेगा. वो आपको गालियां भेजेगा और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितने कंडोम हैं? लेकिन ये बहुत गंभीर समय है इसीलिए इस गंभीर समय में हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है.

■ जेएनयू पर हमला एक नियोजित हमला है इस बात को आप समझिए और ये नियोजित हमला इसलिए है कि

आप यूजीसी से जुड़े आंदोलन को दबाना चाहते हैं. ये नियोजित हमला इसलिए है कि रोहित वेमुला केइसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को वे खत्म करना चाहते हैं. इस देश की सत्ता ने जब-जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम बार-बार ये याद करा रहे हैं कि तुम हमारी लड़ाई को खत्म नहीं कर सकते.

■ क्या कह रहे हैं? एक तरफ देश की सीमाओं पर नौजवान मर रहे हैं. मैं सलाम करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पर मर रहे हैं. मेरा एक सवाल है. जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब की पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए. इसलिए मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा. भाजपा के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पर मर रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है? या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए, जो उस नौजवान के पिता भी हैं उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो इस देश के शहीद हैं कि नहीं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है और तुम देश के अंदर एक झूठी बहस मत खड़ी करो. जो देश के लिए मरता है वो देश केअंदर भी मरते हैं, देश की सीमा पर भी मरते हैं. हमारा सवाल है कि तुम संसद में खड़े होकर किसके खिलाफ रजनीति कर रहे हो? वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं, लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं.

■ देश के अंदर जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? ये क्या कहते हैं किससे आजादी मांग रहे हो? तुम्हीं बता दो कि क्या भारत ने क्या किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो सही में भारत से नहीं मांग रहे हैं. भारत से नहीं मेरे भाईयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं. से और में, में फर्क होता है.

■ विज्ञान में कहा गया है कि जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा. लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है. क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है, वैज्ञानिक होना दूर की बात है. तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भुखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, वो आजादी हम लेकर रहेंगे, और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे. इसी मुल्क में ये हमारा सपना है. यही बाबा साहब का सपना था. यही साथी रोहित का सपना है.

■ आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय बोलना पड़ेगा ना? क्या पता किसको छेड़छाड़ करके फिर से फेंसा दिया जाए. तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और ख्रुश्चेव की बात कर रहे थे. मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं मोदीजी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए. छोड़ दीजिए हिटलर की. मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं. जिससे आपके गुरु जी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था.

■ दो स्तर पर लड़ाई रहेगी. पहली जो जेएनयू छात्र संघ का अपना एजेंडा है हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है उस आरोप के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे और इस बात को झंडेवालान या नागपुर में नहीं तय करेंगे, विद्रोही भवन में तय करेंगे, अपने जेएनयू छात्र संघ के दफ्तर में तय करेंगे, अपने संविधान से तय करेंगे जो हमको लड़ने का अधिकार देता है. अपनी संविधान सम्मत लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और तमाम टीचर, तमाम वो लोग हमारे साथी, जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है और जो लोग जेल में हैं उमर और अनिर्बान उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे. अदालत तय करेगी कि क्या देशद्रोह है और क्या देशभक्ति है. ■

जेपी के चेलों ने ही दे दी आदर्शों की तिलांजलि : सुरेंद्र किशोर

जेपी आंदोलन के साक्षी रहे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि आज बिहार विधानसभा में उन नेताओं और संगठनों के सदस्यों की संख्या खासी है जो जेपी आंदोलन के सहभागी थे. भाजपा, जदयू और राजद के प्रमुख नेतागण 1974-76 के जेपी आंदोलन के स्तम्भ थे. उन्होंने तब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशिक्षा के खिलाफ हजारों बार सड़कों पर नारे लगाए. जेल गए, कष्ट सहे और लाठियां खाईं. पर आज इन समस्याओं की स्थिति क्या है? स्थितियां बदतर ही हुई हैं. जेपी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इस बीच केंद्र और राज्यों में शासन चलाए. बिहार में तो 1990 से लगातार वही लोग सत्ता में हैं. लोग अक्सर पूछते हैं कि जेपी के चेलों ने सत्ता में आने के बाद उन चार प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए कितनी कोशिश की? जेपी के अनुयायी सत्ता के नशे में न सिर्फ जेपी को भूल गए, बल्कि उन्होंने जेपी आंदोलन के आदर्शों को भी तिलांजलि दे दी. कुछ ने मंडल को प्रमुखता दी तो कुछ अन्य ने मंदिर को. ■

बदलाव की अंतरशक्ति दिख रही है : अखिलेंद्र प्रताप

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला प्रकरण और जेएनयू में कन्हैया कुमार गिरफ्तारी प्रकरण पर छात्रों की सक्रियता और एकजुटता को नई शुरुआत के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक दलों का स्वर इन छात्रों के समर्थन का है, नेतृत्व का नहीं है. राजनीतिक दल छात्रों के समर्थक भर हैं. अखिलेंद्र हैदराबाद-जेएनयू प्रकरण को विचारधारात्मक आग्रह का आंदोलन बताते हैं और कहते हैं कि इस बार के आंदोलन में अंबेडकर के प्रति समर्पण का भाव है. कन्हैया भी रोहित को ही आइकॉन मानता है. यह बदलाव की अंतरशक्ति को दर्शा रहा है. इसमें पूरा समूह ही नेतृत्व करता दिख रहा है. छात्रों के बीच से ही नेतृत्व प्रस्फुटित होगा. अखिलेंद्र कहते हैं कि भारतवर्ष विभिन्न विचारधाराओं के साथ चलने वाला देश है. एक खास विचारधारा को आरोपित करने का तौर-तरीका अलोकतांत्रिक है. जेएनयू में लगाए गए देश विरोधी और अफजलवादी नारों के बारे में उनका मानना है कि जेएनयू में हुई नारेबाजी आपत्तिजनक तो है, पर यह राष्ट्रद्रोह नहीं है. ■

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कोलकाता का जादवपुर विश्वविद्यालय बीच-बीच में सुर्खियों में आता रहा है. 11 जनवरी को यूनियन के चुनाव के लिए छात्रों ने वाइस चांसलर सुरंजन दास का 56 घंटे तक घेराव किया था. सुरंजन दास इतिहास के गहरे जानकार हैं और पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक जगत में उनकी प्रतिष्ठा है. उनकी सारी ऊर्जा विश्वविद्यालय को शांत और व्यवस्थित रखने में लगी रहती है. लेकिन लोगों के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि एक विख्यात शैक्षणिक संस्थान में ऐसी घटना कैसे हो गई?

बस कमी है एक जेपी की

पृष्ठ 3 का शेष

यादवपुर विश्वविद्यालय ने देश के लोगों को चौंकाया है

विनय बिहारी सिंह

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशद्रोही नारे लगने के सात दिन बाद कोलकाता के यादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति निश्चय ही अनेक लोगों के लिए चौंकाने वाली घटना थी. जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में एक रैली निकाली गई और उसमें अफजल गुरु की जय-जयकार हुई. जेएनयू में 9 फरवरी को छात्रों की एक सभा में देशद्रोही नारे लगे थे. फिर 16 फरवरी को यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र जुलूस की शक्ल में निकले और सड़कों पर नारे लगाते हुए घूमे. कुछ युवक इस जुलूस में नारे लगा रहे थे, अफजल बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी, जो तुम न दोगे आजादी, तो छीन के लेंगे आजादी. इसके बाद नारे लगे, मोदी का हिंदुत्व नहीं सहेंगे, मोदी की ब्राह्मणगीरी नहीं सहेंगे. इस जुलूस में इशरत जहां के पक्ष में भी नारे लगे जिस पर लश्करे तैयबा जैसे उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का आरोप है. यादवपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुरंजन दास से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देशद्रोही नारे लगाने वाले युवक फ्रिंज एलीमेंट थे यानी दरकिनार हुए युवक थे. वे विश्वविद्यालय से बाहर से आए थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराएंगे तो उनका जवाब था, नहीं. यह वाइस चांसलर का काम नहीं होता. विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की आजादी की स्वस्थ परंपरा रही है लेकिन जिन लोगों ने देशविरोधी नारे लगाए, विश्वविद्यालय की यूनियन उनके खिलाफ है. यूनियन ने इसे लिखित रूप से कहा है.

कोलकाता का यादवपुर विश्वविद्यालय बीच-बीच में सुर्खियों में आता रहा है. 11 जनवरी को यूनियन के चुनाव के लिए छात्रों ने वाइस चांसलर सुरंजन दास का 56 घंटे तक घेराव किया था. सुरंजन दास इतिहास के गहरे जानकार हैं और पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक जगत में उनकी प्रतिष्ठा है. उनकी सारी ऊर्जा विश्वविद्यालय को शांत और व्यवस्थित रखने में लगी रहती है. लेकिन लोगों के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि एक विख्यात शैक्षणिक संस्थान में ऐसी घटना कैसे हो गई? देशद्रोह के नारे लगाने वाले ये लोग अचानक कहां से प्रकट हो गए? विश्वविद्यालय में कश्मीर, मणिपुर और नगालैंड की आजादी के पोस्टर किन तत्वों ने लगाए?

पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वामपंथी और धुर वामपंथी विचारधारा से प्रभावित अनेक छात्र हैं. स्पष्ट है कि वे दक्षिणपंथी विचारधारा वाली केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हैं. पिछले साल जनवरी 2015 में यादवपुर विश्वविद्यालय के फेडरेशन ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट (एफएएस) ने कला संकाय के छात्रों की यूनियन का चुनाव लड़ा. उसके एक साल पहले यानी सन 2014 में चारों पदों, जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी (दिवा काल), असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी (सांध्य काल) और चेयरपरसन पदों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का कब्जा था. लेकिन पिछले साल धुर वामपंथी संगठन (माओवाद समर्थक) यूनाइटेड स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूएसडीएफ) ने तीन सीटों पर कब्जा कर लिया. एसएफआई की झोली में सिर्फ एक पद जनरल सेक्रेटरी (सांध्य काल) का ही आया.

इस साल ये चुनाव अभी होने हैं. तो धुर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने यदि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना के समर्थन में जुलूस निकाला और नारे लगाए तो यह उतनी चौंकाने वाली घटना नहीं है. खासतौर से पश्चिम बंगाल में जहां वामफ्रंट सरकार 34 सालों तक सत्ता में रही हो, वहां वामपंथी विचारधारा में एक पीढ़ी जन्मी है और इसी विचारधारा में पढ़ लिख और विभर्ष कर जवान हुई है. लेकिन वामफ्रंट के शासनकाल में देशविरोधी नारे कभी नहीं लगे. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तो ऐसे तत्वों के खिलाफ है. तब ये कौन लोग हैं जिन्होंने छात्रों के इस विरोध जुलूस के बीच आकर देशविरोधी नारे लगाए? कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि ये बाहरी तत्व हैं जो विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन के बहाने जुलूस में घुस आए और देश विरोधी नारे लगाने लगे. इन्हें विदेशों से मदद मिलती है. पर, ऐसे आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है. उधर कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि गिनती के कुछ तत्व अपने देश में ऐसे भी हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उनके पीछे बड़ी ताकतें काम कर रही हैं. ऐसे तत्व अपने छद्म रूप की खाल में युवा छात्रों से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और अपने आकाओं की मुराद पूरी करते हैं. इस बीच अच्छी खबर यह है कि खुफिया एजेंसियां इस घटना के परिप्रेक्ष्य में सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने गहन पड़ताल शुरू कर दी है. वैश्विक आंकड़ों को देखें तो अपना देश वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है. ऐसे में विश्वविद्यालयों में बेचैनी और राजनीतिक उथल-पुथल शैक्षणिक माहौल को कहां ले जाएगा? बुद्धिजीवियों की चिंता यही है. ■

जेएनयू इस शहादत को भी याद रखना चाहिए था

जेएनयू के छात्र संघर्ष और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तमाम चर्चाएं हुईं, लेकिन किसी भी छात्र नेता ने, नेता ने या स्वनामधन्य पत्रकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शहीद चंद्रशेखर को याद नहीं किया. कई बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे प्रखर छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या को ताजा परिप्रेक्ष्य में भी याद रखने की जरूरत है. 1994-95 में चंद्रशेखर जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे. चंद्रशेखर लगातार दो साल तक छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव जीतते रहे. 31 मार्च 1997 को बिहार के सीवान जिले में बथानी टोला नरसंहार के खिलाफ आयोजित एक सभा को संबोधित करते समय चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई थी. चंद्रशेखर बिहार में राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जुझारू अभियान चला रहे थे. चंद्रशेखर की हत्या बिहार के कुख्यात माफिया सरगना शहाबुद्दीन ने कराई थी. जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या कराने वाले माफिया सरगना शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के खास रहे हैं. उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब तल्ख बयान दिए और जेएनयू के इस छात्र नेता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन जताया. चंद्रशेखर की हत्या के मामले में असली षडयंत्रकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मसला घनघोर राजनीति में फंसा दिया गया था, वह आज भी रिपोर्ट और प्रति रिपोर्ट की बेमानी कानूनी औपचारिकताओं के मकड़जाल में ही उलझा हुआ है. शहाबुद्दीन जेल में तो हैं, लेकिन चंद्रशेखर हत्याकांड में नहीं. ■

राष्ट्रभक्ति की एकपक्षीय परिभाषा बंद होनी चाहिए

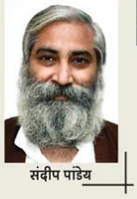

संदीप पांडेय

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनसे अलग विचारों को मानने वाले लोग हैं उनपर देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं, जबकि खुद इस देश के संविधान और कानून-व्यवस्था का सम्मान नहीं करते. आज देश में एक बहस छिड़ी हुई है. कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त? इसे सावधानी से परखने की जरूरत है. क्या देशभक्त कहलाने के लिए काफी है कि कोई भारत माता की तस्वीर लेकर, वंदे मातरम के नारे लगाकर, भारत का झंडा लहराकर, पाकिस्तान को गाली देकर उन लोगों के साथ मार-पीट करे जो उसके विचारों को नहीं मानते? यदि हम आतंकवाद और नक्सलवाद के नाम पर होने वाली हिंसा को गलत मानते हैं तो इस हिंसा को जायज कैसे ठहराया जा सकता है?

इस देश में इस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब गरीब ही बना रहे. इस देश के आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. इस देश में करीब चौथाई बच्चे बाल दासता के शिकार हैं. खराब स्वास्थ्य सेवाओं के चलते एक हजार पैदा होने वालों बच्चों में 47 मर जाते हैं. पांच वर्ष तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इन हजार में से 14 और बच्चे मर जाते हैं. एक लाख बच्चों का जब जन्म होता है तो 200 माएं जन्म देते वक्त मर जाती हैं. जबसे इस देश में उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं, करीब तीन लाख किसान कर्ज के बोझ में आत्महत्या कर चुके हैं. क्या ऐसी नीतियां बनाने वाले जिससे लोगों की मौतें हों और वे बदहाली में जिएं, देशद्रोही नहीं हैं?

इस देश में निजी कम्पनियों के पास सरकारी बैंकों के 1.14 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में बकाया हैं, जिसे बैंकों ने माफ कर दिया है. जिस देश में गरीबी की उपर्युक्त स्थिति हो वहां जनता के पैसे को निजी कम्पनियों को यूं ही दे दिया जाए, क्या यह देशद्रोह नहीं? या फिर भ्रष्टाचार करने वाले जो देश का पैसा अपने निजी उपभोग के लिए रख रहे हैं, क्या देशद्रोही नहीं हैं? भाजपा की सभी सरकारों में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने की बात होती है किंतु हमारी अर्थव्यवस्था का काला धन जिससे राजनीतिक दल अपराधी-माफिया या भ्रष्ट उम्मीदवारों को चुनाव जितवा देते हैं और गलत लोग हमारी विधायिका में पहुंच जाते हैं, क्या यह देशद्रोह नहीं है? विदेशी पूंजी आकर्षित कर अपने यहां कारखाने लगवा कर अपने मजदूरों का शोषण होने देना क्या देशद्रोह नहीं है? देश की प्राकृतिक संपदा पर मुनाफा कमाने का अधिकार देसी-विदेशी कम्पनियों को दे देना क्या देशद्रोह नहीं है? उदाहरण के लिए पेप्सी-कोका कोला हमारा पानी हमें ही ऊंची कीमतों पर बेच कर मुनाफा अमरीका ले जा रही हैं. क्या ऐसी कम्पनियों की मदद करना देशद्रोह नहीं? नकल करके बच्चों को इम्तिहान पास करवा देना, जो इस देश में बड़े पैमाने पर होता है, क्या देशद्रोह नहीं है? क्योंकि हम बच्चों का भविष्य बरबाद कर रहे हैं.

दूसरी तरफ कोई भी ऐसा काम जिससे इस देश के आम नागरिक का सशक्तिकरण हो रहा हो क्या देशभक्ति नहीं? यदि कोई ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है जो खुद विद्यालय जाने में अक्षम हैं, देशभक्ति का काम नहीं? क्या किसी बेसहारा जिसको इलाज की जरूरत है की मदद करना देशभक्ति का काम नहीं? क्या गरीबों को संगठित कर उनके अधिकारों की लड़ाई में शामिल होना ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो देशभक्ति का काम नहीं? क्या किसी पीड़ित या पीड़िता जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो, को न्याय दिलाना देशभक्ति का काम नहीं? क्या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना ताकि आम इंसान का नुकसान न हो और सही नीतियों की मांग करना जिससे आम इंसान को लाभ मिले, देशभक्ति का काम नहीं? सरकार के बजट में अपव्यय के खिलाफ बोलना ताकि देश का पैसा बचे और जरूरी कामों में लगे, देशभक्ति का काम नहीं? उदाहरण के लिए रक्षा पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने के बजाए सरकार को यह राय देना क्या सही नहीं होगा कि सरकार जिन देशों से उसकी दुश्मनी है के साथ संबंध सुधारे ताकि रक्षा का खर्च कम हो और बचा हुआ पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आदि उपलब्ध कराने में लगे ताकि इस देश के और दुश्मन देश के भी गरीब लोगों को राहत मिले. क्या यह देशभक्ति का काम नहीं? यह तो ऐसी देशभक्ति है जिससे अपने देश के साथ पड़ोसी देश का भी फायदा हो.

असल में देखा जाए तो राष्ट्र की अवधारणा भी जाति और धर्म की तरह लोगों को बांटने का काम करती है और ये सभी बांटने वाली श्रेणियां कृत्रिम या मानव निर्मित हैं. राष्ट्र का तो अंततोगत्वा वह हश्र होना चाहिए जैसा आधुनिक यूरोप में हुआ है. जहां अब देश की सीमाओं पर न तो फौजें हैं और न ही एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीसा की जरूरत पड़ती है. दक्षिण एशिया में भी जरूर ऐसा दिन आएगा जब हम एक देश से दूसरे देश में ऐसे चले जाएंगे जैसे एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर रहे हों. इस तरह के राष्ट्र में उग्र तेवर वाले दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों की कोई ज्यादा भूमिका नहीं रह जाती. क्योंकि इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक सामने कोई दुश्मन, वास्तविक अथवा कल्पित, खड़ा किया गया हो. यह इनकी सबसे बड़ी विडम्बना है. इसलिए इनका सारा का सारा कार्यक्रम दुश्मन को केंद्र में रख कर होता है. यानी इनका अस्तित्व दुश्मन के अस्तित्व पर टिका हुआ है. इसलिए समझदार लोग इनकी बातों में नहीं आते. ■

(लेखक मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं)

चौथी दुनिया
प्रपत्र-4
(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	साप्ताहिक प्रति रविवार
3. मुद्रक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	29 डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार विकास मार्ग, दिल्ली-110092
4. प्रकाशक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	29 डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार विकास मार्ग, दिल्ली-110092
5. संपादक का नाम	**संतोष भारतीय**
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश	XXX
पता	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. के-2, गेनन, दूसरी मंजिल, चौथरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं एवं कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज़्यादा के साझीदार या शेयरधारक हैं.	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. 98, मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 1. गेनन डंकरली फाइनेंस लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 2. एम आर होल्डिंग लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 3. ह्वेली मल्टी मीडिया लिमिटेड, 98 मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021

मैं रामपाल सिंह भदौरिया एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं.

हस्ताक्षर
रामपाल सिंह भदौरिया
प्रकाशक

दिनांक : 01 मार्च, 2016

एमएलसी चुनाव में सपा ने जीती 31 सीटें, पर 30 बताकर ही मिटा रही झेंप

चन्द से रह गई पूर्ण खुशी

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 30 सीटें जीत लीं. आठ सीटों पर सपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, बाकी 28 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की. तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें जीती हैं. लेकिन इस तकनीकी कोण में सपा का दर्द छुपा हुआ है. यह एक सीट गोरखपुर के ताकतवर नेता सीपी चन्द ने जीती है. सीपी चन्द समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए थे. लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी का यादव प्रेम गहराया और अचानक प्रत्याशी बदल कर जयप्रकाश यादव को प्रत्याशी बना दिया. पार्टी ने जयप्रकाश यादव के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीपी चन्द को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, लेकिन सीपी चन्द के सामने सपा का प्रत्याशी टिक नहीं पाया. चुनाव आयोग ने भी ऐन मौके पर प्रत्याशियों की लिस्ट में सीपी चन्द को निर्दलीय के रूप में टंकित नहीं किया और बैलेट पेपर पर सीपी चन्द ही सपा के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में दर्ज रह गए. अब सपा के लिए सीपी चन्द लम्बे समय तक गले की हड्डी बन कर चुभते रहेंगे. इस तरह नैतिक रूप से सपा के पास 30 एमएलसी होंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर सीपी चन्द को मिला कर 31. चन्द की जीत से विधान परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए खुशियों के साथ-साथ थोड़ी तिक्तता भी लेकर आया. वाराणसी में बाहुबली ब्रजेश सिंह ने सपा प्रत्याशी मीना सिंह को हराया. ब्रजेश सिंह ने जेल में रहते हुए ही यह चुनाव जीता है.

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में सीतापुर से आनंद भदौरिया, लखनऊ-उन्नाव से सुनील कुमार साजन, प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह, बांदा-हमीरपुर से रमेश, आगरा-फिरोजाबाद से दिलीप यादव, मथुरा-एटा-मैनपुरी से उदयवीर सिंह और मेरठ-गाजियाबाद से राकेश यादव ने निर्विरोध जीत हासिल की. बाकी 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 22 सीटों पर जोरदार जीत हासिल की. 30 सीटें (तकनीकी तौर पर 31 सीटें) जीतकर उच्च सदन में सपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. 100 सीटों वाले राज्य विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटें हैं. इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू गोरखपुर-महराजगंज सीट का चुनाव ही रहा. यहां से विजयी घोषित किए गए सीपी चन्द को निर्वाचन आयोग ने सपा उम्मीदवार बताया, जबकि सपा ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा कि उसके 30 प्रत्याशी ही जीते हैं. सपा ने पहले सीपी चन्द को चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी. बाद में सीपी चन्द के स्थान पर जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया. मतदान के दो दिन पहले सीपी चन्द को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था. लेकिन सपा को इसका कोई फायदा नहीं मिला. 28 सीटों के लिए तीन मार्च को चुनाव हुए. छह मार्च आए चुनाव परिणाम के मुताबिक 23 पर सपा, दो पर बहुजन समाज पार्टी, दो पर निर्दलीय और एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका. 28 सीटों में से 23 पर जीत हासिल करने के साथ ही विधान परिषद में अब सपा की सीटें बढ़कर 58 हो गई हैं.

स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों की 36 सीटों में से 34 बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास थी. एक-एक सीट कांग्रेस और सपा के पास थी. 15 जनवरी को इनका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद सदन में बसपा सदस्यों की संख्या घटकर 14 रह गई थी. इन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही सपा 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन नए नतीजों से उच्च सदन में उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 58 हो गई. इस तरह विधानसभा और विधान परिषद दोनों में सपा को बहुमत हासिल हो गया. ■

काबीना मंत्री की धमकियां भी नहीं जिता पाईं

गाजीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने सपा प्रत्याशी सानंद सिंह को 65 वोटों से हरा दिया. प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ओमप्रकाश सिंह द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने को इस हार का कारण बताया जा रहा है. मंत्री द्वारा धमकी देने का प्रकरण सुर्खियों में आया था, लेकिन उस पर सरकार ने मौन साधे रखा. विजयी प्रत्याशी विशाल सिंह ने सपा उम्मीदवार की हार के लिए ओमप्रकाश सिंह की धमकियों के प्रति लोगों के आक्रोश को कारण बताया. विशाल सिंह चंचल के चाचा और बसपा एमएलसी राजदेव सिंह ने कहा कि लड़ाई सपा से नहीं बल्कि मंत्री ओम प्रकाश सिंह बनाम राजदेव सिंह के परिवार के बीच थी. काबीना मंत्री की धमकियों के प्रति लोगों की नाराजगी का फायदा हमें मिला है. यही हाल रहा तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की और दयनीय स्थिति हो जाएगी. ■

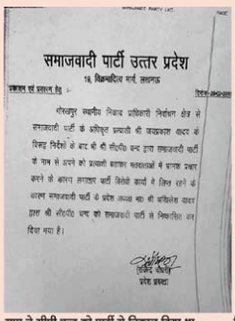

सपा ने सीपी चन्द को पार्टी से निकाल दिया था...

फिर भी चुनाव आयोग ने चन्द को ही माना सपा का प्रत्याशी.

विधान परिषद की 36 सीटों पर जीते उम्मीदवार

1	बाराबंकी	राजेश कुमार यादव	सपा
2	बहराइच	मोहम्मद इक़बाल खान	सपा
3	गोंडा	महफ़ुज़ुरहमान	सपा
4	फैजाबाद	हीरालाल यादव	सपा
5	बस्ती-सिद्धार्थनगर	संतोष यादव उर्फ सनी	सपा
6	गोरखपुर-महराजगंज	सीपी चन्द	सपा(बागी)
7	देवरिया	राम अवध यादव	सपा
8	आजमगढ-मऊ	राकेश कुमार यादव	सपा
9	बलिया	रविशंकर सिंह	सपा
10	गाजीपुर	विशाल सिंह चंचल	निर्दलीय
11	जौनपुर	बृजेश कुमार सिंह उर्फ प्रिंसू	बसपा
12	वाराणसी	बृजेश कुमार सिंह	निर्दलीय
13	मिर्जापुर-सोनभद्र	रामलली	सपा
14	इलाहाबाद	वासुदेव यादव	सपा
15	बांदा-हमीरपुर	रमेश	सपा
16	झांसी-जालौन-ललितपुर	रमा निरंजन	सपा
17	कानपुर-फतेहपुर	दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव	सपा
18	इटावा-फर्रुखाबाद	पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी	सपा
19	आगरा-फिरोजाबाद	दिलीप यादव	सपा
20	मथुरा-एटा-मैनपुरी	उदयवीर सिंह	सपा
21	मथुरा-एटा-मैनपुरी	अरविन्द प्रताप	सपा
22	अलीगढ	जसवंत सिंह	सपा
23	बुलन्दशहर	नरेन्द्र सिंह भाटी	सपा
24	मेरठ-गाजियाबाद	राकेश यादव	सपा
25	मुजफरनगर-सहारनपुर	मोहम्मद अली	बसपा
26	मुरादाबाद-बिजनौर	परवेज अली	सपा
27	रामपुर-बरेली	घनश्याम सिंह लोधी	सपा
28	बदायूं	बनवारी सिंह यादव	सपा
29	पीलीभीत-शाहजहांपुर	अमित यादव	सपा
30	हरदोई	मिस्बाहुद्दीन	सपा
31	लखीमपुर खीरी	शशांक यादव	सपा
32	सीतापुर	आनंद भदौरिया	सपा
33	लखनऊ-उन्नाव	सुनील कुमार	सपा
34	रायबरेली	दिनेश प्रताप सिंह	कांग्रेस
35	प्रतापगढ़	अक्षय प्रताप सिंह	सपा
36	सुलतानपुर	शैलेन्द्र प्रताप सिंह	सपा

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश की नेपाल यात्रा से उम्मीदें

सरोज सिंह

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के कई पुराने मसलों पर नई रोशनी पड़ती दिखाई दी. नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने में नेपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करते हुए ज़ोर दिया गया कि इस कार्य में सप्तकोसी एवं सनकोसी पर प्रस्तावित हाईडैम काफी मददगार साबित हो सकते हैं. नीतीश कुमार के साथ-साथ नेपाली नेताओं ने भी वहां उपलब्ध जल-शक्ति के बेहतर इस्तेमाल और पनबिजली को विकसित करने पर ज़ोर दिया. यह आम राय बनी कि पनबिजली के सहारे नेपाल के लिए समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और भारत भी लाभांवित होगा. नीतीश ने बिहार के साथ नेपाल के सदियों पुराने एवं मधुर संबंधों को नया आयाम देने के ख्याल से पटना और गया से काठमांडू के बीच हवाई सेवा शुरू करने पर भी ज़ोर दिया. इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की छवि एक मंझे हुए नेता के तौर पर उभर कर सामने आई.

नीतीश की यह नेपाल यात्रा उस समय हुई, जब वहां संविधान की कई व्यवस्थाओं को लेकर माहौल में खासी गर्माहट है और साथ ही तराई क्षेत्र में मधेसी आंदोलन ने राजनीतिक व्यवधान पैदा कर रखा है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से यह आंदोलन स्थगित है, लेकिन इसके कभी भी फिर से भड़क उठने की आशंका है. इस आंदोलन से उन तबकों को ताकत मिली है, जो नेपाल को भारत की छाया से मुक्त करने के पक्षधर रहे हैं. इनमें वे राजनीतिक एवं ग़ैर राजनीतिक ताकतें भी शामिल हैं, जो भारत के बजाय चीन से मधुरता चाहती हैं. मधेसी आंदोलन के विभिन्न धड़ों के नेताओं ने भी नीतीश कुमार से भेंट की. हालांकि, नीतीश ने अपने नेपाल प्रवास के दौरान ही साफ़ कर दिया कि मधेसी आंदोलन नेपाल का आंतरिक मसला है और इसका समाधान स्वयं नेपाल को तलाशना है. नीतीश की यह यात्रा नेपाली कांग्रेस के आमंत्रण पर हुई थी. नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए नीतीश ने नेपाल के सार्वजनिक जीवन में नेपाली कांग्रेस की भूमिका को सराहा. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, समाजवादियों एवं महत्वपूर्ण शख्सियतों से नेपाली कांग्रेस के रिश्तों की चर्चा की. संविधान की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उपजे जनाक्रोश विशेषकर, मधेसी आंदोलन के आलोक में नेपाली कांग्रेस का यह 13वां अधिवेशन काफी अहम साबित हुआ. इसमें नीतीश कुमार की भागीदारी ने पूरे प्रकरण को नए आयाम दिए हैं. गौरतलब है कि नेपाली कांग्रेस का जन्म 1947 में भारत में हुआ था और उसका पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था. नेपाल में राणाशाही के ख़िलाफ़ जन क्रांति (जिसे नेपाली क्रांति कहा जाता है) का नेतृत्व वीपी कोइराला ने किया था, जिन्हें भारत और बिहार में खासा आदर-सम्मान हासिल था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा को उपलब्धियों में बदलना बिहार सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका उससे भी कहीं बड़ी है. एक दौर था, जब पटना और काठमांडू के बीच नियमित हवाई सेवा उपलब्ध थी. क़रीब चार दशक पहले यह सेवा बंद कर दी गई, जबकि बिहार से नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी-खासी है. अब काठमांडू जाने के लिए पहले दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता है और दूसरा रास्ता है, वीरगंज एवं विराट नगर से. गया अंतरराष्ट्रीय तीर्थ है और बड़ी तादाद में लोग नेपाल से गया आते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश की सलाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूबे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय खिड़की खुलेगी. इतना तो तय है कि यह हवाई मार्ग घाटे का सौदा नहीं साबित होगा. इसी तरह पनबिजली का मसला है. पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर में जल-शक्ति का इस्तेमाल आर्थिक ताक़त के तौर पर होने लगा है. दुनिया के विभिन्न देश पनबिजली के ज़रिये जल का भरपूर दोहन करते हैं और इससे उनकी आमदनी में काफी इज़ाफ़ा हुआ है. वैसे भी कोयला भंडार सीमित होने के कारण उस पर दबाव कम करना आज आर्थिक बुद्धिमानी माना जाता है. भूटान पानी से इतनी बिजली पैदा करता है कि भारत को भी देता है. जल-शक्ति के सार्थक इस्तेमाल का यह अनुपम उदाहरण है. नेपाल के पास जल-शक्ति का अकूत भंडार है. ऊपर से गिरते पानी से बिजली बनाना खर्चीला भी नहीं है. यह नेपाल के लिए आय का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा को उपलब्धियों में बदलना बिहार सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका उससे भी कहीं बड़ी है. एक दौर था, जब पटना और काठमांडू के बीच नियमित हवाई सेवा उपलब्ध थी. क़रीब चार दशक पहले यह सेवा बंद कर दी गई, जबकि बिहार से नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी-खासी है.

जल के इस इस्तेमाल से उत्तर बिहार की बाढ़ त्रासदी कम करने में भी मदद मिलेगी. नीतीश की नेपाल यात्रा का एक मकसद बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने की पहल करना भी था. सप्तकोसी एवं सनकोसी पर प्रस्तावित हाईडैम की रूपरेखा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने पर सहमति हो चुकी थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हो सका. उक्त हाईडैम बनने से पनबिजली तैयार होने के साथ-साथ नेपाल और बिहार में बाढ़ त्रासदी कम की जा सकती है. भौगोलिक स्थिति के चलते बिहार को बाढ़ से निज़ात तो नहीं मिल सकती, लेकिन बेहतर जल प्रबंधन के ज़रिये राहत ज़रूर दी जा सकती है. हाईडैम बनने से हिमालयी नदियों का बेलगाम जलप्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन, यह अंतरराष्ट्रीय मसला है और बिहार के पास करने के लिए बहुत कम है. ऐसे में बिहार सरकार केंद्र से इस मसले पर गंभीर और सार्थक पहल का अनुरोध ही कर सकती है. और, नीतीश कुमार ने यह मसला छेड़कर माहौल बनाने की कोशिश की है. यह इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपदा प्रबंधन के नाम पर खर्च हो जाता है. जान-माल और फसल का जो नुक़सान होता है, उसका तो आकलन ही संभव नहीं हो पाता. इसलिए बिहार में बाढ़ के मद्देनज़र बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ नेपाल की सक्रियता पर्याप्त नहीं है. कोसी एवं गंडक समेत उत्तर बिहार की विभिन्न नदियां हिमालय से निकलती हैं या वहां से निकली किसी नदी की शाखाएं हैं, जो नेपाल के रास्ते उत्तर बिहार में मैदानी हिस्से पर उतरती हैं और कहर बरपाते हुए गंगा के बाद सागर में मिल जाती हैं. उक्त नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लातीं, बल्कि गाद, मिट्टी और पत्थर भी लाती हैं. कोसी समेत उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उथली होती जा रही हैं, उनके पेट भरते जा रहे हैं. नतीजतन, मामूली बाढ़ भी कहर बरपा देती है.

एक सवाल और है, जिस पर भारत, विशेषकर बिहार को गंभीरता से विचार करना होगा. यह सवाल है तस्करी का. भारत-नेपाल सीमा का क़रीब साढ़े सात सौ किलोमीटर हिस्सा बिहार में है, जो खुला हुआ है. यह खुली सीमा कई परेशानियों की जड़ है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं शिवहर आदि ज़िलों में खिलौनों, बॉलपेन, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, बच्चों की साइकिलों, धूप के चश्मों और रेडिमेड कपड़ों के बाज़ार पर चीनी उत्पादों का कब्जा है. इन वस्तुओं की खोज अगर आप उत्तर बिहार के खुले एवं छोटे बाज़ार-दुकान में करते हैं, तो आपको पहले चीनी उत्पाद मिलेंगे. मांगने पर ही भारत निर्मित वस्तुएं मिल सकेंगी. विडंबना यह कि इस पर देश के किसी कोने में किसी को चिंता नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आपदा, आंदोलन और अर्थव्यवस्था

विशाल एसएन

हाल में हरियाणा में हुए जाट आंदोलन ने समाज, देश एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यापार और व्यापारियों के लिए एक ऐसी चुनौती पेश की है, जिसे नज़रअंदाज़ करना बहुत महंगा साबित हो सकता है. आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ उक्त आंदोलन उस समय आक्रामक हो गया, जब उसमें कुछ उग्र तत्व शामिल हो गए, जो सरकार तक अपनी बात तुरंत पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे. नतीजा यह हुआ कि अनगिनत दुकानों, गोदामों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया. उक्त आंदोलन के चलते व्यापारियों एवं अर्थव्यवस्था के नुक़सान का सही आकलन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इतना तो निश्चित है कि यह नुक़सान हज़ारों करोड़ रुपये का है. इस नुक़सान की भरपाई के लिए कितना और खर्च करना होगा, उसके बारे में तो कल्पना करना ही बेमानी है. अनेक व्यापारियों की जीवन भर की पूंजी नष्ट हो गई, व्यापार तबाह हो गया, दुकानों एवं गोदामों में भरा माल ख़ाक हो गया. बहुत सारे व्यापारी ऐसे होंगे, जिनके लिए यह आघात झेलना आसान नहीं होगा और वे पूरी ज़िंदगी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकेंगे. कुछ ऐसे भी होंगे, जिनके लिए यह आघात हार्ट अटैक, स्ट्रोक या जीवन भर की कोई बीमारी बनकर सामने आएगा. इन हालात के बावजूद कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनकी सुध ले और मदद करे. व्यापारियों को स्वयं यह आघात झेलना होगा. हो सकता है कि जिन्होंने दुकान में आग लगाई, उनमें से कोई कल वहीं सामान खरीदने की लाइन में खड़ा हो.

ऐसा पहली बार नहीं है. कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या आंदोलन, उसके नतीजे में अर्थव्यवस्था ही थरथराती है. और, जब भी अर्थव्यवस्था थरथराती है, तो उसका सबसे भीषण प्रहार व्यापारी पर होता है. अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में बारिश ने तमिलनाडु में जमकर कहर ढाया था. गोदाम, दुकानें, शोरूम एवं फैक्ट्रियां आदि कुछ भी नहीं बचा. हर जगह 10-15 फुट तक पानी भर गया, जिससे माल और फर्नीचर बर्बाद हो गया. दशकों की मेहनत से खड़े हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं कारखाने काम के लायक नहीं बचे. तबाही के बाद सिर्फ़ व्यापारी बचा, मंजर देखता और यह सोचता हुआ कि वह कहां से संभलना शुरू करे. कहना मुश्किल है कि हरियाणा में हुई बर्बादी से उबरने में किसे कितना समय लगेगा और कितने लोग उसके चलते अस्पताल पहुंच जाएंगे या ताज़िंदगी उसके असर में रहेंगे. अगर पिछले एक-डेढ़ दशक के दौरान सामने आए कुछ बड़े आंदोलनों एवं प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुई आर्थिक तबाही के व्यापार पर असर संबंधी आंकड़ों पर निगाह डालें, तो एक भयावह तस्वीर उभर कर सामने आती है (देखें बॉक्स). जबकि छोटे-मोटे दंगों, आपदाओं एवं आंदोलनों के चलते व्यापारियों को होने वाले नुक़सान का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है. तमाम सरकारी-ग़ैर सरकारी उपायों के बावजूद आपदाओं का ख़तरा हमेशा मंडराता रहता है. इन प्रत्यक्ष कारणों के अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी होते हैं, जो समस्या की विकरालता बढ़ा देते हैं. अगर किसी वजह से व्यापार नहीं होता और बाज़ार लंबे समय तक बंद रहते हैं, तब भी व्यापारियों पर मार पड़ती है. पृथक तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुए आंदोलन के चलते लगभग डेढ़-दो वर्षों तक बाज़ार नहीं खुल सके. नतीजतन, व्यापारी लगातार घाटा उठाते रहे. आपदा हो या आंदोलन, अगर उनके चलते बाज़ार न खुल सकें या व्यापारिक गतिविधियां थम जाएं, तो व्यापारियों के सामने विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं.

घटनाएं	वर्ष	अनुमानित नुक़सान (रुपये में)
जाट आंदोलन	2016	35,000 करोड़ से ज़्यादा
चेन्नई की बाढ़	2015	50,000 करोड़ से ज़्यादा
पटेल आंदोलन	2015	...
उत्तराखंड की बाढ़	2013	12,000 करोड़ से ज़्यादा
मुंबई की बाढ़	2005	550 करोड़ से ज़्यादा
गुजरात भूकंप	2001	9,900 करोड़ से ज़्यादा

जिस तरह पर्यावरण, वर्षा, हवा एवं समुद्र यानी सबके व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे यह बिल्कुल साफ़ है कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, भूकंप आदि का ख़तरा हमेशा बना रहेगा. जिस तरह आएदिन आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही कुछ अन्य राज्यों में भी आंदोलन ज़ोर पकड़ेंगे. कहीं गुर्जर अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का सहारा लेंगे, तो कहीं राजपूत. कुल मिला व्यापार और व्यापारियों पर आसन्न ख़तरा टलना नहीं है, बल्कि बढ़ने की आशंका है. आज ज़रूरत इस बात की है कि व्यापारी बार-बार की तबाही से निबटने के लिए स्वयं कमर कसें. यह एक तीखा सच है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था, एजेंसी या विभाग नहीं है, जिसके पास जाकर व्यापारी गुहार लगा सकें और उनकी सुनवाई हो सके. इन हालात में व्यापारियों को स्वयं अपना सहारा बनना होगा और आपसी सहयोग के लिए मजबूत संगठन बनाने होंगे. जहां तक संभव हो, हर चीज का बीमा कराना होगा जैसे मकान, दुकान, माल, वाहन, गोदाम, फैक्ट्री यानी सबका. साथ ही खुद का भी, क्योंकि व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी व्यापारी है. सरकार एवं संबंधित एजेंसियों को भी समझना होगा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, अगर उसका व्यापार ख़तरे में पड़ता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था ख़तरे में पड़ती है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क़ानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. आंदोलनों एवं आपदाओं के व्यापार और व्यापारियों पर पड़ने वाले असर से निबटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाई जाए, अन्यथा भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का सपना सिर्फ़ एक सपना बनकर रह जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान

बजट में सियासी जमाजोड़

सुनीता सिंह

राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह बजट पेश किया. इसमें मुख्यमंत्री ने कुछ कल्याणकारी घोषणाएं भी कीं और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई, लेकिन बजट की सबसे खास बात यह रही कि मौजूदा सरकार ने 26 महीने पहले जहां से यह पारी शुरू की थी, वह फिर से उसी जगह जाकर टिकती दिखाई दी. मतलब, पहले बजट में जिस तरह मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए पिछली सरकार के माथे ठीकरा फोड़ा था, वैसा ही लगातार तीसरी बार हुआ.

180 मिनट का आलोचना बजट

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करीब तीन घंटे तक धारा प्रवाह बोलती रहीं. 122 पन्नों के बजट भाषण की एक-एक लाइन उन्होंने पढ़ी, लेकिन इस दौरान वे पिछली गहलोत सरकार पर बीच-बीच में बरसना नहीं भूलीं. जहां पर भी वित्तीय हालात खराब होने की बात आई, उन्होंने उसका जिम्मेदार गहलोत सरकार को ही बताया. यह बात सियासी हलकों के साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी खटकी कि आखिर 26 महीने बाद भी अगर कोई राज्य वित्तीय कुप्रबंधन के लिए पिछली सरकारों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा हो, तो क्यूं न यह माना जाए कि दरअसल कमी कहीं कुछ अपने ही अंदर है.

रोज़गार का रोडमैप नहीं

यूं तो मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कुल मिला कर 11 नई और कई छोटी-मोटी घोषणाएं कीं और इन सभी में लोगों को कुछ न कुछ देने की भी कोशिश की, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी समस्या यानी की रोजगार को लेकर वे कोई रोडमैड प्रस्तुत करने में कामयाब नहीं हो सकीं. अलबत्ता उन्होंने यह तो वादा किया कि सरकार एक लाख नौकरियां देगी, लेकिन ये नौकरियां कितने समय में दी जाएंगी या कैसे दी जाएंगी, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं किया. सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ा कर 62 साल कर देने से उन्हें कुछ राहत दी, जबकि बेटियों के लिए भी पहली बार कुछ सकारात्मक सोच बजट में दिखी.

बजट में नई सौगात

जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ के नारे को प्रोत्साहन देते रहे हैं, तो राज्य के इस बजट में भी उनके इस आह्वान की झलक मिली, जब मुख्यमंत्री ने राजश्री योजना के नाम पर एक नई योजना लॉन्च, जिसमें एक जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली हर बेटी को जन्म पर 2500 रुपये देने के साथ ही उसके पहले जन्मदिन पर भी 2500 रुपये देने का ऐलान किया गया. इतना ही नहीं, जब बेटी सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेगी, तो उसे 4000 रुपये देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है. इसके बाद पाचवीं कक्ष में पहुंचने पर उसे फिर 5000 रुपये और 10वीं कक्षा में आने पर 11 हजार रुपये देने की बात कही गई है. 12वीं कक्षा पास करने पर बेटी को 25000 रुपये दने की बात इस योजना में की गई है.

अच्छी-अच्छी बातें

कुछ और अच्छी बातें भी बजट में सामने आईं, जिसमें जनता को जमीनों की रजिस्ट्री की डीएलसी रेट न बढ़ाकर कुछ राहत जरूर दी गई. गौरतलब है कि अब तक प्रावधान यह था कि चालू वित्त वर्ष में डीएलसी की मीटिंग न होने पर भी रेट को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता था. रजिस्ट्री दरों में बढ़ोत्तरी न करने से लोगों को जमीन के सौदों में कुछ राहत मिलेगी. यह एक अच्छी खबर है. हालांकि, यह राहत फिलहाल सिर्फ साल भर के लिए ही है. राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या यानी पेयजल को लेकर खुद राजधानी जयपुर के हाल भी बुरे हैं. बजट में 1045 करोड़ रुपये बीसलपुर से मीठा पानी जयपुर पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट को देकर लोगों के गले में राहत की बूंदें डालने की कोशिश हुई. 40 हजार किसानों को अगले साल तक कृषि बिजली कनेक्शन समेत किसानों, महिलाओं, समाज के पिछड़े तबकों और पशुपालकों के लिए की गईं तमाम घोषणाएं बजट को लोक लुभावन बनाते दिखीं. कई वस्तुओं पर वैट दरों में की गई कमी का असर भी लोगों को खुश करने वाला है.

...लेकिन निराश भी किया

बजट में तमाम चीजों के बावजूद कई बातें बेहद निराशाजनक कही जा सकती हैं. पहली बात तो यह कि सातवें वेतन आयोग की आस में प्रदेश का तमाम सरकारी तबका मुख्यमंत्री की ओर निहार रहा था कि वे इस बजट में सातवें वेतन आयोग के मद में कुछ राशि के आवंटन की घोषणा जरूर करेंगी. लेकिन उन्हें इस बारे में सीएम की ओर से एक भी शब्द न बोलने से घोर निराशा हुई. इसकेअलावा सिर्फ 10.50 करोड़ रुपये स्टार्ट अप के लिए दिए गए जो इतने बड़े मद के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. इसके अलावा कुछ जो सबसे अधिक विचलित करने वाला था, तो वह पिछली सरकार के समय के दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों पर मुख्यमंत्री का चुप्पी साधे रखना और उदासीन बने रहना. पहले बात रिफाइनरी की करते हैं. पश्चिमी राजस्थान केलिए जिसे आर्थिक उन्नति क्षेत्र में उगता हुआ सूरज माना जा रहा था, उस इलाके को मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं ने बेहद निराश किया है. तीन साल से कागलों में दफन रिफाइनरी का काम कब शुरू होगा, इस पर कुछ नहीं कहा गया. जबकि जयपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर केलिए भी कोई घोषणा नहीं हुई.

कुछ आकर्षक घोषणाएं

- कारोबारियों को स्टार्ट अप में छूट
- मकान खरीदना सस्ता हुआ
- डीलर्स को ढेर सारी सुविधाएं और इंसपेक्टर राज से मुक्ति देने के उपाय
- 86 हजार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए 354 करोड़
- 325 करोड़ रुपये की कर राहत
- एमबीबीएस की 350 सीटें प्रदेश के मेडिकल कालेजों में बढ़ाई.
- सामूहिक विवाह का अनुदान 10 हजार से बढ़ा कर 15 हजार किया.
- बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना
- मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप और स्कूटी-साइकिल वितरण योजना
- कारोबारियों को फुड प्रोसेसिंग में रियायतें
- 2000 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक का निर्माण
- खिलाडियों और सैन्यकर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं
- बृज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 103 करोड़
- मेंहदीपुर बाला जी और खाटू श्याम जी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट आवंटन
- रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के उपाय पर जोर देने के लिए बजट आवंटन

बजट वसुंधरा का, विजन मोदी का

यह भी काबिले गौर है कि वसुंधरा सरकार का लगातार तीसरा बजट मोदी के विजन को ही परिलक्षित करता दिखाई दिया. मोदी की पांच प्रिय योजनाओं सफाई यानी स्वच्छता, डिजिटलाइजेशन, ग्रीन योजना, स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना को इस बजट में भी आकार मिलता दिखाई दिया. जयपुर और उदयपुर को स्मार्ट सिटी के नाम पर 400 करोड़ रुपये मिले, जबकि अलग-अलग शहरों में सीवरेज इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 4200 करोड़ रुपये दिए गए. फसल बीमा योजना, पशु बीमा योजना, फसली ऋण जैसी कई बातें कुछ देर तक तो यह अहसास ही कराती दिखीं कि यह बजट केंद्र सरकार की फोटो प्रति ही है.

बिजली का घाटा खुद ओढ़ा

इस बजट की एक और खास बात यह रही कि इस पूरे बजट का तकरीबन 20 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को उबारने में ही खर्च हो गया. नतीजे में विकास के नाम पर आम जनता के हिस्से थोड़ा बहुत ही आ पाया. हालांकि, विद्युत निगमों के घाटे में जाने के लिए भी वसुंधरा ने गहलोत सरकार पर ठीकरा फोड़ कर एक तरह से यहां भी अहसान ही लादने की कोशिश की.

इनके लिए निराशाजनक

सूर्यनगरी यानी जोधपुर संभाग को न रोड न कॉलेज. कुछ कहा भी, तो पिछली घोषणाओं को पूरा करने का वादा ही किया. सरकार ने कई जिलों की लंबे अरसे से लंबित मांगों को दरकिनार किया, तो कई जगहों की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी भी की. जयपुर में मेट्रो परियोजना का जिक्र न करके एक तरह से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश ही हुई.

ब्लेम गेम का कारण समझिए

बिजली कंपनियों के घाटे से बिगड़े गणित ने तकरीबन पूरे बजट को ब्लेम गेम जैसा बना दिया. सरकार ने उदय योजना की बात कह बिजली कंपनियों का घाटा खुद वहन करने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन इसका खामियाजा विकास योजनाओं को भुगतना पड़ा. सरकार ने सारे वित्तीय अनुशासन तोड़ कर राजकोषीय घाटा 9.99 प्रतिशत पर पहुंचा दिया, जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत बजट घाटा तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता. हालात खराब हैं, इसका अंदाजा तो मुख्यमंत्री को भी हो गया, जिसके चलते उन्हें सफाई भी देनी पड़ी कि पिछली सरकार की खामियां सामने लाने के लिए वे दोहरे आंकड़े जारी कर रही हैं.

राजनीतिक विश्लेषण

जैसी की आशंका थी, कांग्रेस को यह बजट नहीं भाना था और हुआ भी ऐसा ही. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां इस सरकार को नाकामियों के लिए पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ने के लिए कोसा, तो साथ ही यह टिप्पणी भी कर डाली कि इस सरकार को कांग्रेस सरकार की कमियां खोजने में ही 26 माह लग गए, तो भला विकास योजनाओं का नंबर कब आता. वहीं कांग्रेस के प्रदेश में खेवनहार यानी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बजट को वास्तविकता से परे और आर्थिक स्थिति को और खस्ताहाल बनाने वाला बजट बता कर सरकार पर तीखा हमला बोला. ■

feedback@chauthiduniya.com

इरोम शर्मिला

कब ख़त्म होगा रिहाई-गिरफ्तारी का सिलसिला

शर्मिला को आत्महत्या के आरोप में 15 बार गिरफ्तार और रिहा किया जा चुका है. यह एक तरह से मज़ाक भी है. सवाल यह है कि क्या शर्मिला सचमुच अपना जीवन ख़त्म करने के लिए अनशन कर रही हैं? कतई नहीं. शर्मिला कई बार अपनी इच्छा ज़ाहिर कर चुकी हैं कि वह भी अन्य लोगों की तरह जीना चाहती हैं. शर्मिला ने अपना प्यार अब तक संजो रखा है. वह उस दिन के इंतज़ार में हैं, जब उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी.

एस. बिजेन सिंह

इस कहानी में कुछ भी नया नहीं है. यह सिर्फ़ भारतीय क़ानून का एक अनोखा अंदाज़ है. मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला एक बार फिर रिहा हुईं और गिरफ्तार भी हो गईं. यह एक वार्षिक परंपरा है. ग़ौरतलब है कि शर्मिला पूर्वोत्तर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट–1958 हटाने की मांग को लेकर पिछले 15 वर्षों से आमरण अनशन पर हैं. राज्य सरकार ने उन्हें आत्महत्या की कोशिश के आरोप में आईपीसी की धारा 309 के तहत गिरफ्तार किया था. न्यायिक हिरासत की समय सीमा पूरी होने पर हर वर्ष उन्हें रिहा किया जाता है और फिर तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है. जैसे शर्मिला का अनशन जारी है, वैसे यह परंपरा भी पिछले 15 वर्षों से जारी है. न तो शर्मिला अपना अनशन तोड़ रही हैं और न केंद्र–राज्य सरकारें उनकी मांग के प्रति कोई सकारात्मक रुख अपना रही हैं, जिससे यह रिहाई–गिरफ्तारी का सिलसिला ख़त्म हो. इस बार भी उन्हें बीती 29 फरवरी को रिहा किया गया, लेकिन उनका अनशन जारी था. सो, वह फिर गिरफ्तार कर ली गईं.

शर्मिला को आत्महत्या के आरोप में 15 बार गिरफ्तार और रिहा किया जा चुका है. यह एक तरह से मज़ाक भी है. सवाल यह है कि क्या शर्मिला सचमुच अपना जीवन ख़त्म करने के लिए अनशन कर रही हैं? कतई नहीं. शर्मिला कई बार अपनी इच्छा ज़ाहिर कर चुकी हैं कि वह भी अन्य लोगों की तरह जीना चाहती हैं, भोजन-पानी करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं. शर्मिला ने अपना प्यार अब तक संजो रखा है. वह उस दिन के इंतज़ार में हैं, जब उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी. शर्मिला ने अपनी मां से वादा कर रखा है कि जिस दिन वह अपने संघर्ष में सफल होंगी, उस दिन उनके हाथों से खाना खाएंगी. लेकिन, आज के दौर में शर्मिला का संघर्ष फीका पड़ता जा रहा है. बीते 15 वर्षों से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बार जब वह रिहा हुईं, तो महिला कार्यकर्ताओं के सहयोग से इंफाल स्थित शहीद मीनार पर माथा टेकने के बाद वहीं अनशन पर बैठ गईं. पुलिस द्वारा मना करने पर उन्हें वहां से हटना पड़ा. मीडिया से उन्होंने कहा, मैं यहां इसलिए आई हूं, ताकि मेरा संघर्ष सफल हो. मैं अफ्सपा के ख़िलाफ़ लड़ती रहूंगी.

शर्मिला ने कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि हत्या या दमन कोई समाधान नहीं है. इस मौक़े पर मणिपुर के राजा लैसेंबा सनाजाउबा भी शर्मिला से मिलने आए. उन्होंने कहा कि शर्मिला इस संघर्ष में अकेली नहीं हैं. सभी लोग अफ्सपा से पीड़ित हैं, इसलिए घाटी एवं पहाड़ों में रहने वाले सभी लोगों को इस संघर्ष में शामिल होना चाहिए. इंफाल को अशांत क्षेत्रों की सूची से हटाकर अफ्सपा ख़त्म किया जाना चाहिए. शर्मिला को इस बात का भी अफ़सोस है कि उनकी मांगों का समर्थन जिस पैमाने पर होना चाहिए, नहीं हो रहा है. शर्मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि अफ्सपा को पूर्वोत्तर से हटाना संभव नहीं है. एक तरफ़ तो केंद्र पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ़ अफ्सपा जैसे काले क़ानून को लेकर उसका रुख़ लचीला है. अगर पूर्वोत्तर में शांति के लिए अफ्सपा ज़रूरी है, तो फिर बीते 15 वर्षों में पूर्वोत्तर, ख़ासकर मणिपुर में शांति क्यों नहीं स्थापित हो सकी, सिवाय अलगाव की भावना बढ़ाने के? यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब एक न एक दिन सरकार को देना होगा.

क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (1958)

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट संसद में 11 सितंबर, 1958 को पारित किया गया था. यह क़ानून पूर्वोत्तर के अशांत राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नगालैंड में लागू है. यह क़ानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार देने के लिए बनाया गया था. अफ्सपा लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, लूट एवं हत्या जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई. जब 1958 में अफ्सपा बना, तो यह राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन 1972 में हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक, किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) घोषित कर वहां अफ्सपा लागू किया जा सकता है. इस क़ानून के सेक्शन 4–ए के अनुसार, सेना किसी पर भी गोली चला सकती है और अपने बचाव के लिए शक को आधार बना सकती है. सेक्शन 4–बी के अनुसार, सेना किसी भी संपत्ति को नष्ट कर सकती है. सेक्शन 4–सी के अनुसार, सेना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और वह भी बिना वारंट के. सेक्शन 4–डी के अनुसार, सेना द्वारा किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है. सेक्शन 6 के अनुसार, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सेना के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. ग़ौरतलब है कि जीवन रेड्डी कमेटी ने भी सरकार को संकेत कर दिया था कि यह क़ानून दोषपूर्ण है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है.■

sbijensngh@gmail.com

कब और क्यों शुरू हुआ अनशन

दो नवंबर, 2000 को असम राइफल्स के जवानों ने इंफाल से सात किलोमीटर दूर मालोम बस स्टैंड पर 10 बेकसूर लोगों को गोलियों से भून डाला. घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें अगले दिन स्थानीय अख़बारों में छपीं. मरने वालों में 62 वर्षीया महिला लिसेंगबम इबेतोम्बी एवं 18 वर्षीय सिनाम चंद्रमणि भी शामिल थे. चंद्रमणि 1988 में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार पा चुका था. इस घटना से विचलित होकर 28 वर्षीया शर्मिला ने चार नवंबर, 2000 को सत्याग्रह शुरू कर दिया.

सियासत की भेंट चढ़ गया भारत-पाक मैच

वीरभद्र सिंह

अनुराग ठाकुर

अवंतिका मिश्रा

भारत-पाकिस्तान के जिस मुक़ाबले पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, उसकी मेजबानी का मौक़ा हिमाचल प्रदेश के हाथों से फिसल गया. यह मैच धौलाधार के पहाड़ों की गोद में स्थित खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नहीं हो सका. कोलकाता के ईडन गार्डन को यह मैच कराने का मौक़ा मिल गया. धर्मशाला से इस हाई वोल्टेज मैच के शिफ्ट होने के कई कारण रहे. कोई इसे शहीदों के परिवारों एवं पूर्व सैनिकों का विरोध मान रहा है, तो कोई हिमाचल सरकार की मजबूरी. लेकिन, जानकार इसकी पीछे की मूल वजह सियासी नफ़ा-नुक़सान मान रहे हैं. हिमाचल को इससे क्या नुक़सान या फ़ायदा हुआ, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नेताओं को इससे क्या मिला, यह समझने के लिए प्रदेश की सियासी और क्रिकेट पृष्ठभूमि पर भी नज़र डालना ज़रूरी है.

हिमाचल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वर्तमान में दो सियासी ध्रुव हैं. बीसीसीआई के सचिव एवं एचपीसीए के अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर धूमल के बेटे हैं. भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की राजनीति में एंट्री क्रिकेट के माध्यम से हुई. एचपीसीए का अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल में उन्होंने क्रिकेट को नई दिशा दी, यह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी मानते हैं. धर्मशाला स्टेडियम के रूप में हिमाचल को पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैदान दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. 2008 में पहली बार सांसद बनने से पूर्व वह क्रिकेट के माध्यम से लोगों के सामने आए थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल के बेटे होने के अलावा क्रिकेट के क्षेत्र में काम का भी उन्हें राजनीति में लाभ मिला. एचपीसीए के माध्यम से बीसीसीआई में अहम ओहदा पाने वाले अनुराग ठाकुर को एक तरह से क्रिकेट ने ही नई पहचान दी.

2012 में प्रदेश में कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एचपीसीए की कई गड़बड़ियों का हवाला देते हुए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रातोंरात ताले लगवा दिए थे. एचपीसीए के ख़िलाफ़ विजिलेंस की जांच बैठा दी गई. कई मामलों की जांच चल रही है. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि धूमल परिवार ने एचपीसीए को अपनी जागीर बना लिया है. सूबे में क्रिकेट का पूरा साम्राज्य भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है. बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर इस बार टी–20 वर्ल्ड कप के आठ मैच धर्मशाला में लेकर आए थे, जिसमें भारत–पाक मुक़ाबला भी शामिल था. धर्मशाला में भारत–पाक मैच के विरोध में जैसे ही कुछ स्वर उठे, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शहीदों के परिवारीजनों की भावनाओं का हवाला देते हुए मैच के ख़िलाफ़ खड़े हो गए. बेशक, पठानकोट आतंकी हमले के शहीदों के परिवारीजनों का विरोध वाजिब था, लेकिन उनसे पहले मैच के विरोध में उतरे कुछ अन्य लोगों के भी सियासी हित रहे हैं. हिमाचल में पूर्व सैनिकों का एक बड़ा वोट बैंक है. कभी वीरभद्र सिंह के कट्टर विरोधी रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया की अगुवाई में मैच का विरोध कर रही पूर्व सैनिक लीग के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी रही. मुख्यमंत्री ने साफ़ कह दिया कि विरोध कर रहे पूर्व सैनिकों पर सरकार मैच के दौरान भी लाठी नहीं चलाएगी. उधर भाजपा की ओर से धर्मशाला में भारत–पाक मैच का सबसे पहला विरोध पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने किया. हिमाचल भाजपा में शांता और धूमल प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. ऐसे में क्रिकेट के पंखों पर हर कोई सियासी उड़ान भरता दिख रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गड़बड़ा गया अर्थशास्त्र

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के कोलकाता शिफ्ट हो जाने से हिमाचल को क़रीब पांच सौ करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. धर्मशाला में मैच होता, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और राज्य सरकार, दोनों का भला होता. मैच टलने से अनुराग का नुक़सान हुआ और वीरभद्र सिंह का भी. मैच से अनुराग ठाकुर का रुतबा बढ़ता, साथ ही एचपीसीए के ख़जाने में करोड़ों की रक़म भी आ जाती. पर्वतीय प्रदेश में मैच देखने का लोगों में जुनून था, जिसका सस्ती सियासत ने पटाक्षेप कर दिया. जानकार बताते हैं कि मैच के दौरान धर्मशाला स्टेडियम के अंदर क़रीब 25 लाख रुपये का मुनाफ़ा खाद्य एवं शीतल पेय पदार्थों की बिक्री से होता. वहीं मैच के टीवी राइट्स की कमाई बीसीसीआई के खाते में जाती. बाद में उसका 15 फ़ीसद एचपीसीए को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिल जाता. बीसीसीआई को विज्ञापनों और टीवी चैनल राइट्स से प्रति मैच 20 से 25 करोड़ रुपये की कमाई होती. इसके बदले बीसीसीआई खिलाड़ियों की मैच फीस और आने-जाने का खर्च उठाती. होटल में खिलाड़ियों के रहने-खाने का खर्च भी बीसीसीआई वहन करती, जबकि एचपीसीए को मात्र स्टेडियम के भीतर के इंतजाम देखने पड़ते. एचपीसीए को मैच टिकटों की बिक्री से भी कमाई होती. लेकिन, आख़िरकार वही हुआ, जिसका खेल प्रेमियों एवं व्यवसायियों को डर था. मैच को धर्मशाला से कोलकाता शिफ्ट किए जाने से कारोबारियों को भी करोड़ों रुपये का नुक़सान हुआ. धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान मैच को हरी झंडी दिलाने के लिए अनुराग ठाकुर ने ख़ासी मशक्कत की थी, जो प्रदेश की राजनीति के आगे बौनी साबित हुई. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पहले भारत-पाक मैच का ज़ोर-शोर से स्वागत किया, लेकिन फिर अपने तेवर बदल लिए, जिससे प्रदेश में मैच का विरोध बढ़ता गया. स्थिति यह बनी कि पाकिस्तान से एक दल सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने धर्मशाला आ पहुंचा, जिसके बाद मैच हिमाचल के हाथों से फिसल कर कोलकाता की झोली में चला गया. इस मैच का सीधा प्रसारण विश्व के 400 देशों में होना था. धर्मशाला होटल एसोसिएशन ने मैच शिफ्ट होने पर गहरी नाराज़गी प्रकट की. एसोसिएशन का कहना है कि इससे पर्यटन व्यवसाय को ख़ासा नुक़सान हुआ और हिमाचल की साख पर भी दाग लग गया. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

तय करिए, किस रास्ते जाएगा देश

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यहां का मतदाता है. 2014 में इसी मतदाता ने तय किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, 2015 में तय किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. भारतीय जनता की ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता. संघ परिवार यह व्यवस्था पसंद नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से उनके पास इतना साहस नहीं है कि वे इसका विरोध कर सकें. वे इसी व्यवस्था के तहत सत्ता में भी आना चाहते हैं और फिर इसी व्यवस्था को नुक़सान भी पहुंचाना चाहते हैं.

आने वाले मई महीने में मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लेगी. एक निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो देश की आर्थिक गति पहले जैसी है. अरुण शौरी ने ठीक कहा कि यह यूपीए–3 सरकार है, इस पर एनडीए की कोई छाप नहीं है. इस बार का बजट इसलिए थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें कृषि क्षेत्र पर कुछ ज़ोर दिया गया है, जिस पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा था. यह एक अच्छा संकेत है और बजट में जो प्रावधान हुए हैं, उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह किसानों की आय अगले छह वर्षों में दोगुनी करना चाहते हैं. यह काम सिर्फ़ दो तरीके से हो सकता है, उत्पादकता बढ़े या फिर मूल्य. उत्पादकता दोगुनी नहीं हो सकती. अगर मेहनत की जाए, तो यह दस फ़ीसद या इससे थोड़ा अधिक बढ़ सकती है, लेकिन मूल्य बढ़ाए जा सकते हैं. आप न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा सकते हैं और किसानों को उनकी फसल के लिए ज़्यादा भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएं लागू करनी होंगी.

इस सबके दो अर्थ हैं. पहला तो यह कि कृषि क्षेत्र की उन्नति होगी और ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा. लेकिन, महंगाई कम नहीं होगी. खाद्य महंगाई अपनी जगह बनी हुई है. अगर किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है, तो ज़ाहिर है कि उपभोक्ताओं को इसके लिए ज़्यादा भुगतान करना होगा. इसलिए सरकार को काफी सावधानी से काम करना होगा. दूसरी बात यह कि सरकार ने वित्तीय घाटे को पहले की घोषणा के मुताबिक तय किया है. वित्तीय घाटा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, जिसे हम तीन फ़ीसद, पांच फ़ीसदी या छह फ़ीसद बताकर काम चला लें. सवाल है कि आख़िर इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया? आख़िरकार, वित्तीय घाटा आय और व्यय के बीच का अंतर होता है. अतिरिक्त खर्च क्या है? अगर आप राजस्व के लिए अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं, तो बेकार है. लेकिन, अगर आप निवेश में खर्च करते हैं, सड़क–बांध निर्माण और उद्योग आदि में खर्च करते हैं, तो उससे हमें कुछ वापस मिलेगा. इस तरह के वित्तीय घाटे के साथ कुछ भी ग़लत नहीं है.

दुर्भाग्य से जिस यूएस मॉडल का हम अनुसरण कर रहे हैं, वह एक अनुबंध की तरह है, जो दूसरे देशों पर वित्तीय घाटा जैसी शर्तें लगा देता है. मैं समझता हूं कि रघुराम राजन आरबीआई में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय घाटा एक सरकारी निर्णय है, न कि रिजर्व बैंक का. सरकार के पास अरविंद सुब्रमण्यम के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार है. समस्या यह है कि उक्त सभी लोग एक ही माइंड सेट (एक तरह से सोचने वाले) के हैं. शिकागो डॉक्टरीन और वाशिंगटन कन्सेंस आदि सब अमेरिका की बातें हैं. हमारे यहां अपना एक थिंक टैंक होना चाहिए. प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं. विवेकानंद फाउंडेशन, जो आरएसएस एवं भाजपा से जुड़ी संस्था है, की तर्ज पर आर्थिक विकास के लिए खुद अपने यहां विकसित एक संस्था होनी चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए.

दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाइयों, मसलन रोहित वेमुला की आत्महत्या और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, से देश का विमर्श ही बदल गया. हर कोई इन्हीं मुद्दों के बारे में बात कर रहा है. कोई भी शख़्स विकास, नौकरी एवं रोज़गार आदि की बात नहीं कर रहा है. यह अच्छा संकेत नहीं है. यह सही है कि वेमुला की मौत एक बड़ी बात है, जिसे रोका जा सकता था. किसी ने भी इस मामले में समझदारी से काम नहीं लिया, न वीसी ने और न कमेटी ने. यह दु:खद है, लेकिन मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि संघ परिवार और उनसे जुड़े लोग मोदी के लिए कठिनाइयां ही पैदा कर रहे हैं. वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम. मुझे यह भी नहीं मालूम कि इससे क्या हासिल होगा. चुनाव के लिए अब सिर्फ तीन वर्ष बचे हैं. हर कोई फिर से चुना जाना पसंद करता है और पिछले छह माह में कुछ भी नहीं हुआ है. सरकार को एक ग़ैर ज़रूरी मुद्दे को, जो संघ परिवार को खुश कर सकता है कि हमने मुस्लिम या ईसाई को मजा चखाया, मुद्दा बनाकर समय बर्बाद नहीं करना चहिए. इस सबका देश और देश के विकास से कोई लेना–देना नहीं है. इसका उस नारे से भी कोई लेना–देना नहीं है, जो नरेंद्र मोदी ने दिया था कि सबका साथ–सबका विकास और जिसकी वजह से उन्हें बहुमत मिला था.

सरकार को फिर से अपने उन वादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उसने जनता से किए थे. निश्चित तौर पर सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी कुछ पहल शुरू की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके अपने ही लोग उसकी राह में बाधा डाल रहे हैं. यह दु:खद है. इसी तरह अफ़ज़ल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर यूपीए सरकार के कार्यकाल में दी गई थी. यही नहीं, उसके परिवार को सूचना तक नहीं दी गई, जो बिल्कुल एक सभ्य आचरण के ख़िलाफ़ है. लेकिन ये सब बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं. अब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं. अदालत के फ़ैसले की आलोचना करने में क्या हर्ज है? इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. ग़लत तब होगा, जब आप फ़ैसले की नीयत (मोटिव ऑफ जजमेंट) को अपनी आलोचना में शामिल करते हैं. मैं हमेशा यह बोल सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ग़लती की. इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. यह एक लोकतंत्र है. कुछ छात्र नारे लगा रहे थे, तो भाजपा को तकलीफ हुई, लेकिन उसे कश्मीर में उस पीडीपी के साथ सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं है, जिसने साफ़ तौर पर कहा कि अफज़ल गुरु की फांसी ग़लत है. आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन नारे लगाने की वजह से एक युवक को जेल में डाल देते हैं.

मैं समझता हूं कि मोदी को एक छोटे से समूह की बैठक यह फ़ैसला करने के लिए बुलानी चाहिए कि आख़िर सरकार के आदर्श और प्रतिमान क्या होंगे? क्या संविधान की आपकी व्याख्या वैसी है, जैसी कांग्रेस की थी? आपका रुख स्पष्ट होना चाहिए. अगर आप विमर्श बदलना चाहते हैं, तो बदलिए. इन मुद्दों पर एक नई बहस शुरू कीजिए. आप कहिए कि हम इस सबकी अनुमति नहीं देंगे. आप कहिए कि हम पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे. वहां राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगने दीजिए. फिर से चुनाव होने दीजिए. लोगों को तय करने दीजिए कि सरकार कौन बनाएगा. भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यहां का मतदाता है. 2014 में इसी मतदाता ने तय किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, 2015 में तय किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. भारतीय जनता की ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता. संघ परिवार यह व्यवस्था पसंद नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से उनके पास इतना साहस नहीं है कि वे इसका विरोध कर सकें. वे इसी व्यवस्था के तहत सत्ता में भी आना चाहते हैं और फिर इसी व्यवस्था को नुक़सान भी पहुंचाना चाहते हैं.

यह सब इस देश को कहीं नहीं ले जाएगा, पांच वर्ष बर्बाद हो जाएंगे. निश्चित तौर पर देश हर दिन प्रगति करता है, लोग हर दिन अपना काम करते हैं. लेकिन, जो कुछ भी हो रहा है, उस वजह से हम वह हासिल नहीं कर पाएंगे, जिसे मोदी विजन कहा जाता है. मोदी बहुत बड़ी बात करते हैं. मैं उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को बहुत पसंद करता हूं. मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूं, जब वह कहते हैं कि देश के किसानों की आय छह वर्षों में दोगुनी करना चाहते हैं. बहुत अच्छा विचार है. लेकिन, आप यह करेंगे कैसे? आप ऐसा वाशिंगटन कन्सेंस या तीन फीसद वित्तीय घाटे के साथ नहीं कर सकते. आप ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए बिना नहीं कर सकते. जितनी जल्दी सरकार अपने एजेंडे पर फोकस कर ले और विचार करे कि देश को किस रास्ते पर जाना चाहिए, अगले ढाई वर्षों में यही उसके लिए सबसे बेहतर काम होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

खाद सब्सिडी सीधे खाते में जाए

उर्वरक कंपनियां और डीलर किसानों को लूट न सकें, इसलिए आवश्यक है कि सरकार एलपीजी की भांति उर्वरक सब्सिडी भी किसानों के बैंक खाते में भेजे. खरीफ एवं रबी की बुआई का समय आते ही खाद विक्रेता डीएपी और यूरिया का कृत्रिम संकट दिखाकर काला बाज़ारी शुरू कर देते हैं. मजबूरी में किसान को महंगे दामों में उर्वरक की खरीद करनी पड़ती है.

–राज किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

सेना, सीमा और आतंकवाद

कवर स्टोरी–नेपाल सीमा पर सेना (07–13 मार्च, 2016) पढ़ी. स्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र नेपाल सीमा पर सेना की तैनाती आवश्यक है. भारत–नेपाल सीमा पर दोनों ओर मौजूद अवैध बस्तियां तुरंत हटाई जाएं. नेपाल को अपनी ज़मीन पर आतंकवादी गतिविधियां रोकनी चाहिए. भारत–नेपाल के बीच चल रहा तनाव भी अब ख़त्म हो चुका है. नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हालिया भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मतभेद दूर हो चुके हैं.

–रितेश सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

पूरे देश के प्रधानमंत्री

भारत के लोग अंधे और बहरे नहीं हैं (07–13 मार्च, 2016) शीर्षक तले अपने कॉलम में कमल मोरारका ने दो–तीन मुद्दों का खास तौर पर जिक्र किया. पढ़कर बहुत अच्छा लगा. भारतीय ट्रेनों में बहुत गंदगी रहती है. सच है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार रेलवे में है. रेल मंत्री को भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए सख्त क़दम उठाने चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि सबका साथ–सबका विकास, लेकिन भाजपा, आरएसएस एवं उनसे जुड़े अन्य संगठनों के नेता बार–बार जनता के बीच द्वेष पैदा करने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं. जेएनयू मामले में भी हमें यही देखने को मिला. जिसने भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली, उसे देशद्रोही करार दिया गया. किसी को देशद्रोही कहने से पहले भाजपा को अपने गिरेबां में झांकने की ज़रूरत है. नरेंद्र मोदी को द्वेष फैलाने वाले नेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं.

–राकेश कुमार, *बक्सर, बिहार.*

मरते किसान, सोती सरकार

जब तोप मुक़ाबिल हो–किसानों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए (07–13 मार्च, 2016) ने बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने किसानों का दर्द जिस तरह बयां किया, वह काबिले तारीफ़ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों एवं ग़रीबों का जिक्र करके उनके दु:ख–दर्द दूर करने की बात करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं आपके वादों पर सवाल खड़े करती हैं. वर्ष 2015 में महाराष्ट्र में 3,228 किसानों ने आत्महत्या की. महाराष्ट्र और केंद्र, दोनों जगह आपकी (भाजपा) सरकार है. अब आप इन मौतों का ठीकरा राज्य सरकार के सिर फोड़कर बच नहीं सकते. विडंबना देखिए, एक तरफ़ पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ चंद हज़ार रुपये का कर्ज अदा न कर पाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है.

–मानसी कोचर, *पालम, नई दिल्ली.*

आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग

आलेख–इराक, क्या था और क्या हो गया (07–13 मार्च, 2016) पढ़ने के बाद यह ग़लतफहमी दूर हो गई कि इराक में शिया–सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं. वहां शिया–सुन्नी मिलकर आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, यह जानकर काफी खुशी हुई. जिस तरह इराक में शिया–सुन्नी एकजुट होकर आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उसी तरह दुनिया भर के शिया–सुन्नी अपने सारे मतभेद भुलाकर ग़रीबी और आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ें, यही वक्त की मांग है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है और मानवता का दुश्मन है.

–शाहिद इकबाल, *छपरा, बिहार.*

देशद्रोह का आरोप ग़लत

जेल से रिहा होने के बाद जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जो भाषण दिया, उसकी देश–दुनिया में चर्चा हो रही है. कन्हैया ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा. किसी छात्र को बिना तथ्यों की जांच किए देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज देना आख़िर किस दृष्टि से न्यायसंगत है? जेएनयू प्रकरण में पहले सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए. लेकिन, छात्रों को भी अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए.

–निशांत यादव, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स–आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख–कान–नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव–विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

माल्या की फरारी के लिए ज़िम्मेदार कौन

> जिस शख़्स के ऊपर नागरिक उड्डयन मंत्रालय या सरकार का इतना कर्ज हो, वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य बन गया! ऐसे में सरकारी कंपनियां उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकती थीं? और, यह सब तत्कालीन सरकार की जानकारी में हुआ. दूसरी सरकार आई. उसने जब पैसे वसूलने का मन बनाया या एनपीए की सूची बनानी शुरू की, तब उसे समझ में आया कि उसके भी दोस्त इस कतार में हैं. लिहाजा बैंकों से कहा गया कि वे अपनी वसूली की तैयारी करें.

विजय माल्या विदेश चले गए. बहस होती रही, बैंक सीबीआई को ख़बर करते रहे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट चले गए कि विजय माल्या को विदेश जाने से रोका जाए. लेकिन, लगता है कि सबने मिलकर विजय माल्या को इस देश से बाहर जाने में मदद की. वित्त मंत्रालय के अधिकारी और खुद वित्त मंत्री विजय माल्या के सबसे घनिष्ठ दोस्तों में हैं. विजय माल्या बीते दो मार्च की रात विदेश चले गए, ऐसा सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है.

विजय माल्या के ऊपर 7,000 करोड़ रुपये का सरकारी कर्ज है, जिसे बैंकों ने कहा है कि वसूला नहीं जा सकता. विजय माल्या के ऊपर इस 7,000 करोड़ के कर्ज को राजनीतिक तौर पर प्रचारित भी किया गया. लेकिन, जब यह कर्ज चढ़ रहा था और किंगफिशर डूब रही थी, उस समय न सरकार चेती, न बैंक चेते, न सीबीआई चेती. सरकारी बैंकों ने जो 1.14 लाख करोड़ रुपये एनपीए में डाले हैं और एक तरीके से उन्हें माफ़ कर दिया है, उनमें कुछ प्रमुख नाम उन उद्योगपतियों के हैं, जो सरकारी पैसे को अपना पैसा समझते हैं. भूषण स्टील के ऊपर 40 हज़ार करोड़, एस्सार स्टील के ऊपर 30 हज़ार करोड़, एबीजी शिपयार्ड के ऊपर 11 हज़ार करोड़, भारती शिपयार्ड पर 8,000 करोड़, किंगफिशर एयरलाइंस यानी विजय माल्या के ऊपर 7,000 करोड़, होटल लीला के ऊपर 4,500 करोड़, विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी के ऊपर 3,200 करोड़, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया पर 2,600 करोड़, ज़ूम डेवलपर के ऊपर 1,810 करोड़, स्टर्लिंग बायोटेक के ऊपर 1,732 करोड़, एस कुमार्स नेशनवाइड के ऊपर 1,692 करोड़ और सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर 1,446 करोड़ रुपये बकाया हैं.

सीबीआई या बैंक इन कंपनियों के बारे में खामोश हैं और सिर्फ़ विजय माल्या का नाम तोते की तरह रट रहे हैं. यह भी एक तरीका है कि सबको बचा लो, किसी एक के ऊपर सारी जांच केंद्रित कर दो और फिर उसे भी देश से बाहर निकाल दो. 1.14 लाख करोड़ रुपये जनता के पैसे हैं, लेकिन इसकी चिंता किसे है? इन सारे लोगों के ऊपर जब एनपीए बढ़ रहा था, तब किसी का ध्यान नहीं गया. इनमें से कई लोग, खासकर विजय माल्या शौकीन और रंगीन पार्टियां देने के लिए मशहूर रहे हैं. माल्या का चाहे बेंगलुरु स्थित घर हो या गोवा स्थित, दोनों ही राजनेताओं एवं नौकरशाहों के सर्वाधिक सुप्रसिद्ध मनोरंजन के स्थान हैं. वहां जो लोग जाते थे, वे कांग्रेस के भी बड़े नेता होते थे और विपक्ष के भी. विपक्ष के जो नेता उन पार्टियों में जाते थे, आज वे भारत सरकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री हैं. कैसे मान लें कि सरकारी पैसे की कोई वसूली हो पाएगी, क्योंकि राजनीतिक इच्छाशक्ति पैसा वसूलने के ख़िलाफ़ है और इस मसले में मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी और तथाकथित विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं आपस में समझौता है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमेशा खामोश रहते थे. जिन कुछ अवसरों पर उन्होंने मौन तोड़ा, उनमें एक मौक़ा किंगफिशर एयरलाइंस को बेलआउट पैकेज देने का भी रहा. उन्होंने कहा कि हम किंगफिशर को डूबने से बचाने के लिए कुछ उपाय करेंगे और उसके बाद तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री वयालार रवि ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ मिलकर इसके रास्ते निकालने शुरू किए. उनके निर्देश पर तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय मुरली देवड़ा एवं जितेंद्र प्रसाद ने सरकारी बैंकों के साथ बैठकें शुरू कीं. नतीजा यह हुआ कि 900 करोड़ रुपये बकाया होने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने विजय माल्या के हवाई जहाजों में ईंधन भरना शुरू कर दिया. उनके दबाव से एयरपोर्ट अथॉरिटी

> अगर आप अर्थव्यवस्था और देश के प्रति जरा भी ईमानदार हैं, तो कम से कम इस बात पर शर्म कीजिए कि 25 हज़ार रुपये से लेकर सवा लाख रुपये तक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर एक किसान आत्महत्या कर लेता है और हज़ारों करोड़ रुपये डकारने वाले पूंजीपति ऐश करते रहते हैं, उनके दरवाजे पर एक नोटिस भी नहीं चिपकता.

ने विजय माल्या से ग्राउंड टैक्स नहीं वसूला, तेल कंपनियों ने अपना पैसा नहीं वसूला और विजय माल्या की एयरलाइंस सरकारी पैसे से उड़ती रही. उन्हें जो बेलआउट पैकेज मिला, वह सारा पैसा इस देश या सरकारी हाथों से, जनता के हाथों से निकल कर विजय माल्या की संपत्ति बन गया.

विजय माल्या के बारे में हम इतना सब कुछ इसलिए जानते हैं, क्योंकि उन्हें तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य बनवा दिया. जिस शख़्स के ऊपर नागरिक उड्डयन मंत्रालय या सरकार का इतना कर्ज हो, वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य बन गया! ऐसे में सरकारी कंपनियां उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकती थीं? और, यह सब तत्कालीन सरकार की जानकारी में हुआ. दूसरी सरकार आई. उसने जब पैसे वसूलने का मन बनाया या एनपीए की सूची बनानी शुरू की, तब उसे समझ में आया कि उसके भी दोस्त इस कतार में हैं. लिहाजा बैंकों से कहा गया कि वे अपनी वसूली की तैयारी करें. तब बैंकों ने कहा कि हम वसूल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस कंपनी को हमने कर्ज दिया है, उसके पास कोई एसेट्स नहीं है. कमाल की बात यह कि जब राजनीतिक तौर पर विजय माल्या को चुना गया, तो उनके दोस्तों, जो मौजूदा सरकार में असरदार मंत्री हैं, ने उनके देश से बाहर जाने के रास्ते साफ़ कर दिए. यह हमारा आरोप नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा. वरना यह कैसे हो सकता है कि देश का पैसा हज़म करने वाला शख़्स विदेश चला जाए और सीबीआई देखती रह जाए, बैंक देखते रह जाएं, सरकार देखती रह जाए. यहीं पर समझ में आता है कि आप न पठानकोट कांड के मुलजिमों को पकड़ सकते हैं, न देश के ख़िलाफ़ साज़िश रचने वालों को पकड़ सकते हैं. आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बोल सकते हैं.

यह आरोप नहीं, दर्द है. यह दर्द हम इसलिए बयान कर रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या के अलावा जो लोग इस सूची में शामिल हैं, उनके नाम किसी टेलीविजन चैनल या अख़बार ने प्रमुखता से नहीं बताए–छापे हैं. भूषण स्टील 40 हज़ार करोड़ रुपये और एस्सार स्टील 30 हज़ार करोड़ रुपये लेकर बैठी हुई है, लेकिन उनसे उक्त कर्ज वसूलने की कोई योजना सरकार के सामने नहीं आई है. आख़िर क्यों नहीं सरकार एक क़ानून बनाकर उनकी दूसरी कंपनियों एवं प्रमोटर्स की व्यक्तिगत एसेट्स जब्त करती है, ताकि देश का पैसा वसूल हो सके और आगे से कोई शख़्स सरकार या देश को चूना लगाकर, धोखा देकर पैसा खाने की हिम्मत न करे. इस मामले में हमारे विपक्षी भाई और सत्ताधारी भाई दोनों एकराय हैं कि ऐसा कोई क़ानून नहीं बनना चाहिए. यह सारा पैसा वसूलने के लिए संसद में अब तक कोई बहस नहीं हुई. संसद में उन सवालों के ऊपर बहस होती है, उन सवालों के ऊपर संसद स्थागित होती है, जो नॉन इश्यू हैं. लेकिन, जो इश्यू हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, वे इस संसद की चिंता का विषय नहीं हैं. कारण फिर वही हो सकता है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद सत्तापक्ष एवं विपक्ष के लोगों को यह पैसा खाने वाले लगातार उपकृत करते रहे हैं. यह आरोप हम पुन: परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लगा रहे हैं.

हमारा आग्रह सरकार से है, हमारा आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है. अगर आप अर्थव्यवस्था और देश के प्रति जरा भी ईमानदार हैं, तो कम से कम इस बात पर शर्म कीजिए कि 25 हज़ार रुपये से लेकर सवा लाख रुपये तक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर एक किसान आत्महत्या कर लेता है और हज़ारों करोड़ रुपये डकारने वाले पूंजीपति ऐश करते रहते हैं, उनके दरवाजे पर एक नोटिस भी नहीं चिपकता. किसानों द्वारा आत्महत्या को अनदेखा मत कीजिए प्रधानमंत्री जी. किसानों की मौत आपके माथे पर एक बदनुमा दाग है. जितना पैसा आपकी सरकार या आपसे पहले की सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले किया है, उसका अगर आधा हिस्सा भी आपने किसानों के लिए आवंटित कर दिया होता, तो आत्महत्याएं रुक सकती थीं, किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली की झलक दिखाई पड़ सकती थी. कम से कम आत्महत्या तो नहीं होती. क्या यह देश कॉरपोरेट बनाम किसान की लड़ाई की तरफ़ जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, सोचिए. ■

editor@chauthiduniya.com

भाजपा का भविष्य तय करने वाला बजट

मेघनाद देसाई

हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे कठिन समय वह होता है, जब उसे चांसलर द्वारा दिए गए बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है. यही नहीं, अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी के साथ–साथ उसमें ज़बरदस्त राजनीतिक सूझबूझ भी होनी चाहिए. अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए आम बजट में कोई खामी निकालना किसी भी विपक्षी नेता के लिए आसान नहीं था. ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं राजनीति से प्रेरित थीं. तमाम बहसें शहरी क्षेत्र की मांगों, औद्योगिक क्षेत्र की ज़रूरतों और बैंकों के एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) पर केंद्रित थीं. जेएनयू मुद्दे पर सरकार घिरी हुई दिख रही है, इसलिए उसे इस बजट में आर्थिक मसलों का उचित हल देना था. दरअसल, राजनीतिक तौर पर जहां यह बजट चतुराई भरा था, वहीं आर्थिक रूप से भी स्वस्थ था. कश्मीर की आज़ादी के नारे और अफ़ज़ल गुरु पर केंद्रित हंगामे के बीच बहस का रुख दो वर्षों से सूखे का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ़ मोड़ दिया गया. विरले ही कोई बजट भाषण ग्रामीण भारत से शुरू हुआ और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित रहा हो. भारतीय जनता पार्टी

के बारे में आम धारणा यह है कि वह शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों की पार्टी है. वित्त मंत्री के बजट भाषण ने यह धारणा बदल दी.

> बजट की नौ सूत्री वरीयता सूची में महिला स्वास्थ्य को भी स्थान दिया गया है. उन्हें धुआंयुक्त चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए एलपीजी कनेक्शन देने की बात कही गई है. पूर्ववर्ती बजटों में आम तौर पर महिलाओं की समस्याओं को लेकर चिंता नहीं होती थी. मानव संसाधन विकास सूचकांक पर भारत का रिकॉर्ड निराशाजनक इसलिए है, क्योंकि 1991 के बाद भी महिला कल्याण कभी अग्रणीय मुद्दा नहीं रहा.

अर्थव्यवस्था की दशा–दिशा का अंदाज़ा लगाना वित्त मंत्री के लिए एक पेचीदा मसला था. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा आर्थिक आंकड़ों के संशोधन ने भी भ्रम पैदा किया. उनसे जो इशारे मिल रहे थे, वे विरोधाभासी थे. सवाल यह है कि क्या भारत जी–20 देशों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था है? अगर ऐसा है, तो निर्यात और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों का रुख नीचे की तरफ़ क्यों है? क्या अर्थव्यवस्था को गति देने की ज़रूरत है या उसकी चाल ठीक है? ये फ़ैसले जितने राजनीतिक हैं, उतने ही आर्थिक भी. दरअसल, इन सवालों का जवाब हां में भी है और न में भी. कुल मिलाकर स्थिति ठीक है, लेकिन फिलहाल शहरी क्षेत्रों या औद्योगिक मंदी से बड़ा संकट गांव का संकट है. ऐसे में अधिक ज़ोर गांव की ज़रूरतों, कल्याण और उत्पाद पर होना चाहिए था. एक लंबे समय से यहां संरचनागत सुधार की ज़रूरत थी. जल संसाधनों में लंबे समय से महसूस की जा रही गिरावट (जिसे लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा था) पर ध्यान देना था. ग्रामीण सड़क निर्माण की ज़रूरत थी. यह ज़िम्मेदारी पंचायतों को देने से इसकी मांग बढ़ गई थी. वर्षों की बहस के बाद फसल बीमा योजना लागू करनी थी.

बजट की नौ सूत्री वरीयता सूची में महिला स्वास्थ्य को भी स्थान दिया गया है. उन्हें धुआंयुक्त चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए एलपीजी कनेक्शन देने की बात कही गई है. पूर्ववर्ती बजटों में आम तौर पर महिलाओं की समस्याओं को लेकर चिंता नहीं होती थी. मानव संसाधन विकास सूचकांक पर भारत का रिकॉर्ड निराशाजनक इसलिए है, क्योंकि 1991 के बाद भी महिला कल्याण कभी अग्रणीय मुद्दा नहीं रहा. महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या बजट घाटे का लक्ष्य शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तोड़ा जाना चाहिए. इसका जवाब यह है कि अगर अर्थव्यवस्था जी–20 में उच्चतम दर से बढ़ रही है, तो उसमें और अधिक ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. बैंकों के बैड लोन्स का मामला बुनियादी ढांचे का निवेश बढ़ाकर सुलझाया जा सकता है. इसके लिए नियत व्यवस्था में छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं थी. तथाकथित नव मध्य वर्ग को यह अवगत कराना था कि देश में कुछ और लोग भी हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है.

वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा जोखिम भरा है. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विदेशी निवेश से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी. यह बर्बादी फिलहाल दो प्रतिशत है. सिंचाई की उपलब्धता से छोटे और बड़े काश्तकारों के खेतों की पैदावार में इजाफ़ा होगा. इससे उपभोक्ता खाद्यान्न की जो क़ीमत देता है और किसान को जो पैसा मिलता है, उसके बीच का फासला कम होगा. इन सब बातों के बावजूद कृषि एक ऐसा जुआ है, जो बेहतर मानसून और सूखे से बचाव पर निर्भर है. भाजपा का पुनर्निर्वाचन भी इसी पर निर्भर करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सिमोन के हौसले को सलाम

झारखंड

कुमार कृष्णन

झारखंड की राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर स्थित है बेड़ो प्रखंड. यहां खस्सी टोली की जामटोली पहाड़ी की तलहटी के निचले क्षेत्रों में एक शख्स पिछले सात दशक से प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझता आ रहा है. अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, जीवन के प्रति असीम आस्था और प्रकृति से मिले व्यवहारिक ज्ञान के बल पर उन्होंने बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया. अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने अपनी ग्रामीण तकनीक से जल प्रबंधन और वन संरक्षण को नया आयाम दिया. किसी पर्यावरणविद् तथा कृषि वैज्ञानिक जैसी गहरी सोच रखने वाला यह शख्स, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है. वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. 84 वर्षीय पड़हा राजा सेमोन उरांव को पूरे क्षेत्र में सेमोन बाबा के नाम से जाना जाता है.

15 मई, 1932 को पड़हा राजा बेड़ा उरांव के घर जन्मे सिमोन ने होश संभालते ही अपने को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से घिरा पाया. मजह दस वर्ष की उम्र में अपनी बंजर जमीन में सबसे पहले शकरकंद की खेती की. इसके बाद दूसरी फसलें लगानी शुरू की. फसल बेचने से मिले पैसों से उनका उत्साह बढ़ा. जामटोली पहाड़ी के निकट दूर-दूर तक ज़मीन पथरीली और बंजर थी. ऊंची-नीची इस भूमि पर खेती करना संभव नहीं था. सिमोन के परिवार वालों के पास कुल 11 एकड़ ज़मीन थी, वह भी उबड़-खाबड़, नदी-नालों और कटीली झाड़ियों से भरी पड़ी थी. जामटोली पहाड़ी में एक नाला बहता था, यहां संकरे-गहरे नाले को झरिया नाला कहा जाता है. महज 15 वर्ष की उम्र में सिमोन ने झरिया नाला को बांधने का साहसिक निर्णय लिया. अपने पिता की प्रेरणा से कुछ ग्रामीणों के साथ वह इस अभियान में जुटा. शुरूआत में कटीली झाड़ियों से घिरी पथरीली ज़मीन पर कुदाल चलाना मुश्किल साबित हुआ. कई दिनों के बाद सफलता हाथ लगी और एक छोटा बांध बनकर तैयार हुआ. लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. लेकिन जैसे ही बरसात आई बांध टूटकर बह गया. सिमोन ने हार नहीं मानी और ग्रामीणों की मदद से दोबारा प्रयास किया और दूसरी जगह बांध बनाने का निर्णय लिया. लेकिन बांध बारिश के कारण फिर टूट गया. इस बार सिमोन ने फिर हिम्मत नहीं हारी और खड़बागड़ा नाले को ग्रामीणों की मदद से बांधा गया. बांध बनने के बाद उसमें 21 फीट पानी था.

उनके अथक प्रयास के बाद बांध के आसपास की ज़मीन खेती के लायक बनती गई. सिमोन ने बैल तथा भैंसे की मदद से जमीन को समतल बनाया. बंजर जमीन तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सिमोन के प्रयास से आसपास लगभग सत्तर एकड़ जमीन खेती के लायक बनी. सिर्फ नेरपतरा के निकट 17 फीट गड्ढे में मिट्टी भरकर दस एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाया. डोंकटाड़ नाला तथा अंतबालू नामक स्थान पर बीस एवं सत्ताइस फीट गहरे नाले एवं गड्ढे नाले को सिमोन ने ऊपरी बंजर भूमि को काटकर अत्यंत परिश्रम से मिट्टी से भरा और लगभग 12 एकड़ जमीन खेती के लायक बनाई. खाबड़गढ़ा के निकट गहरे खड़नुमा जमीन में 23-23 फीट मिट्टी डाली और सात एकड़ भूमि को खेती के लायक बनाया. इस तरह बंजर भूमि को खेती के लायक बनाने का सिलसिला जारी रहा. मिट्टी संरक्षण विभाग ने अलग-अलग किस्तों में 14 हजार एवं 16 हजार रुपये ग्रामीणों को सहायता स्वरूप दिए एए.

जमीन तो खेती के लायक बनती गई लेकिन हर बरसात में बांध टूटते गए. उन्होंने ग्रामीणों के मनोबल को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि हार मानने से काम नहीं चलेगा. उनकी प्रेरणा और हिम्मत से ग्रामीण प्रभावित थे. बैर टोली, हरिहरपुर, जामटोली, खस्सी टोली के ग्रामीणों

आज सिमोन के प्रयास से सात गांवों की लगभग तीन सौ एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है. सिमोन उरांव झारखंड के संभवत: पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन से पहले जंगल बचाओ अभियान चलाया. सिमोन उरांव को हरियाली तथा जंगलों से बहुत गहरा लगाव है.

के साथ गांव में बैठक आयोजित की. ग्रामीणों ने यह विचार किया कि एक व्यक्ति अकेला इतना कुछ कर सकता है तो यदि सभी मिलकर साथ दें तो क्षेत्र में हरित क्रांति आ सकती है. ग्रामीणों ने सोचा कि जहां दिन में बारिश होती है और दोपहर बाद बिलकुल सूख जाती है ऐसी बंजर जमीन के लिए यदि सिंचाई का उचित प्रबंध किया जाए तो यहां की उपज से सैकड़ों परिवारों को दो वक्त की रोटी मिल सकती है. बैठक में सिमोन उरांव के अलावा बैर टोली के सुका ताना भगत, पोगरो उरांव, तोता उरांव हरिहरपुर जामटोली के चेगे उरांव, बुधवा उरांव सहित दर्जनों लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि आसपास के खेतों को सालों भर पानी चाहिए तो चेक डैम से बड़े बांध की आवश्यकता होगी.

सिमोन उरांव के व्यक्तिगत प्रयास का फल था कि उससे प्रेरित होकर गांव वाले एकजुट हुए और 1961 में झरिया नाला के गायघाट के पास एक बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ. नौ वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह बांध बनकर तैयार हुआ. यह कोई आसान काम नहीं था. तीन गांवों के तीन सौ ग्रामीणों ने इस बांध के निर्माण कार्य में श्रमदान किया. बांध के निर्माण के क्रम में वर्ष 1967 में जल के तेज बहाव से बांध क्षतिग्रस्त हुआ. सिमोन उरांव ने पानी के अंदर रहकर बांध की मरम्मत की. तकरीबन 15 मिनट पानी के अंदर रहने की वजह से सिमोन का दम घुटने लगा लगा था. गांव वाले काफी चिंतित हो गए थे, लेकिन सिमोन की जान बच गई और वे सकुशल बाहर आ गए. लगभग 49 फीट ऊंचा बांध बनकर तैयार हो गया. लेकिन उनके पिता बांध से होने वाली सिंचाई नहीं देख पाए. 1970 में उनका निधन हो गया.

गायघाट के निर्माण में ग्रामीणों को कैथोलिक बैंक, कैनरा बैंक तथा प्रखंड मुख्यालय से ऋण भी लेना पड़ा. इसके बाद सिमोन उरांव ने खस्सी टोला के निकट छोटा झरिया नाला में 1975 में एक नए बांध का निर्माण किया. झरिया नाला बांध 27 फीट ऊंचा बांधा गया. सिमोन के प्रयास से ग्रामीणों ने झरिया नाला बांध में एकजुट होकर श्रमदान किया. सिमोन सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए सदैव तत्पर रहते थे. सिमोन सरकार और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम करते थे. सिमोन के प्रयास से ही 80 के दशक में हरिहरपुर जामटोली के निकट गायघाट बांध के ऊपरी इलाके में देशवाली बांध का निर्माण किया. चार लाख रुपये की लागत से बना यह बांध लघु सिंचाई योजना से निर्मित है. यह इस क्षेत्र में सिमोन के प्रयास से बना तीसरा बड़ा बांध है. बांधों के निर्माण में लुइसा उरांव, हौवा उरांव, कमली उरांव, जोसेफ मिंज, बुधवा बुन्नु उरांव, किशनु तथा गड़ेद्रा उरांव की लगभग आठ एकड़ जमीन डूबी. वन विकास समिति के माध्यम से सिमोन उरांव ने ग्रामीणों की डूबी जमीन के एवज में उन्हें दूसरी जगह जमीन मुहैया करा दी. गायघाट के ग्रामीणों की मदद से सिमोन ने साढ़े पांच हजार फीट लंबी कच्ची नहर निकाली. सिमोन के प्रयास से ही सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 1500 फीट लंबी नहर का पक्कीकरण कराया गया.

वर्ष 1977-78 के भीषण अकाल के कारण ग्रामीणों की हालत आर्थिक रूप से बहुत गंभीर हो गई थी. गाल के जानवरों के लिए भी चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. किसी के खेत में एक मन धान भी नहीं उपज पाया था. ग्रामीण पलायन करने के बारे में सोच रहे थे. सिमोन उरांव ने लोगों को यह कहते सुना कि हम अपने मवेशियों को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, सिमोन ने एक तरकीब निकाली. उसने कृषि वन विकास समिति के माध्यम से प्रखंड कार्यालय से पंप खाद, बीज, किर्लोस्कर मशीनें खुरहा टोली के ग्रामीणों को दे दी तथा ग्रामीणों को सामूहिक रूप से गेहूं की खेती करने का निर्देश दिया. इस वर्ष लगभग 250 एकड़ भूमि में ग्रामीणों ने एकजुट होकर गेहूं लगाया. इसका नतीजा साकारात्मक रहा. 150-150 मन गेहूं का उत्पादन किया गया.

आज सिमोन के प्रयास से सात गांवों की लगभग तीन सौ एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है. सिमोन उरांव झारखंड के संभवत: पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन से पहले जंगल बचाओ अभियान चलाया. सिमोन उरांव को हरियाली तथा जंगलों से बहुत गहरा लगाव है. सिमोन ने अपनी कृषि वन विकास समिति तथा ग्रामीणों की मदद से 258 एकड़ जंगल की वैज्ञानिक तरीके से रक्षा की. उन्होंने 1967-68 में रेतीली जमीन में खरवागढ़ तथा रूगड़ीटांड में सरई के बीज डालकर जंगल लगाया.

सिमोन वर्तमान में सब्जी उत्पादन में व्यस्त हैं. उन्होंने मधुमक्खी पालन और सब्जी उत्पादन के नए तौर तरीकों के साथ युवाओं के स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा किए हैं. पड़हा के माध्यम से सिमोन उरांव ने सिर्फ बेड़ो प्रखंड ही नहीं बल्कि करां लापुंग और रातु प्रखंड के कई गांवों में शांति बहाल करने, गांव के झगड़े गांव में ही पड़हा के माध्यम से सुलझाने तथा दूसरों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. देश-विदेश से अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसंधानकर्ता, सरकारी पदाधिकारी इनके कामों को देखने आते हैं. सिमोन उरांव को झारखंड में असीम संभावना दिखाई देती है. 84 वर्ष की उम्र में भी उनमें युवाओं जैसी ऊर्जा और फूर्ति है. उन्होंने देश और व्यवहारिक ज्ञान की बल पर एक मिसाल कायम की है.■

feedback@chauthiduniya.com

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

फिर नक्सली आग में जलेगा जहानाबाद!

अस्सी के दशक में गया जिले का अनुमंडल जहानाबाद नक्सली गतिविधियों की आग में जल रहा था. बीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में जहानाबाद एक दर्जन से अधिक नरसंहारों का गवाह बना, जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए. पहला नरसंहार वर्ष 1980 में परस बिगहा में हुआ और अंतिम साल 2000 में रामपुर में हुआ. 1980 से 2000 के बीच कंसारा, अरवल, नोन्हीं नगमा, शंकर बिगहा, नारायणपुर, दमुआखगड़ी, सेनारी, लक्ष्मणपुर बाथे, मियांपुर जैसे बड़े-बड़े नरसंहार हुए.

सुनील सौरभ

पिछले एक दशक से विकास की ओर अग्रसर मगध प्रमंडल के जहानाबाद जिले को एक बार फिर लाल भूमि में तब्दील करने का प्रयास प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) ने शुरू कर दिया है. 27 फरवरी, 2016 को जहानाबाद जिले में हथियारों और नक्सली साहित्य के साथ पकड़े गए एरिया कमांडर गर्जेंद्र यादव सहित चार माओवादियों ने पुलिस के समक्ष इस बात का खुलासा किया. अस्सी के दशक में गया जिले का अनुमंडल जहानाबाद नक्सली गतिविधियों की आग में जल रहा था. बीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में जहानाबाद एक दर्जन से अधिक नरसंहारों का गवाह बना, जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए. पहला नरसंहार वर्ष 1980 में परस बिगहा में हुआ और अंतिम साल 2000 में रामपुर में हुआ. 1980 से 2000 के बीच कंसारा, अरवल, नोन्हीं नगमा, शंकर बिगहा, नारायणपुर, दमुआखगड़ी, सेनारी, लक्ष्मणपुर बाथे, मियांपुर जैसे बड़े-बड़े नरसंहार हुए.

साल 1986 में हुए कंसारा नरसंहार के बाद जहानाबाद को पूर्ण जिला का दर्जा दिया गया, ताकि विकास के सहारे कानून व्यवस्था को ठीक रखते हुए नक्सली वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके. जिला बनने के बाद भी जहानाबाद में नक्सली वारदातों में कोई कमी नहीं आई. दमुआ खगड़ी नरसंहार के बाद जहानाबाद पहुंचे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के मुंह पर वीरेन्द्र विद्रोही नाम के एक युवक ने कालिख लगा दी थी. उस वक्त इस बात की चर्चा पूरे देश में बड़ी

जोरशोर से हुई थी कि जहानाबाद के लोग नक्सली आग में जल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री के चेहरे पर कालिख लगाना इसी विरोध का परिणाम है. उस दौर में जहानाबाद जिले में 6 इंच छोटा करने का नक्सलियों का जुमला बेहद चर्चित हुआ करता था, क्योंकि नरसंहारों में नक्सली तेज़ हथियार से निर्दोष या चिन्हित लोगों के सिर को धड़ से अलग कर देते थे. उस वक्त प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्सवार ग्रुप और डॉ विनियन की मजदूर किसान संग्राम समिति जहानाबाद और अरवल में ज्यादा सक्रिय थी. नक्सली कार्रवाई और अधिक बढ़ने लगी तो अरवल को भी जहानाबाद से अलग एक नया जिला बना दिया गया. साल 2000 के बाद घोर नक्सल प्रभावित जहानाबाद और अरवल जिले में नक्सली कार्रवाई कम होने लगी. वर्ष 2005 में बिहार में आई नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने और नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया तो नक्सली वारदातों में काफी हद तक कमी आ गई. जहानाबाद, अरवल विकास के रास्ते शांति की ओर आगे बढ़ता रहा.

पिछले दस सालों से जहानाबाद और अरवल के लोग शांति से अपने-अपने कारोबार में जुटे हैं. लेकिन हाल ही में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) ने जहानाबाद में नए सिरे से अपने संगठन का विस्तार कर लेवी वसूलने और फरमान नहीं मानने वाले को 6 इंच छोटा करने का अभियान शुरू किया है. इस बात का खुलासा पाली थाना क्षेत्र के टिंवलपुर गांव में 27 फरवरी, 2016 को गिरफ्तार किए गए माओवादी कमांडर सहित चार नक्सलियों ने किया है. इन नक्सलियों के पास से कार्बाइन, पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल तथा नक्सली साहित्य बड़ी संख्या में जब्त किए गए हैं. माओवादियों ने बताया कि भदसारा गांव में निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन को जलाने की उनकी योजना थी. ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड नामक कंपनी ने पॉवर सब स्टेशन का सागरपुर-धराड़ा में निर्माण किया है. भदसारा में निमार्ण कार्य चल रहा है. माओवादियों ने कंपनी से लेवी की मांग की थी. लेवी नहीं देने पर निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन को आग के हवाले करने की उनकी योजना थी. इसी दौरान पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की गिरफ्त में आए माओवादी कमांडर गर्जेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि संगठन ने ईंट भट्ठा मालिकों और विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों व निर्माण एजेंसियों से लेवी वसूलने के लिए नया तरीका अपनाया है. उनके साथ शामिल हुए नए लोगों को संगठन में शामिल कर उन्हें छोटे-छोटे क्षेत्रों में लेवी वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसी योजना के तहत सभी लोगों को उनके क्षेत्रों में निर्माण कार्य कर रही कंपनियों और भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने का काम दिया गया था. हाल ही में तकरीबन 70 लोगों को लेवी वसूलने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली कर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा भी दिया गया है. गिरफ्तार माओवादियों ने बताया कि इससे पूर्व बरावां स्थित पाईन निमार्ण कार्य में लगी जेसीबी को लेवी नहीं देने के कारण जला दिया गया था. सेवनन में पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया गया. रुस्तमपुर में भागवत शर्मा के खेत में लगी धान की फसल आग के हवाले करने में भी इन माओवादियों की संलिप्तता थी. पुलिस की गिरफ्त में आए माओवादियों ने बताया कि ग्रुप में शामिल हुए नए लोगों को लेवी वसूलने तथा अन्य तरह की ट्रेनिंग गया जिले के जंगल में दी गई थी. माओवादी एरिया कमांडर गर्जेंद्र यादव ने 13 नवंबर, 2005 की रात जहानाबाद में हुए जेल ब्रेक कांड में शामिल होने की बात स्वीकार की है. इन माओवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस जब पाली थाना क्षेत्र के टिंवलपुर गांव में दबिश देने पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने माओवादियों का मुस्तैदी के साथ सामना करते हुए उन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. पूछताछ के बाद अन्य स्थानों से भी कई माओवादियों को पकड़ा गया है. पुलिस के अनुसार माओवादियों से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि जहानाबाद को माओवादी एक बार फिर जहानाबाद और उसके आस-पास अपने आधार को मजबूत करने में जुटे हैं. पुलिस का मानना है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेरोजगार युवकों के लिए सरकार कोई योजना नहीं बनाती है तो ऐसे ग्रामीण युवक राह भटककर माओवादी संगठनों में शामिल हो सकते हैं. इस वजह से जहानाबाद जिला एक बार फिर से नक्सली ताकतों के आगोश में जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय और वामपंथ का पुराना नाता है

बेगूसराय और उसके आस-पास के इलाके में कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह ने वामपंथ की नींव रखी थी. बिहार केपहले मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह की कैबिनेट के मंत्री रामचरित्र सिंह के बेटे चंद्रशेखर सिंह ने अपने पिता से बगावत कर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया था. एक दौर था जब बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ था, इसी वजह से बेगूसराय को मिनी मॉस्को भी कहा जाता था.

नवीन चौहान

राजधानी दिल्ली से लगभग एक हजार किमी की दूरी पर स्थित बिहार का बेगूसराय जिला हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में रहा. बेगूसराय के एक गरीब भूमिहार परिवार से संबंध रखने वाले कन्हैया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडेरेशन(एआईएसएफ) से ताल्लुक रखते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की छात्र इकाई है. बेगूसराय और वामपंथ का बहुत पुराना नाता रहा है. एक समय इसे मिनी मॉस्को के नाम से भी जाना जाता था. बिहार में वामपंथ ने यहीं से अपने पैर पसारे, लेकिन आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई में जुटा हुआ है. कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप लगने, उनके जेल जाने और फिर जमानत पर रिहा होने के घटनाक्रम में वापपंथी दलों को कन्हैया में वामपंथ की वापसी के लिए आशा की किरण नज़र आई है. लेकिन क्या कन्हैया बिहार में वामपंथ को फिर से स्थापित कर पाएंगे? क्या मिनि मॉस्को अपने अतीत की बुलंदियों को एक बार फिर हासिल कर पाएगा ?

पिछले एक महीने में कन्हैया छात्र नेता से राष्ट्रीय नेता बन गए. सीपीआई सहित अन्य दलों की नज़रें कन्हैया कुमार पर टिकी हुई हैं. हर कोई इस युवा नेता को अपने दल में शामिल करना चाहता है और जेएनयू प्रकरण का राजनीतिक लाभ लेना चाहता है. सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी तो कन्हैया के आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों के लिए प्रचार करने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश पहली बार लेफ्ट के युवाओं की ताकत देख रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कन्हैया कुमार समेत वो सभी कार्यकर्ता जो लेफ्ट का समर्थन करते हैं, पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों का प्रचार करेंगे. कन्हैया के बंगाल चुनाव प्रचार में उतरने की खबर पर प्रतिक्रिया देत हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कन्हैया के चुनाव प्रचार में उतरने से बंगाल चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनका कहना है कि जिन नारों के बल पर कन्हैया हीरो बना है वही नारे बंगाल में वापमंथी दलों को सता रहे हैं. बंगाल में ये सभी परेशानियों तीन दशक लंबे वामपंथी शासन की देन हैं.

बेगूसराय और उसके आस-पास के इलाके में कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह ने वामपंथ की नींव रखी थी. बिहार केपहले मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह की कैबिनेट के मंत्री रामचरित्र सिंह के बेटे चंद्रशेखर सिंह ने अपने पिता से बगावत कर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया था. एक दौर था जब बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ था, इसी वजह से बेगूसराय को मिनी मॉस्को कहा जाता था. चंद्रशेखर को बिहार का लाल सितारा भी कहा जाता है. दरअसल चंद्रशेखर सिंह जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब वह रुस्तम साटन नाम के वामपंथी और मार्क्सवादी कार्यकर्ता के संपर्क में आए. इसके बाद वह वामपंथी विचारधारा के होकर रह गए. 1940 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. बाद में वह 1967 में बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार में मंत्री भी बने.

बीहट गांव में रहने वाले कन्हैया के परिवार का वामपंथ से तीन पीढ़यों पुराना नाता है. उनके दादा मंगल सिंह बेगूसराय के बरौनी खाद कारखाना में फोरमेन थे. वह वामपंथी विचारधारा को मानते थे और चंद्रशेखर सिंह के बचपन के दोस्त थे. कन्हैया के पिता भी अपने पिता की राह पर चले ौर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने. अभी भी वह पार्टी के कार्ड होल्डर हैं. उनकी राह पर चलते हुए कन्हैया ने भी वामपंथ का दामन थामा और देश के जाने-माने विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए. लेकिन जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के बाद जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ा और देश के सारे विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर किया. एक पखवाड़े में कन्हैया एक अनजान छात्र से देश के युवा छात्र नेता के रूप में पहचाने जाने लगे. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु केरल और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर वह एक राजनेता के रूप में भाषण देते नज़र आएंगे. उनकी इन चुनावों में सक्रिय भूमिका से विपक्षी दलों को फायदा होगा या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन इन चुनाव परिणामों से कन्हैया का राजनीतिक भविष्य जरूर तय होगा. क्या इन चुनावों के बाद राजनीतिक दल कन्हैया को उसी तरह हाथों हाथ लेंगे जिस तरह वे उसे अभी ले रहे हैं या फिर यूज एंड थ्रो नीति का अनुसरण करेंगे.

एक दौर था जब बेगूसराय जिले में विधानसभा की सातों सीट पर वामपंथी दलों के प्रतिनिधि चुने गए थे. इन दलों से निकले निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आगे बढ़े. इन्हीं वामपंथी दलों से लोग कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी दलों में भी गए. बीजेपी में आकर दो वामपंथी नेता विधायक, मंत्री और सांसद भी बने. पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भी वामपंथ की खास धमक दिखती रही है. वामपंथ की थोड़ी-बहुत ताकत अभी भी यहां रैलियों में दिखती है. चुनावों में गणितीय आंकड़ों के मद्देनजर इसकी चर्चा होती है. वामपंथी छात्र संगठनों से निकले कई छात्र नेताओं ने दूसरे राजनीतिक दलों में अपना समायोजन कर लिया है. जो बुजुर्गवार लोग वामपंथ की आवाज की तरह बने हुए हैं, नौजवान उनको परिवार भाव से सुन तो लेते हैं, पर उनकी बताई राह का अनुसरण नहीं करते.

जिस गांव में कन्हैया का घर है. वह गांव यानी बीहट जिले में वामपंथ के सबसे अधिक प्रभाव वाला गांव रहा है. पड़ोसी गांव मधुरापुर के सूर्यनारायण सिंह उर्फ सूरज बाबू को अभी तक कोई भूल नहीं पाया. जमानत के बाद कन्हैया केजेएनयू में भाषण की तारीफ कर रहे लोगों ने बीहट केही कॉमरेड चंदेश्वरी प्रसाद सिंह को यकीनन नहीं सुना होगा. स्थानीय बोली में उनका भाषण वैचारिक विरोधियों को भी सहजता से जोड़ता था. गांव में अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कथित वामपंथियों की भूमिका रहती है. जिस तरह से येचुरी ने उसे पश्चिम बंगाल में सीपीएम का स्टार प्रचारक बता दिया. जेडीयू, आप, कांग्रेस सहित कई दलों ने कन्हैया में दिलचस्पी दिखाई है. सीपीआई की छात्र इकाई से आनेवाले कन्हैया केलिए गंभीरता से सोचने का वक्त है.

जिस गांव में कन्हैया का घर है. वह गांव यानी बीहट जिले में वामपंथ के सबसे अधिक प्रभाव वाला गांव रहा है. पड़ोसी गांव मधुरापुर के सूर्यनारायण सिंह उर्फ सूरज बाबू को क्षेत्र के लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं. जमानत के बाद कन्हैया के जेएनयू में दिए भाषण की तारीफ कर रहे लोगों ने बीहट के रहने वाले कॉमरेड चंदेश्वरी प्रसाद सिंह को यकीनन नहीं सुना होगा. स्थानीय बोली में उनका भाषण वैचारिक विरोधियों को भी सहजता से जोड़ता था. गांव में अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कथित वामपंथियों की भूमिका रहती है. जिस तरह से येचुरी ने कन्हैया को पश्चिम बंगाल में सीपीएम का स्टार प्रचारक बता दिया. उसके बाद जेडीयू, आप, कांग्रेस सहित कई दलों ने कन्हैया में दिलचस्पी दिखाई है. सीपीआई की छात्र इकाई से आन वाले कन्हैया के लिए गंभीरता से सोचने का वक्त है.

चंद्रशेखर सिंह के अलावा इंद्रदीप सिंह इस क्षेत्र के जाने माने वामपंथी नेता रहे हैं. वर्ष 1964 जब भारतीय वामपंथी आंदोलन में फूट पड़ी तब बिहार में ऐसा नहीं हुआ था. महासचिव जगन्नाथ शंकर की अगुवाई में बिहार में सीपीआई इतनी ताकतवर थी कि उनके नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के साथ हुए गठबंधन की वजह से जयप्रकाश नारायण को अपने आंदोलन की शुरूआत करनी पड़ी थी. जेएनयू प्रकरण ने कई संभावनाओं के रास्ते खोल दिए हैं. इन संभावनाओं में से कुछ काल्पनिक हो सकती हैं. लेकिन इस प्रकरण से सीपीआई की आंखो में चमक आ गई है. उन्हें लगता है कि कन्हैया उन्हें सफलता के नए शिखर पर लेकर जाएंगे और वामपंथी विचारधारा को बाहार के साथ-साथ देश में पुनस्थापित करेंगे. जब वर्ष 1964 में पार्टी का विघटन हुआ था. तब सीपीआई छोटी और सीपीआई(एम) बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसने आगे चलकर लगातार तीन दशक तक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में शासन किया और बीच-बीच में केरल मे भी. अपने राजनीतिक ढलान पर पहुंचने के बाद भी सीपीआई(एम) के पास आज भी लोकसभा में 9 सदस्य हैं जबकि सीपीआई के खाते में एक. ऐसे में सीपीआई की राह में सौभाग्य से कन्हैया नाम की संजीवनी आ गिरी है, जो सीपीआई को अभयदान दे सकती है. कहा जा रहा है कि जरूर सीपीआई ने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे. शायद इसी वजह से बुरे दौर में कन्हैया तारणहार के रूप में उनके पाले में आ गया है.■

navinonline2003@gmail.com

HPL Electric & Power Pvt. Ltd.
www.hplindia.com
HPL
POWER OF TECHNOLOGY

C/o : C&FA SURYA UDYOG
Ist Floor, Bhagat Sadan, Sahi Lane,
S.P. Verma Road, Patna-1
Ph No. : 0612-3260738
Mob. No. : 7541895555
E-mail : surya.udyog.br@gmail.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

बच्चों को जीने दिजिए ....उनका बचपन

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. N.L.CHAUHAN (SASARAM)
M.S. ORTHO

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

सासाराम के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एन.एल. चौहान जो सदर अस्पताल सासाराम में कार्यरत हैं, मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग हड्डी की मजबूती पर चर्चा की। उनकी बातों से यह आभास हुआ कि उनको बच्चों के बचपन खो जाने की भी चिंता है। उन्होंने बताया कि आजकल के बच्चे पूरा समय इन्टरनेट, पढ़ाई और घर में टी.वी. देखने में बिता देते हैं। इस वजह से उनका शारीरिक विकास भी सही से नहीं हो पाता है इन बातों से यह भी स्पष्ट है कि बच्चों का असली बचपन दोस्तों के साथ दौड-धूप वाला कहीं खो गया है। यह भी एक कारण है जिससे बच्चों के पैर कमर आदि में दर्द रह सकता है। बच्चों के पैर-हाथ में दर्द के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि न्यूट्रीशियन की कमी इसका प्रमुख कारण हो सकती है। बच्चों को संतुलित आहार चाहिए, दूध, अंडा, हरी शब्जी फल-फ्रूट आदि मिलना चाहिए। शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा होनी चाहिए। बच्चों के प्रति माता-पिता को सजग रहना चाहिए और यदि बच्चे दर्द की शिकायत करते हैं तो उन्हें कुशल चिकित्सक से चेकअप करवाते रहना चाहिए। अन्य कारणों में बच्चों में गठिया की शिकायत, रियमूटिक फिवर, पेशाब में इन्फेक्शन आदि भी है दर्द के कारण हैं और हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। गले में इन्फेक्शन के कारण को समझ कर दर्द और हड्डियों की कमजोरी का इलाज किया जाता है। डॉक्टर एन.एल. चौहान ने कहा आप बच्चे हों बूढ़े हों या फिर जवान ये जान लें कि इस शरीर को खड़ा रखने के लिए अपनी अस्थियों के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसके लिए संतुलित आहार, डेली वर्कआउट, योगा, मार्निंग वाक, कसरत आदि के साथ साथ सन एनर्जी शरीर को अवश्य दें आजकल विदेशों में धूप स्नान का रीवाज भी है। ▪ भारती

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

उत्तर प्रदेश - नव निर्माण की ओर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के अथक प्रयत्नों से लोक निर्माण विभाग निरन्तर नई ऊँचाईयों को छू रहा है। विभिन्न विकास कार्यों से प्रदेश सँवरने लगा है तथा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश बन सकेगा।

उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कुशल दिशा-निर्देशन में आज प्रदेश प्रगति के पथ की ओर निरन्तर अग्रसर है। हर क्षेत्र में इस प्रकार से विकास कार्य किये जा रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों की सरकारों के लिए अनुकरणीय हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा भी प्रदेश की प्रगति हेतु कई ऐसे कदम उठाये गये हैं, जिनसे प्रदेश की दशा एवं दिशा दोनों में अभूतपूर्व सुखद बदलाव आया है।

मार्गों का चौड़ीकरण/अनजुड़े ग्रामों के लिए पक्के सम्पर्क मार्ग/ग्राम सम्पर्क मार्ग का अनुरक्षण के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने की योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा 30 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। 21 जनपदों में दो लेन मार्ग तथा 9 जनपदों में चार लेन मार्ग बनाये जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 18470 किलोमीटर का कार्य कराया जा चुका है।

डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत लगभग 10 हजार ग्रामों में समस्त क्षतिग्रस्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने का लक्ष्य

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अगले पांच वर्षों में लगभग 10 हजार ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। इन गावों में विशेष रूप से पेयजल, बिजली और सड़क मार्ग जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत सरकार ने 184 करोड़ रू0 आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के महत्वपूर्ण राजमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों का निर्माण, पहले से बने मार्गों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजना के तहत 2014-15 में 643 बसावटों के सापेक्ष 484 बसावटों का संतृप्तीकरण किया जा चुका है। शेष 159 बसावटों का संन्तृप्तीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 917.28 करोड़ रू0 की लागत से निर्मित 100 सेतुओं का निर्माण पूर्ण कराकर उन्हें आवागमन हेतु खोला गया। इसके अतिरिक्त 1159.50 करोड़ रू0 की लागत से 83 सेतुओं के निर्माण का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्ष 2015-16 में 7200 कि0मी0 मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 2882 कि0मी0 लम्बे मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में 5800 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 18470 कि0मी0 का कार्य कराया गया है।

डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत अगले पाँच वर्षों में लगभग 10 हजार ग्रामों में समस्त क्षतिग्रस्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने का लक्ष्य है।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपदों में हाटमिक्स प्लान्ट की स्थापना करके सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इण्डो नेपाल बार्डर के सात जनपदों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।

जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्ग से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पांच जनपद मुख्यालयों को चार लेन मार्ग से तथा 5 जनपद मुख्यालयों को दो लेन विद पेव्ड शोल्डर से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 2250 करोड रू0 से मार्गों का अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

गावों को मार्गों से जोडने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेतुओं के निर्माण के लिए सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग

राजमार्गों के निर्माण में गति लाने के लिए पी.पी.पी. माडल के जरिए निजी विकास कर्ताओं के साथ कई मार्गों के निर्माण का अनुबन्ध

क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 154 सेतुओं का निर्माण करीब 1343 करोड़ रू0 से कराया गया है। 2014-15 में 171 सेतुओं का निर्माण करीब 1568 करोड़ रू0 खर्च करके कराया गया।

राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 2 लाख एक हजार 94 कि0 मी0 है। कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी लंबाई करीब 7550 कि0मी0 है। सरकार प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक गांव और उसकी आबादी को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए युद्धस्तर पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों और जिला मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण सड़क विकास के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2012-13 तक कुल 49,708 कि0मी लम्बे मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 17500 मार्ग बनाये जाने हैं, जिसकी स्वीकृत लागत 13354 करोड़ रू0 है। नवम्बर 2015 तक 16229 मार्ग, जो 45058 कि0मी0 लम्बे हैं, उन पर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसकी सम्पूर्ण लागत 11907 करोड़ है, 886 मार्ग अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन मार्गों के निर्माण से समस्त बसावटें पक्के मार्ग से आच्छादित हो गई हैं।

राजमार्गों के निर्माण में गति लाये जाने के लिए पी0पी0पी0 माडल के जरिए निजी विकास कर्ताओं के साथ कई मार्गों के निर्माण का अनुबंध किया गया है। वर्ष 2014-15 में निजी विकासकर्ताओं के साथ मिलकर करीब 1050 कि0मी0 लम्बे राजमार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर कुल 9000 करोड़ रू0 खर्च किए जायेंगे। इनमें दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग, बरेली- अल्मोड़ा -बागेश्वर मार्ग, वाराणसी-शक्तीनगर मार्ग, मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग, एटा-शिकोहाबाद मार्ग, अलीगढ़-मथुरामार्ग, अकबरपुर-जौनपुर-मिर्जापुर-दुदधी मार्ग, शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग, ताड़ीघाट -बारामार्ग और बलरामपुर-गोंडा-जरवल मार्ग प्रमुख है।

नवीन मार्गों की सतह की गुणवत्ता के आंकलन के लिए 13 प्रयोगशालाएं बनाई गई। ये प्रयोगशालाएं तीन खण्डीय स्तर पर है, जिनमें एक उप निदेशक और दो अधिशाषी अभियन्ताओं को तैनात किया गया हैं। रिसर्च डेवलेपमेंट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल के अधीन मेरठ में एक क्षेत्रीय प्रयोशाला का भी गठन किया गया है। इसके अलावा 9 मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं।

प्रदेश के राज्यमार्गों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु विश्व बैंक से एवं प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एशियन डेवलेपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियाँ

- कुल 2358 किमी लम्बे राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण कराया गया।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3658 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराया गया।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत अब तक 45.51 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण करते हुए 27 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है।
- श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष अब तक 53.53 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए 117 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण किया गया है तथा 182 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से संतृप्त किया गया है।
- 19 जनपद मुख्यालय को एन0एच0ए0आई0 के द्वारा, 2 जनपद मुख्यालय ई0पी0सी0 मोड पर एन0एच0 द्वारा, 10 जनपद मुख्यालय उपशा के द्वारा तथा 14 जनपद मुख्यालय (कुल लम्बाई-487 कि0मी0 व लागत 1950 करोड़ रुपये) लो0नि0वि0 द्वारा जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। 01 जनपद मुख्यालय हमीरपुर (लम्बाई-52 कि0मी0 व लागत 289 करोड़ रुपये) लो0नि0वि0 द्वारा अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा रहा है।
- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने की योजना के तहत लक्षित कुल 15 जनपद मुख्यालयों में से 10 जनपद मुख्यालयों (कुल लम्बाई-383 कि0मी0 व लागत 1840 करोड़ रुपये) का कार्य स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 4 जनपद मुख्यालयों (अमरोहा, श्रावस्ती, सम्भल एवं फर्रूखाबाद) को वर्ष 2014-15 में जोड़ा जाना लक्षित है। इसमें से जनपद अमरोहा को जोड़े जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- 198 कि0मी0 लम्बाई में 4 लेन का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष अब तक 65 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है।
- 1309 कि0मी0 लम्बाई के राज्य मार्गों पर 302 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य के सापेक्ष अब तक 916 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- 1582 कि0मी0 लम्बाई के प्रमुख जिला मार्गों पर 283 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य के सापेक्ष अब तक 1107 किमी लम्बाई में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- 4155 कि0मी0 लम्बाई के अन्य जिला मार्गों पर 531 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य के सापेक्ष अब तक 2910 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- 7000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गों पर 740 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य के सापेक्ष अब तक 4900 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- वर्ष 2014-15 में 24 दीर्घ सेतु, 08 रेलवे उपरिगामी सेतु एवं 11 लघु सेतु इस प्रकार कुल 43 सेतु 606 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किए गए।

ओवरब्रिज तथा सेतुओं के निर्माण से सुगम होता यातायात

लॉरेटो कान्वेंट चौराहे से तेलीबाग (महात्मा गांधी मार्ग) से सुल्तानपुर, वाराणसी, रायबरेली, कानपुर एवं इलाहाबाद की ओर जाने वाले वाहन गुजरते हैं। लखनऊ-दिलकुशा रेल खण्ड से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके कारण सम्पार संख्या-214 (स्पेशल) को बार-बार बन्द करना पड़ता था, परिणामस्वरूप मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। इस सम्पार पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु बन जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल गया है और सुगम यातायात की सुविधा मिलने लगी है।

रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई 655.95 मीटर तथा परियोजना की कुल लागत 4205 लाख रुपये है। मुख्य सेतु की कुल लागत 1000.93 लाख रुपये तथा पहुंच मार्ग की लागत 3204.07 लाख रुपये है। इस सेतु का निर्माण जनू, 2013 में प्रारम्भ हुआ और अक्टूबर, 2014 में इसे पूरा कर लिया गया। रेल उपरिगामी सेतु के मुख्य सेतु, लम्बाई 66.50 मीटर (रेलवे भाग) का निर्माण भी किया गया। रेल लाइन के ऊपर 08 नम्बर स्टील गर्डर (लगभग 200 एम0टी0) की लॉचिंग करते हुए रेलवे भाग का निर्माण कार्य 5 माह की अल्प अवधि में पूरा कराया गया।

इसी प्रकार गोमती नगर स्थित रेल उपरिगामी सेतु के दाहिने भाग में एलीवेटेड रोड बन जाने से भी जनता को सुविधा मिलेगी। इस स्थान पर पूर्व में मार्ग के दांयी ओर

आम जनता के आवागमन को सुगम बनाने तथा शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा विशेष प्रयास

02 लेन मार्ग ही उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में इस स्थान पर मार्ग को और चौड़ा करने की आवश्यकता के अनुरूप कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान की पूरी लम्बाई में बिना कोई निर्माण किए हुए एक एलीवेटेड पहुंच मार्ग बनाया गया है। इस पहुंच मार्ग को पूर्व निर्मित आर0ओ0बी0 से जोड़कर यातायात को सुगम किया गया है। मार्ग की कुल लम्बाई 359.50 मीटर तथा लागत 868.35 लाख रुपये है। सितम्बर, 2013 में कार्य प्रारम्भ हुआ था तथा एक वर्ष में पूरा कर लिया गया। कब्रिस्तान के ऊपर 46.5 मीटर स्पान के 04 स्टील गर्डर लगभग 140 एम0टी0 की लॉचिंग करते हुए निर्माण कार्य कराया गया है।

आम जनता के आवागमन को सुगम बनाने तथा शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए रेल उपरिगामी सेतुओं के त्वरित निर्माण पर खास ध्यान दिया गया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में प्रमुख नदियों पर दीर्घ सेतुओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें 11 सेतु गंगा नदी पर, 12 सेतु यमुना नदी पर, 15 सेतु गोमती नदी पर, 11 सेतु राप्ती नदी पर तथा 14 सेतु अन्य बड़ी नदियों जैसे रामगंगा, चम्बल, घाघरा, केन, धसान, बेतवा तथा क्वारी नदी पर बनाए जा रहे हैं।

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इन्हें 4-लेन में विकसित कराया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भारत सरकार से प्रदेश के महत्वपूर्ण 3 मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करते हुए इन्हें 4-लेन में विकसित कराए जाने जाने का अनुरोध किया है। यह मार्ग हैं-झांसी-खजुराहो, लिपुलेक-भिण्ड और दोहरी घाट- आजमगढ-जौनपुर-इलाहाबाद मार्ग।

इन मार्गों के उच्चीकरण व चौड़ीकरण से अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलेगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

यह तीन मार्ग अभी तक पूरी तरह राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जुड़े हैं, बीच-बीच के हिस्से जो राज्य मार्ग हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 4-लेन चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, पिछड़ेपन को दूर करने, देशी-विदेशी पर्यटकों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं राज्य की सैन्य छावनियों को जोड़ने के दृष्टिगत, इन मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करके इन्हें 4-लेन में विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

बरेली-बागेश्वर स्टेट हाईवे पर 4-लेन सड़क का लोकार्पण

राज्य सरकार ने बरेली-बागेश्वर स्टेट हाइवे-37 पर बरेली से होते हुए हल्द्वानी, अल्मोड़ा के आगे बागेश्वर तक जाने वाले मार्ग को प्राथमिकता देते हुए 540.02 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के आधार पर इसे निर्धारित समय में तैयार कराया है। 4-लेन विद पेव्ड शोल्डर के चौड़ीकरण एवं घनी आबादी वाले क्षेत्र भोजीपुरा में फ्लाई ओवर बन जाने के कारण बरेली से बहेड़ी की दूरी 45 मिनट से 1 घंटे के अन्दर पूरी हो जायेगी। इसके अलावा इस मार्ग पर 09 लघु सेतुओं, 56 पुलियों, 01 टोल प्लाजा तथा 01 ट्रक ले-बाई का निर्माण किया गया है।

उत्तराखण्ड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित नैनीताल, रानीखेत, भीमताल, मुक्तेश्वर आदि पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए जनसामान्य द्वारा इस मार्ग का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान सरकार सड़क एवं सेतु निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। बेहतर आवागमन की सुविधा से आर्थिक विकास तेजी से होता है। जिला मुख्यालयों को चार लेन/दो लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्गों से जोड़ा जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब तक 39 जनपद जुड़ चुके हैं। समाजवादी सरकार सभी जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़कों से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।

समाजवादी आवास योजना से हकीकत में मिलेगा सपनों का बसेरा

समाजवादी आवास योजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने मध्यम आय वर्ग के लोगों के आशियाने का सपना पूरा करने के लिए 'समाजवादी आवास योजना' की शुरूआत की है। इसके तहत वर्ष 2016 तक तीन लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। भविष्य में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है। इस योजना के तहत बनाये जाने वाले मकानों की लागत 15 से 30 लाख रूपये के बीच होगी। इन मकानों के निर्माण के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। योजना के तहत रियायतों की पेशकश भी की जायेगी। इनमें स्टाम्प शुल्क में कमी तथा एकल खिड़की व्यवस्था भी शामिल है। योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण आवास विकास परिषद एवं जिले के विकास प्राधिकरण करायेंगे। इसके लिए शहरों में लम्बे समय से खाली पड़ी जमीनों का प्रयोग किया जायेगा। प्रदेश सरकार का समाजवादी आवास योजना के तहत अधिक से अधिक बेघरों को आवास बनाकर देने का लक्ष्य है।

योजना के मुख्य आकर्षण

शहरों में निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के घर का सपना समाजवादी आवास योजना से पूरा होगा

निम्न-मध्यम तथा मध्यम आय परिवारों हेतु प्रदेश सकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत समाजवादी आवास योजना के संचालन की पहल की

मुख्यमंत्री ने किया 20 हजार आवासों का शिलान्यास तथा विकासकर्ताओं को सौंपे पंजीयन प्रमाण पत्र।

योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त 15 से 22 लाख तक के सस्ते सरकारी मकान बनाने का लक्ष्य

योजना के अन्तर्गत विकासकर्ताओं हेतु 'सिंगल विन्डो सिस्टम' की व्यवस्था

योजना के तहत आवास ऐसे बनाए जाएंगे ताकि भूकम्प में भी कोई नुकसान न हो।

समाजवादी आवास योजना शहरों के नियोजित विकास में भी मदद्गार साबित होगी।

शहरों के विकास के साथ ही लोगों को शहरों में घर की बहुत आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने 'समाजवादी आवास योजना' प्रारम्भ की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 15 से 22 लाख तक के सस्ते सरकारी मकान बनाये जायेंगे। इस योजना में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और आवास विकास के साथ ही निजी डेवलपर्स को भी सस्ते मकान बनाने होंगे। इस योजना पर तेजी से कार्य हो, इसलिए इस योजना के लिए विशेषकर 'सिंगल विन्डो क्लीयरेंस' की भी व्यवस्था होगी। निजी क्षेत्र से निवेश करने वालों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, वाह्य विकास शुल्क, नक्शा पास कराने की फीस और एफ0ए0आर0 में छूट की व्यवस्था की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग की इस योजना से मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के पास अपना एक निजी घर होने का सपना साकार हो सकेगा। इस योजना में शहरों के अलावा गाँवों में भी ऐसे मकान बनाये जायेंगे, ताकि गाँवों में भी विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके।

शहरों में रहने वाले तमाम लोगों के अपने घर का सपना समाजवादी आवास योजना के माध्यम से पूरा होगा। योजना के तहत बनने वाले आवासों की अच्छी गुणवत्ता तथा पहले से ही इनकी कीमत तय होने से आने वाले समय में जनता के बीच समाजवादी आवास की ही सर्वाधिक मांग होगी।

मुख्यमंत्री समाजवादी आवास योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी आवास योजना के तहत बनने वाले 20 हजार आवासों का शिलान्यास किया और योजना में पंजीकृत निजी विकासकर्ताओं को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने विकासकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें 'सिंगल विण्डो सिस्टम' का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। इस मौके पर योजना सम्बन्धी दो पुस्तिकाओं का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।आवासों की उत्तम गुणवत्ता पर बल देते हुये इनका निर्माण इस प्रकार किया गया है, जिससे कि भूकम्प की स्थिति में भी कोई नुकसान न हो। शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। जिस रफ्तार से नगरीकरण हो रहा है, उस अनुपात में लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। इसके मद्देनजर समाजवादी आवास योजना लोगों की आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शहरों के नियोजित विकास में भी मददगार साबित होगी। योजना का नाम 'समाजवादी आवास योजना' इसलिये रखा गया क्योंकि लोगों के लिए यह शब्द सहज और सरल है। साथ ही, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द का उल्लेख है जिसे कोई नहीं हटा सकता।

समाजवादी सरकारों द्वारा हमेशा नगरों के संतुलित विकास पर बल दिया गया। पिछली सरकार के कार्यकाल में हाईटेक टाउनशिप एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना पर कार्य हुआ। लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क विकसित कराया गया, जो यह दर्शाता है कि नगरों का समग्र विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए।

शहरों में रहने वाली जनता को अच्छी आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ ऐसे स्थान भी उपलब्ध कराए जाने जरूरी है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ समय गुजार सकें।

राज्य सकार की विकास गतिविधियों से भी आवास की मांग बढ़ेगी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना से जहाँ रोजगार और कारोबार में इज़ाफ़ा होगा, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए आवास का इंतजाम भी करना होगा। इसी प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़े शहर जहाँ तरक्की करेंगे, वही दूसरी ओर कृषि क्षेत्र और व्यापार जगत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। समाजवादी सरकार गांव, गरीब और किसान की प्रगति के साथ-साथ अवस्थापना विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। ग्रामीण इलाकों में आवासहीनों के लिए 'लोहिया ग्रामीण आवास योजना' संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को मकान के लिए 03 लाख 05 हजार रूपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, सौर उर्जा आधारित रौशनी और पंखे की सुविधा भी मुहैय्या करायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली धनराशि देकर पूरा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधन से लाभार्थियों को एकमुश्त इतनी अधिक राशि प्रदान कर रही है।

जहां एक ओर जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना तथा लोहिया ग्रामीण आवास योजना से गांवो का चौतरफा विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर समाजवादी आवास योजना भी इसी प्रकार जनता में लोकप्रिय साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों, मजदूरों सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए काफी काम किया है। यह योजना मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप तैयार की गई है। एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-17 की अवधि में 24 लाख आवास की मांग अनुमानित है। मध्यम एवं निम्न मध्यम आय वर्गों की जरूरतो को ध्यान में रखकर यह योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत निजी विकासकर्ताओं को सभी स्वीकृतियां आवास बन्धु के माध्यम से प्रदान की जाएगी। समाजवादी आवास योजना को आवास उपलब्ध कराने की एक समेकित योजना साबित होगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवासीय इकाईयों की मांग में निम्न-माध्यम तथा मध्यम आय वर्ग परिवारों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। किन्तु इन वर्गों के लिए अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं थी। वर्तमान सरकार ने ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अफोर्डेबल हाउसिंग नीति घोषित करते हुए उसके तहत 'समाजवादी आवास योजना' के संचालन की पहल की। इस योजना में लाभार्थियों को सभी सुविधाओं से युक्त आवास 15 लाख रूपये से 30 लाख रूपये की लागत के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में साईकिल ट्रैक्स और फुटपाथ के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, हरियाली का भी प्रावधान किया जाएगा।

समाजवादी आवास योजना को आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। यह योजना शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत 60 विकासकर्ताओं का पंजीयन किया गया है।

शहरी निम्न मध्यम तथा मध्यम आय परिवारों के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत समाजवादी आवास योजना का संचालन

अधिक से अधिक बेघरों को घर और सुविधाओं का तोहफा

उत्तर प्रदेश सकार का लक्ष्य है समाजवादी आवास योजना के तहत अधिक से अधिक बेघरों को घर देना। पति-पत्नी यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें एकल इकाई मानते हुए फ्री होल्ड सम्पत्तियों पर लेवी से छूट मिलेगी। लोगों को आवास समय से मिले इसके लिये सरकार ने करार किया है। विलम्बित होने के बाद भी इसी निर्धारित दर पर लोगों को मकान मिलेंगे।

सरकार किसी भी शहर में कोई भी जमीन खाली नहीं छूटने देगी। जमीन मालिकों से उसके ऊपर निर्माण कराने का करार होगा। इसका 55 प्रतिशत लाभ जमीन के मालिक को होगा, 25 प्रतिशत जमीन पर सरकार का हक होगा तथा 20 प्रतिशत डेवलपर का होगा।

इन मकानों के निर्माण के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। योजना के तहत रियायतों में स्टाम्प शुल्क में कमी तथा एकल खिड़की व्यवस्था भी शामिल है। सरकार ने भू-उपभोग में बदलाव के लिये बाईलॉज भी तैयार किया है। इसके तहत एक अलग कोष बनाया जायेगा और उसमें भू-उपयोग परिवर्तन का शुल्क जमा किया जायेगा। लोग यह जान सकेंगे कि उस धन का उपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का सदैव यही प्रयास रहा है कि विकास सभी क्षेत्रों में चहुँमुखी रूप से परिलक्षित होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाजवादी आवास योजना प्रारम्भ की गयी है।

आवासीय योजनाओं में दुर्बल आय वर्ग हेतु घरों का निर्माण अपरिहार्य करने की नीति के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के अधिकतम भवनों/भूखण्डों/ फ्लैट्स के निर्माण अथवा विकास का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य में अच्छी गुणवत्ता व नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर विशेषकर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु 2 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है ताकि हमारी धरा हरी-भरी रहे।

सरकार की नीति सदैव शहरों का सुनियोजित विकास की रही है। इसलिए समस्त निर्माण कार्यों में उत्कृष्ट वातावरण का ध्यान रखा गया है तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप विकास कार्य कराये गये हैं जिनमें ग्रीन बेल्ट/हरित पट्टी आदि का निर्माण, इको पार्क तथा बच्चों के पार्क का विकास जैसे जरूरी कदम उठाये गये हैं।

नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनके द्वारा सरकार की भविष्य के साथ कदम मिलाकर चलने की धारणा प्रबल होती है।

हिंदी साहित्य में मठाधीशी

अनंत विजय

मुंबई के ऐतिहासिक सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रांगण में दो दिनों तक साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत का बेहतरीन समागम हुआ. हिंदी-अंग्रेजी के साहित्यकारों और लेखकों ने दो दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक जेवियर्स के कैंपस में गंभीर विमर्श किया. इस विमर्श में युवा पीढ़ी की भागीदारी आश्वस्तिकारक रही. यह लिटरेचर फेस्टिवल इस लिहाज से अन्य साहित्य समारोहों से अलग रहा, क्योंकि इसमें संगीत पर भी खासा जोर रहा. इसमें कई सत्रों में बेहद दिलचस्प बहसें हुईं. एक सत्र साहित्य की मठाधीशी पर था. मठाधीशी साहित्य पर मेरा मानना है कि साहित्य में इस तरह के गढ़ और मठ गढ़ने की शुरुआत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही शुरु हुई. आजादी पूर्व 1936 में बनाए गए इस प्रगतिशील लेखक संघ का उद्देश्य उस वक्त चाहे जो रहा हो, आजादी के बाद तो यह शुद्ध रूप से साहित्य का एक ऐसा मठ बन गया, जिसमें दीक्षित होकर ही कोई साहित्यकार बन सकता था. संघ की मान्यताओं में रचनाकार का पक्ष पहले से दिया रहता था और रचनाकारों को उस पर चलना होता था. इस उक्ति को समय-समय पर कई लेखकों ने दोहराया है. दरअसल प्रगतिवाद का मतलब हो गया था मार्क्सवादी सिद्धांतों का अंधानुकरण. प्रगतिशीलता के नाम पर साहित्यकारों को प्रगतिशील लेखक संघ से लेखक होने का सर्टिफिकेट मिलने लगा था. उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी प्रतिभा या मेधा का आकलन होने लगा. प्रगतिशील लेखक संघ की प्रतिबद्धता भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी, लिहाजा इस संगठन से जुड़े लेखकों के लेखन से लेकर उनके वक्तव्यों तक में पार्टी की नीतियों की छाप साफ तौर पर दिखाई देती थी. यह मठाधीशी के साहित्य की शुरुआत का दौर था जो अब भी बदस्तूर जारी है. बीच में जब कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ तब साहित्य के इस मठ में भी बंटवारा हो गया. अपना चूल्हा-चौका लेकर अलग हुए लोगों ने जनवादी लेखक संघ बनाया. साहित्य का यह नया मठ जनवादी लेखक संघ अपने हर कदम के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर ताकने लगे. सीपीएम के सीपीआई से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से जनवादी लेखक संघ नाम वाले साहित्यिक मठ में साहित्यिक भक्तों की संख्या बढ़ने लगी. कालांतर में सीपीआई-एमएल बना तो एक बार फिर से साहित्य का यह मठ टूटा और जन संस्कृति मंच का जन्म हुआ. ये तीनों मठ अब भी साहित्य में अपने-अपने भक्तों के साथ डटे हुए हैं. हिंदी साहित्य में इन तीनों मठों का कालखंड बहुत लंबा चला. साहित्य के इन मठों में बैठे महंतों ने अपने भक्तों को जमकर रेवड़ियां बांटी. विचारधारा मानने वालों को विश्वविद्यालयों में नौकरियां मिलीं, फैलोशिप मिले, पुरस्कार मिले, विदेशों में सैर सपाटे के अवसर मिलने लगे. शर्त बस यही थी कि मठ के प्रति आस्था बनी रहे और सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन भी होता रहे. जैसा कि आम तौर पर होता है कि मठों के महंत अपने इर्द-गिर्द चापलूसों को रखते हैं और उनको ही पुरस्कृत करते हैं, वही यहां भी होता रहा. मठ के महंतों की तरह काम करने वाले इन लेखक संघों के मठाधीश भी प्रतिभा को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और प्रतिभाशील लेखकों को दरकिनार कर दिया जाता था. मार्क्सवादी मान्यताओं के अंधानुकरण पर सवाल खड़े करने वाले लेखकों को साहित्य की दुनिया से बाहर कर दिया जाता था. जिस तरह की साजिशें मठों के महंत किया करते थे, कमोबेश उसी तरह की साजिशें इन साहित्यिक मठों के महंत करते थे और विरोधियों को हाशिए पर डाल देते थे. लेखक संघों के मठों के अलावा हिंदी साहित्य में छोटे-छोटे मठ बनाने की कोशिश होती रही. लेखक संघों की मनमानी के खिलाफ 1945 में परिमल नाम की संस्था बनाई गई. इस संस्था से जुड़े लेखकों का मानना था कि जो लेखक हैं वो अपनी राह खुद

बनाएं, नई राह के अन्वेषी बनें, न कि मार्क्सवाद की बनी-बनाई लीक पर चलते रहें. लेकिन प्रगतिशील लेखकों ने परिमल से जुड़े लेखकों पर विचार ही नहीं किया. उनको कलावादी कहकर दरकिनार करते रहे. प्रगतिशीलता के दौर में साहित्य अकादमी और राज्यों की अकादमियां भी इन्ही संघों की शाखा के तौर पर काम करने लगी थीं. उसके बाद अगर साहित्य के मठों को देखें तो लेखकों ने अपने-अपने मठ बना लिए. एक जमाना था जब अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह और राजेन्द्र यादव साहित्य के मठाधीश के तौर पर उभरे और स्थापित हुए. हंस पत्रिका के जरिए राजेन्द्र यादव ने जो साहित्यिक मठ बनाया, उसमें उन्होंने अपनी विरोधी विचारधारा के लोगों को भी स्थान दिया. कई साहित्यिक संस्थाओं को बनाने में अशोक वाजपेयी की भूमिका रही और प्रशासनिक सेवा में होने की वजह से उनको राजाश्रय भी मिला. अशोक वाजपेयी के अनुयायियों की लंबी संख्या है और अच्छी बात यह है कि वाजपेयी अपने शिष्यों या मठ के सदस्यों का खास ख्याल रखते हैं, नौकरी दिलवाने से लेकर पुरस्कार दिलवाने, देने तक में. नामवर सिंह ने अपने दौर में अपने मठ के सदस्यों को विश्वविद्यालयों में फिट किया. अस्सी और नब्बे के दशक में नामवर जी साहित्य के सबसे बड़े मठाधीश थे. एक जमाना था जब इन तीनों को हिंदी साहित्य का ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाने लगा था. राजस्थान की लेखिका रजनी कुलश्रेष्ठ ने कहानी छपने से लेकर किताब छपने तक में साहित्यिक मठाधीशों की भूमिका की ओर संकेत किया. वह संकेत भयावह था. हमारा मानना है कि साहित्य में मठाधीशी का जन्म कम्युनिस्टों ने अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिए किया. इसको उन्होंने लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया. अब भी स्थिति ज्यादा नहीं बदली है और प्रगतिशीलता के तमगे के बिना हिंदी साहित्य में आपको गंधीगता से नहीं लिया जाता है. हालांकि अब दूसरी विचारधारा के लोग या कम्युनिस्टों से वैचारिक मतभेद वाले लेखक भी अपने को असर्ट करने लगे हैं. यह स्थिति साहित्य के लिए अच्छी है जहां हर विचारधारा को विमर्श और लेखन के लिए समान अवसर और मंच मिले. मुंबई में आयोजित लिट ओ फेस्ट में इस तरह के विषयों को केंद्र में रखकर गंभीरता से विमर्श हुआ और प्रभात रंजन, सुंदर ठाकुर और पंकज दुबे जैसे युवा लेखकों ने बेबाकी से अपने विचार रखे. वहां यह बात भी निकल कर आई कि औसत दर्ज के लेखकों को मठों की जरूरत होती है ताकि उनकी कमजोर रचनाओं को आगे बढ़ाया जा सके. लेखकों को अपनी रचनाओं पर यकीन होना चाहिए तभी ये मठ या गढ़ टूटेंगे.

लिट ओ फेस्ट में हिंदी की जोरदार वकालत की गई. आज जब चेतन भगत जैसे लेखक हिंदी को देवनागरी में न लिखकर, बल्कि रोमन लिपि में लिखने की वकालत कर रहे हैं ऐसे माहौल में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने देवनागरी की जमकर वकालत की. एक सत्र में मनोज वाजपेयी ने कहा कि अब वो उन फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते जो देवनागरी में न लिखी गई हो. मनोज वाजपेयी ने स्वीकार किया कि सत्या फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद वो अब इस स्थिति में हैं कि फिल्म जगत में अपनी शर्तों पर काम कर सकें. लिहाजा अब वो देवनागरी में स्क्रिप्ट की मांग कर सकते हैं, कर भी रहे हैं. मनोज जब यह कह रहे थे तो वो उस प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे थे जो बॉलीवुड में आम चलन में है. बॉलीवुड में ज्यादातर स्क्रिप्ट और संवाद रोमन में लिखे जाते हैं और कलाकार भी उसको ही पढ़ते हैं. मनोज वाजपेयी जब देवनागरी की वकालत कर रहे थे तो वो चेतन भगत को नकार रहे थे. मनोज वाजपेयी ने चेतन भगत जैसे रोमन में लिखने के पैरोकारों को लिट ओ फेस्ट के मंच से एक संदेश भी दिया. दरअसल चेतन भगत जैसों को हिंदी और देवनागरी की परंपरा का न तो एहसास है और न ही उसके व्याकरण और उच्चारण का ज्ञान. क्राइम लेखन पर भी एक सत्र रहा जिसमें पुलिस अधिकारी और लेखक ब्रजेश सिंह और अमित खान ने हिस्सा लिया. सबसे अच्छा रहा मराठी धरती पर हिंदी कविताओं की काव्य पाठ. इस काव्य पाठ में स्मिता पारिख, चित्रा देसाई, देवमणि पांडे, रजनी कुलश्रेष्ठ को सुनने के लिए छात्रों की भीड़ को देखकर लगा कि अगर कविताएं कुछ संप्रेषित करती हैं तो उसके श्रोता या पाठक उसकी ओर वापस आ सकते हैं. यह एक बेहद सुखद स्थिति होगी, अगर हिंदी कविता के पाठक, श्रोता उसकी ओर वापस लौट सकें. अगर मीना बाजार में तब्दील हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल ऐसा कर सकें तो साहित्य के लिए यह बड़ा काम होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

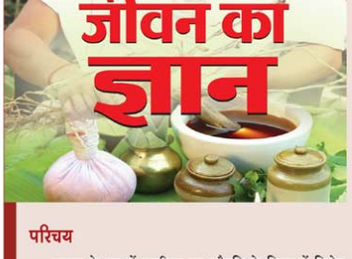

अरहर

परिचय

अनाज के रूप में सुप्रसिद्ध इस औषधि के विषय में विशेष द्रष्टव्य यही है कि अन्य कतिपय औषधियों के समान भारतवर्ष की ही यह एक खास अप्रतिम शक्तिवर्धक वस्तु है. अरहर प्राय: भारतवर्ष में सभी जगह दाल के रूप में उपयोग की जाती है लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं. यह मूलत: दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राप्त होती है. भारत के प्राय: सभी प्रांतों में 1800 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जाती है. यह दो प्रकार की होती है- 1. एक तो वह जो प्रतिवर्ष होती है. जिसका पौधा दो या तीन हाथ ऊंचा होता है और दाल आकार में बड़ी होती है. यह दक्षिण भारत में बहुलता से होती है. 2. दूसरी वह जो तीन या चार वर्षों तक फूलती-फलती रहती है. इसका पौधा 5 से 8 हाथ तक ऊंचा होता है. इसकी दाल आकार में छोटी होती है. जो प्राय: उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारतवर्ष में ही होती है.

बाह्य-स्वरूप

अरहर का 1.5-3 मीटर तक ऊंचा, सीधा, वर्षायु अथवा बहुवर्षायु, रोमश शाखीय पौधा अथवा क्षुप होता है. इसके पत्र संयुक्त तथा आधार पर फूले हुए होते हैं. इसके पुष्प पीत, रक्त अथवा बैंगनी वर्ण सहित पीत वर्ण से युक्त होते हैं. इसकी फली 7-7.5 सेंमी लंबी, 0.6-1.3 सेंमी व्यास की, स्पष्ट मृदु रोमश, बहुधा रक्ताभ बैंगनी वर्ण की धारियों से युक्त, सीधी, दोनों ओर संकुचित होती हैं. इसके बीज 3-5, धूसर-भूरे, रक्त अथवा पांडुर पीत वर्ण के द्विबीज पत्री होते हैं. इसका पुष्पकाल तथा फलकाल अक्टूबर से मार्च तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- अरहर रस में मधुर, कषाय, शीत, लघु, रूक्ष व कफपित्तशामक तथा किंचित् वातकारक होती है.
- अरहर ग्राही, विबन्धकारक, आध्मान-कारक तथा विष्टम्भी होती है.
- अरहर मेद, मुखरोग, गुल्म, ज्वर, अरोचक, कास, हृदयरोग, रक्तदोष, विष, प्रभाव तथा अर्श नाशक है.
- अरहर के पत्र गुरु, त्रिदोशामक, ग्राही तथा कृमिघ्न होते हैं.
- घृतयुक्त अरहर वातशामक होती है. अरहर का लेप कफपित्तशामक होता है. अरहर यूष दीपन, बलकारक पित्तशामक तथा दाहनाशक होता है.
- **श्वेत अरहर-** दोषों का प्रकोप करने वाली, ग्राही, गुरु, पथ्य, अम्लपित्तकारक, आध्मानकार, वातपित्त कारक तथा मलरोधक होती है.
- **रक्त अरहर-** रुचिकारक, बलकारक, पथ्य, पित्तशामक तथा ग्राही होती है व अम्लपित्त, ताप, ज्वर, संताप तथा अनेक रोगों का शमन करती है.
- **कृष्ण अरहर-** बलकारक, अग्निदीपक, पित्तशामक, दाहनाशक, पथ्य, कृमि तथा त्रिदोषशामक होती है.
- इसका मेथेनॉल सार ऐल्बिनो चूहों में कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेरित यकृत विषाक्तता के प्रति- यकृत्रक्षक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.
- इसका पत्र सार सूक्ष्मजीवाणुरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग:

- **अर्धावभेदक-** 5-10 मिली अरहर पत्र-स्वरस में दूध मिलाकर 1-2 बूंद नाक में डालने से आधासीसी की वेदना का शमन होता है.
- 5 मिली दूर्वा स्वरस में 5 मिली अरहर पत्र-स्वरस मिलाकर 1-2 बूंद नाक में डालने से आधासीसी की वेदना का शमन होता है.

नेत्र रोग :

- अरहर मूल को पानी में घिसकर आंखों में अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है.

मुख रोग:

- अरहर पत्र-स्वरस या इसकी छाल को पानी में भिगाकर, छानकर कुल्ला करने से मुंह के छाले दूर होते हैं.
- अरहर के कोमल पत्तों को चबाने से मुख के छाले दूर होते हैं तथा मसूड़ों की सूजन में लाभ होता है.

कंठ रोग:

- **कंठशोथ-** अरहर पत्र-स्वरस को गर्म कर या इसकी छाल को पानी में भिगोकर कुछ गुनगुना करके गरारा करने से कंठ की सूजन का शमन होता है.

वक्ष रोग:

- **वक्षगत-विकार-** इसकी कलियों तथा हरी फलियों को पीसकर छाती पर लेप करने से छाती से संबंधित रोगों में लाभ होता है.
- **हिचकी-** अरहर की भूसी को हुक्के में रखकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है.

यकृतप्लीहा रोग:

- **कामला-** प्रतिदिन प्रात:काल 1-2 ग्राम अरहर पत्रों को सेंधा नमक के साथ मिलाकर, पीसकर जल के साथ सेवन करने से पीलिया में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

- **वातरक्त-** अरहर, चना, मूंग, मसूर, तथा मोठ के 20-20 मिली यूष में अधिक मात्रा में घी मिलाकर पीने से वातरक्त के रोगियों को लाभ होता है.

त्वचा रोग:

- **व्रण-** सद्य:क्षत पर अरहर पत्र-स्वरस का लेप करने से घाव से होने वाला रक्तस्राव रुक जाता है तथा उबले हुए पत्रों का लेप करने से घाव शीघ्र भर जाता है.

सर्वशरीर रोग:

- अरहर की दाल को पीसकर सूजन वाले स्थान पर लेप करने से लाभ होता है.

विष चिकित्सा:

- **अफीम विषाक्तता-** अरहर के पत्तों का रस पिलाने से अफीम का विष उतरता है.

प्रयोज्यांग: पंचांग, पत्र, पुष्प तथा बीज.
मात्रा: चिकित्सक के परामर्शानुसार. ■

आचार्य बालकृष्ण

कब और कैसे करें प्रथम अपील

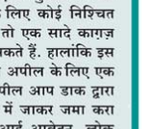

प्रथम अपील के लिए आम तौर पर कोई फीस निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील के लिए भी शुल्क निर्धारित कर रखा है. प्रथम अपील के लिए कोई निश्चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है. आप चाहें तो एक सादे काग़ज़ पर भी लिखकर प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं. हालांकि इस मामले में भी कुछ राज्य सरकारों ने प्रथम अपील के लिए एक ख़ास प्रारूप तैयार कर रखा है. प्रथम अपील आप डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं. प्रथम अपील के साथ आरटीआई आवेदन, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (यदि उपलब्ध कराई गई है तो) एवं आरटीआई आवेदन के साथ दिए गए शुल्क की रसीद आदि की फोटोकॉपी लगाना न भूलें.

प्रथम अपील का प्रारूप

सेवा में,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील.

महोदय,

मैंने सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है.
(आवेदन की प्रति संलग्न है)

सूचना का अधिकार क़ानून 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है.

मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/गलत है/मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है.

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 19(1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दें. इस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें. साथ ही सूचना का अधिकार क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दें.

भवदीय

नाम
पता

संलग्नक :
1. आवेदन की प्रति.
2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना (यदि दी गई है तो) की प्रति.
3. आवेदन शुल्क रसीद की प्रति ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एक-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

साईं वंदना

बंधन से निकल पाना कठिन क्यों

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

शुभ-अशुभ- प्रारब्ध

मनुष्य को यह कैसे पता चलेगा कि वर्तमान जीवन में उसके कौन से कर्म प्रारब्ध का भोग हैं और कौन से कर्म भविष्य में प्रारब्ध का बीज बन रहे हैं?

जीवन में कभी-कभी जो अकस्मात घटनाएं घटित होती हैं, वे बहुत बड़ा प्रारब्ध हैं. उनमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता. जैसे कि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या अकस्मात मौत हो जाती है. जब व्यक्ति के बुरा न चाहते हुए और बुरा कर्म न करते हुए भी बुरा होता है तथा अच्छा न चाहने पर भी अच्छा होता है, यह भी प्रारब्ध है. अच्छे या बुरे कर्म को जानते हुए भी जब लोग इन कर्मों को करते हैं, तो शुभ या अशुभ प्रारब्ध बना लेते हैं. वही हमारे साथ अगले जन्मों तक रहते हैं. यदि इन बातों के प्रति सजग रहकर कोई चलेगा तो भविष्य के प्रारब्ध से बच सकेगा. इसीलिए ऋषि-मुनियों ने, गुरुओं ने और माता-पिता आदि ने सदैव सदाचार की प्रेरणा दी है.

ऋण चुकाने से ही बंधन-मुक्ति

बंधन से निकल पाना कठिन क्यों होता है?

बंधन से निकल पाना उन्हीं लोगों को कठिन लगता है, जो सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाते. जिसका ज्यादा प्रारब्ध होगा. उसके परिवार का बंधन भी ज्यादा होगा. ऋण चुकाने पर ही उसका बंधन कटेगा. इसके लिए संबंधों की सत्यता समझते हुए इच्छा-रहित होकर धीरज के साथ कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए. अतः सद्गुरु को मन में धारण किए हुए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए. ■

साईं भक्तों!
आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

एशिया कप-2016

भारतीय टीम बनी एशिया की सिरमौर

भारतीय टीम इस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है. इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-0 से हराकर उसका सूपड़ा साफ कर दिया था. उसके बाद श्रीलंका को 2-1 से हराया और अब एशिया कप में बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारत ने 2016 में टी-20 प्रारूप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 11 मैचों में 10वीं जीत दर्ज की. भारतीय टीम की अच्छी फॉर्म को देखते हुए उसकी काफी प्रशंसा हो रही है.

तरुण फोर

भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर, एशिया कप पर छठी बार कब्जा किया. भारत की इस जीत में शिखर धवन और विराट कोहली की बैटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा. धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार यह खिताब जीता है. मैच शुरू होने से पहले तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई जिसके कारण मैच दो घंटे की देरी से शुरू हुआ. बारिश के कारण मैच को 15 ओवर का कर दिया गया था. भारत ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया. बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश ने निर्धारित 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य दिया. भारत ने 13.5 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम को पहला झटका पांच रन के स्कोर पर दूसरे ओवर में लगा, जब अल-अमीन हुसैन की गेंद पर रोहित शर्मा केवल एक रन बनाकर स्लिप में आउट हो गए. विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 41 रन बनाए. धोनी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और महज 6 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे. फॉर्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 43 गेंदों में सर्वाधिक 60 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद और अल-अमीन ने एक-एक विकेट झटके. सौम्य सरकार को मैच में शानदार कैच पकड़ने का पुरस्कार दिया गया. कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया. कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अल अमीन हुसैन को मिला. प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार शिखर धवन को मिला. प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार शब्बीर रहमान को दिया गया.

कोहली ने क्या कहा

- कोहली ने कहा कि यह अहम है कि हर कोई आत्मविश्वास से भरा है और सबकी फॉर्म अच्छी है.
- पिछले कुछ मैचों में हमने देखा कि युवराज सिंह बहुत अच्छी पारियां खेल रहे हैं. सुरेश रैना टी-20 के खतरनाक खिलाड़ी हैं.
- रोहित शर्मा शानदार हैं और धोनी भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से जानते हैं. हार्दिक पांड्या गेंद को अच्छी तरह से स्ट्राइक करते हैं. मैं भी गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहा हूं.

बांग्लादेश ने किया कमाल

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर में 3-0 से हराया था, उसके बाद भारत को 2-1 से मात दी थी. घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रही बांग्लादेश की टीम से सभी को काफी उम्मीदें थीं.

बांग्लादेश काफी मजबूत टीम के रूप में उभर कर सामने आई है. लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान से अपना लोहा मनवा चुकी बांग्लादेश ने फाइनल में भारत के सामने घुटने टेक दिए. बांग्लादेश का प्रदर्शन दिन पर दिन बेहतरीन होता जा रहा है. अब बांग्लादेश की टीम को हराना आसान नहीं है, क्योंकि वह आखिरी समय तक संघर्ष करती है. उसने एशिया कप में भारत के साथ फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था. एशिया कप बांग्लादेश को अपने हाथ से गंवाना पड़ा. यह दूसरा मौका था, जब बांग्लादेश की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी. इससे पहले 2012 में बांग्लादेश की टीम एशिया कप के काफी निकट पहुंचकर 2 रन से पाकिस्तान से फाइनल में हार गई.■

भारतीय टीम इस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है. इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-0 से हराकर उसका सूपड़ा साफ कर दिया था. उसके बाद श्रीलंका को 2-1 से हराया और अब एशिया कप में बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारत ने 2016 में टी-20 प्रारूप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 11 मैचों में 10वीं जीत दर्ज की. भारतीय टीम की अच्छी फॉर्म को देखते हुए उसकी काफी सराहना हो रही है और उसे विश्वकप के लिए सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है.

भारत की रिकॉर्ड जीत

एशिया कप के अभी तक के इतिहास में भारत और श्रीलंका 5-5 बार चैंपियन रह चुके थे. भारतीय टीम 2016 का एशिया कप का खिताब जीतकर इस सीरीज में नंबर वन पर पहुंच गई है. इससे पहले भारतीय टीम 1984 (पहला एशिया कप) 1988, 1990, 1991, 1995, 2010 में चैंपियन रह चुकी है. वह 3 बार 1997, 2004 और 2008 में उप विजेता रही है. वहीं श्रीलंका 1986 में पहली बार खिताब जीतने के बाद से 1997, 2004, 2008 और 2014 में चैंपियन रही. पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में यह टूर्नामेंट जीता था. भारतीय टीम जब भी एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, तो उसका मुकाबला हमेशा श्रीलंका से ही हुआ है. यह पहली बार है जब कोई दूसरी टीम भारत के सामने थी. भारत की एशिया कप में यह छठवीं खिताबी जीत है.■

feedback@chauthiduniya.com

आईसीसी टी-20 विश्वकप क्रिकेट

किसके सिर पर सजेगा टी-20 का ताज

भारत में पहली बार टी-20 विश्व कप आयोजित हो रहा है. 2007 से शुरू हुए विश्व कप का यह छठा संस्करण है जो तीन अप्रैल 2016 तक जारी रहेगा. सभी मुकाबले भारत के स्टेडियम (बेंगलुरु, चेन्नई, मोहाली, मुंबई, नागपुर, दिल्ली और कोलकाता) में खेले जाएंगे.

क्या है टूर्नामेंट का फॉर्मेट

टूर्नामेंट दो राउंड में खेलें जाएंगे. पहले राउंड में आईसीसी की आठ एसोसिएटेड टीमें होंगी. इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदरलैंड और ओमान है. जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, हांगकांग, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीम है. इन दोनों ग्रुप से दो टीमें दूसरे राउंड में पहुंचेंगी जिसे सुपर 10 का नाम दिया गया है. इस राउंड में भी दो ग्रुप बनाए गए हैं. ग्रुप 1 में वर्तमान टी-20 विश्व चैंपियन श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड के साथ एक क्वालीफायर टीम रखी गई है. ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी एक क्वालीफायर टीम को रखा गया है. टूर्नामेंट का फाइनल तीन अप्रैल को ईडन गार्डन में खेला जाएगा. भारत इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण 2007 का विजेता है. जबकि दो साल पहले बांग्लादेश में खेले गए टूर्नामेंट में भारत उप-विजेता रहा. खिलाड़ियों की आईसीसी टी-20 रैंकिंग के बारे में बात करें तो विराट कोहली दूसरे नंबर हैं, रोहित शर्मा 11वें नंबर, सुरेश रैना 16 वें, युवराज सिंह 22वें, कप्तान एमएस धोनी 43वें और शिखर धवन 48वें नंबर पर हैं. गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के बॉलर सुनील नरेन की गैरमौजूदगी में भारत के आर अश्विन टॉप बॉलर के तौर पर इस विश्व कप में खेलेंगे. नरेन के बाद अश्विन दूसरे नंबर पर हैं. आर जडेजा 11वें और जसप्रीत बुमराह 27वें स्थान पर हैं. ऑल-राउंडरों में भारत के युवराज सिंह नंबर 6 पर टॉप ऑल-राउंडर हैं.

यह पहला मौका है जब टी-20 विश्वकप टूर्नामेंट भारत में खेला जा रहा है. भारत इस समय टी-20 विश्वकप जीतने का सबसे मजबूत दावेदार है. भारत न केवल रैंकिंग में नंबर है, सबकी पसंदीदा टीमों में से एक है. क्रिकेट के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. टीम इंडिया के ग्रुप को काफी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी हैं. यह भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी.

भारत के पूर्व आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि भारत में शुरू हो रही टी-20 विश्वकप चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज पहुंचेंगे. सहवाग पहले ही भारत को इस प्रतियोगिता को जीतने का प्रबल दावेदार बता चुके हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

टीम इंडिया की खास बातें

1. रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह और सुरेश रैना जबरदस्त फॉर्म में हैं. किसी भी टीम के बॉलर्स की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखते हैं.
2. कप्तान एमएस धोनी एशिया कप में जीत दिलाने के बाद एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आए. वह टी-20 और वनडे में वर्ल्ड के बेस्ट कप्तान हैं.
3. आर. अश्विन और रवींद्र जडेजा की फॉर्म भारत के लिए सबसे सकारात्मक बात है, क्योंकि एशिया कप की मेजबान बांग्लादेश और भारतीय पिचों में ज्यादा फर्क नहीं है. वह दोनों वहां काफी असरदार साबित होंगे.
4. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और पवन नेगी के रूप में टीम इंडिया के पास यंग टैलेंट भी हैं. जो विरोधी टीमों केलिए परेशानी बन सकता है.
5. टी-20 वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन बनना भारतीय टीम केलिए सकारात्मक है. इसका अन्य टीमों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा.
6. भारत ने पिछली दो सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया. ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 3-0 से और श्रीलंका को भारत में 2-1 से हराया. अब भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम इस समय आत्मविश्वास से भरपूर है.
7. विराट की वापसी से टीम को और मजबूती मिलेगी.
8. अनुभवी गेंदबाज नेहरा की वापसी ने टीम की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत किया है.
9. आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर रहे पवन नेगी पर भी सबकी नजरें होंगी.

टी-20 रैंकिंग में टॉप-10 टीमें

1. भारत- 127
2. वेस्टइंडीज़ -118
3. द. अफ्रीका-118
4. न्यूज़ीलैंड- 116
5. इंग्लैंड - 112
6. ऑस्ट्रेलिया-111
7. पाकिस्तान-110
8. श्रीलंका- 109
9. अफ़ग़ानिस्तान- 77
10. बांग्लादेश- 75

सम्मान

मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

"फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रख्यात अभिनेता मनोज कुमार को साल 2015 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा."

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई, 1937 को पाकिस्तान के मौजूदा ख़ैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ. मनोज कुमार का मूल नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है. विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया.

मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्में की जिनमें *पूरब और पश्चिम, शहीद, दो बदन, रोटी कपड़ा और मकान, हिमालय की गोद में, उपकार और क्रांति* जैसी फिल्में शामिल हैं. मनोज कुमार को इन फिल्मों में दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है. 1960 में कांच की गुड़िया के साथ उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में वह देशभक्ति फिल्मों में अभिनय और निर्देशन की तरफ मुड़े. फिल्म *उपकार* के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और साल 1992 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से भी नवाज़ा. एक समय मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए उनके प्रशंसकों ने उन्हें भारत कुमार भी कहना शुरू कर दिया था.

फिल्म जगत में योगदान के लिए प्रख्यात अभिनेता मनोज कुमार को 2015 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. सिनेमा के प्रति अहम योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है. देश में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है. उन्होंने कहा है कि अधिक उम्र होने के बावजूद वह खुद पुरस्कार लेने दिल्ली जाएंगे. 78 वर्षीय मनोज कुमार इस सम्मान को पाने वाले 47वें व्यक्ति होंगे. भारतीय सिनेमा के सबसे सर्वोच्च सम्मान में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और एक शॉल दी जाती है.

मनोज कुमार ने कहा कि इस सम्मान से नवाज़े जाने की घोषणा से वे बेहद खुश हैं. यह अब तक मिले पुरस्कारों में यह अहम और सम्मानित पुरस्कार है. उन्होंने बताया कि मैं शुक्रवार की दोपहर आराम कर रहा था, जब अशोक पंडित व मधुर भंडारकर का फोन आया. मुझे सबसे पहले उन्होंने यह खुशख़बरी दी. मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा.

पढ़ाई के लिए कॉलेज शिक्षण संस्थानों में चल रहे बवाल पर मनोज कुमार ने कहा कि आज के युवा जागरूक हैं. उन्हें देश से प्रेम है. रहा सवाल छात्र राजनीति का तो कॉलेज, विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान पढ़ाई के लिए हैं. वहां छात्र पढ़ाई ही करें तो अच्छा है. मैं एक सिपाही हूं. मेरे काम को सम्मान देने के लिए सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है. मैं स्वयं दिल्ली पहुंच यह पुरस्कार ग्रहण करूंगा.

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है. दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई. यह पुरस्कार वर्ष के अंत में राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ प्रदान किया जाता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पिछले पांच वर्षों में मिले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

2010	के. बालाचन्द्रन	निर्देशक
2011	सौमित्र चटर्जी	अभिनेता
2012	प्राण	अभिनेता
2013	गुलज़ार	गीतकार
2014	शशि कपूर	अभिनेता

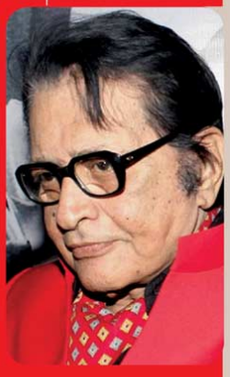

हिंदी फिल्म जगत में मनोज कुमार को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण की प्रतिभा के साथ-साथ निर्देशन, लेखन, संपादन और बेजोड़ अभिनय से भी दर्शकों के दिल में अपनी ख़ास पहचान बनाई है. अभिनेता मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है. जब वह महज दस वर्ष के थे तब उनका पूरा परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आकर बस गया. बचपन के दिनों में उन्होंने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म, शबनम देखी थी. फिल्म में दिलीप कुमार के निभाए किरदार से मनोज कुमार इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने भी फिल्म अभिनेता बनने का फैसला कर लिया. इसके बाद अभिनेता बनने का सपना लेकर वह मुंबई आ गए. बतौर अभिनेता मनोज कुमार ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म फैशन से की. कमजोर पटकथा और निर्देशन के कारण फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह से नकार दी गई.

ऐश्वर्या को पहचानना मुश्किल

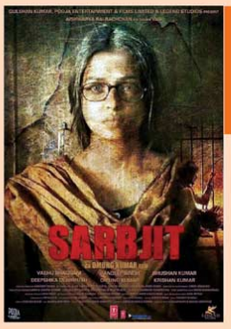

शूटिंग के दौरान मौजूदा भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उन्हें देख कर कहा, ये ऐश्वर्या बुढ़िया के गेटअप में क्यों है? भीड़ में मौजूद उस व्यक्ति की बात ऐश के लिए किसी कॉम्प्लिमेंट से कम नहीं थी. वे सरबजीत की बहन दलबीर कौर के किरदार में कुछ इस तरह डूब गई हैं कि लोग उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे हैं.

इन दिनों सरबजीत की शूटिंग में व्यस्त ऐश्वर्या राय बच्चन अपने किरदार में इतनी फिट हो गई हैं कि लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. एश्वर्या इस फिल्म में सरबजीत की बहन का किरदार निभा रही हैं. इंडिया गेट और रेड फोर्ट पर शूटिंग कर रहीं ऐश के इस अवतार को देख मौजूदा भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उन्हें देख कर कहा कि ऐश्वर्या बुढ़िया के गेटअप में क्यों हैं? भीड़ में मौजूद उस व्यक्ति की बात ऐश के लिए किसी कॉम्प्लिमेंट से कम नहीं थी. वे सरबजीत की बहन दलबीर कौर के किरदार में कुछ इस तरह डूब गई हैं कि लोग उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे हैं. हाल ही में ऐश्वर्या ने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है. इससे पहले वे बाघा बॉर्डर, गोल्डन टेंपल, अटारी बॉर्डर पर शूटिंग करती हुईं कैमरे में कैद हुई थीं.■

सिने झरोखा

कंगना पर भारी पड़ रही हैं सोनम

फिल्म नीरजा में सोनम का अभिनय उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है. हो सकता है कि अगले अवॉर्ड सीज़न में सोनम का जादू चल जाए, क्योंकि फिल्म की सफलता के साथ-साथ सोनम कपूर के अभिनय की ख़ूब तारीफ हो रही है.

सोनम कपूर द्वारा निभाया गया नीरजा का किरदार अब कंगना की क्वीन के किरदार पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है. दरअसल एक टिकट बुकिंग के लिए मशहूर पोर्टल ने अपनी साइट पर वोटिंग कराई और लोगों से पूछा कि उन्हें फिल्म क्वीन में कंगना का किरदार ज़्यादा अच्छा लगा या फिल्म नीरजा में सोनम कपूर का? साईट का दावा है कि इस पोल में सोनम ने कंगना को हरा दिया. सोनम के पक्ष में 52 प्रतिशत दर्शकों ने वोट किया, वहीं 48 प्रतिशत दर्शकों को कंगना का अभिनय ज़्यादा पसंद आया. क्वीन में कंगना के अभिनय को खूब वाहवाही मिली थी और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है. लेकिन अब नीरजा के बाद सोनम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. फिल्म नीरजा में सोनम का अभिनय उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है. हो सकता है कि अगले अवॉर्ड सीज़न में सोनम का जादू चल जाए, क्योंकि फिल्म की सफलता के साथ-साथ सोनम कपूर के अभिनय की ख़ूब तारीफ हो रही है.■

फिल्म रुस्तम का पोस्टर हिट

अक्षय कुमार की आगामी फिल्म रुस्तम के पोस्टर रिलीज़ कर दिए गए हैं. कोई शक नहीं कि ये पोस्टर बेहतरीन हैं और फिल्म के प्रति आपकी उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देंगे. नेवी अफसर के लुक में अक्षय कुमार जबरदस्त लग रहे हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ इलियाना डिक्रूज और ईशा गुप्ता नजर आएंगी. इलियाना फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रोमांस करती दिखेंगी, जबकि ईशा गुप्ता एक निगेटिव किरदार नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में सचिन खेडेकर, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, परमीत सेठी और बिजेंद्र काला जैसे कलाकार दिखाई देंगे. फिल्म रुस्तम 1959 के नानावटी केस पर निर्धारित होगी. यह एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अगले साल रिलीज़ होगी बाहुबली-2

साल 2015 को पीछे मुड़ कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म बाहुबली रही. फिल्म के क्लाईमैक्स को ऐसा बनाया गया था कि दर्शक इसके सीक्वल का इंतजार बहुत बेसब्री से करें और ऐसा हुआ भी. पहले बाहुबली-2 साल 2016 में रिलीज़ होने वाली थी. लेकिन फिल्म की रिलीज़ डेट पोस्टपोंड कर दी गई है. खबरों की मानें तो बाहुबली-2 की रिलीज़ डेट फाइनल कर दी गई है और यह फिल्म 14 अप्रैल 2017 को रिलीज़ होने वाली है. यह गुड फ्राइडे का दिन है, लिहाज़ा उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ान आने वाला है. बाहुबली भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. तेलुगु ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. यही कारण है कि इस बार फिल्म को चीन, जर्मनी सहित अन्य देशों में भी रिलीज़ किया जाएगा.■